नई दिल्ली । मंगलवार, 28 जुलाई, 2026
आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083
वर्ष :12, अंक : 203/ मूल्य 3.00 रुपए । पृष्ठ 12

दैनिक
विश्व केसरी
सिर्फ पत्रकारिता...
नई दिल्ली संस्करण
vishwakesari.com
@vishwakesariTV
@vishwakesari
vishwa_kesari_official
आर. एन. आई. संख्या डीईएलएच आईएन/2015/61415

@ खेल सीडब्ल्यूजी 2026 : पहले ही प्रयास में 8.01 मीटर... @ विचार आंदोलन, नेतृत्व और लोकतंत्र : सवालों के बीच सच्चाई... @ व्यापार लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में...

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक संसद में पेश

फास्ट ट्रैक अदालतें और सख्त सजा के प्रावधान

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोक सभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया।

इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों को और मजबूत करना है। इसके तहत त्वरित जांच, विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से त्वरित सुनवाई, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति, अपीलों का समयबद्ध निपटान और अधिक कठोर दंड प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, ताकि लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और संगठित गड़बड़ियों को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। हाल के वर्षों में प्रश्न-पत्र लीक होने और परीक्षा से जुड़ी संगठित गड़बड़ियों की घटनाओं को देखते हुए, मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये प्रस्तावित संशोधन लाए गए हैं। इनका उद्देश्य अधिक जवाबदेही तय करना, ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त रोक लगाना और लोक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखना है। इस विधेयक में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके तहत जेल की सजा को कम से कम तीन वर्ष, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के मौजूदा प्रावधान से बढ़ाकर कम से

> **अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। जेल की सजा को कम से कम तीन वर्ष, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है**

कम पांच वर्ष, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, अधिकतम जुर्माना भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम के तहत अपराधों में शामिल पाए जाने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए, विधेयक में अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने और उन्हें कोई भी लोक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित करने की अवधि को चार वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में सेवा प्रदाताओं के प्रबंधकीय कर्मियों के लिए कड़ी सजा का भी प्रस्ताव है। इसमें कम से कम पांच वर्ष और अधिक से अधिक दस वर्ष तक की जेल की सजा और अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। इस संशोधन विधेयक में परीक्षा से जुड़े संगठित अपराधों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए जेल की कम से कम सजा को पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, करने और अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच का कार्य इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष कार्य बल को सौंप सकता है। त्वरित जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में एक नई धारा 12क अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें दो माह के भीतर जांच पूरी करने, इस अधिनियम के तहत अपराधों की दैनिक सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के तौर पर नामित करने, आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से तीन माह के अंदर सुनवाई पूरी करने और प्रत्येक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस विधेयक में एक नई धारा 12ख अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें यह प्रावधान है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के किसी निर्णय, आदेश या सजा के खिलाफ अपील तीस दिनों की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है।

सोनिया-राहुल को ईडी की याचिका का जवाब देने तीन हफ्ते की मोहलत

नेशनल हेराल्ड मामला

एजेंसी ■ नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य प्रतिवादियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (क्रिमिनल रिविजन पिटीशन) पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

ईडी ने याचिका ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी, जिसमें कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।

जस्टिस मनोज जैन की सिंगल-जज बेंच ने प्रतिवादियों को अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर के लिए तय की।

सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा, ईडी ने कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को इस मामले में आरोपी बनाने का प्रस्ताव दिया है।

ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 16 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत उसकी अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। केंद्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने यह मानकर गलती की है कि पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत किसी निजी शिकायत से उत्पन्न 'अनुसूचित अपराध' पर आधारित नहीं हो सकती।

ईडी के अनुसार, किसी सक्षम अदालत द्वारा निजी शिकायत पर लिया गया संज्ञान पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर से अधिक महत्व रखता है, और आपराधिक कार्यवाही या तो पुलिस जांच के माध्यम से या मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत के जरिए शुरू की जा सकती है।

इससे पहले, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि अगर ट्रायल कोर्ट की व्याख्या को बरकरार रखा जाता है, तो पीएमएलए 'बेकार और अनावश्यक' हो जाएगा।

केंद्र सरकार के कानूनी अधिकारी ने कहा था कि पीएमएलए में मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के पंजीकरण के लिए कोई विशिष्ट तरीका नहीं बताया गया है, और इसके लिए केवल 'अनुसूचित अपराध' से जुड़ी आपराधिक गतिविधि का आरोप होना आवश्यक है। इससे पहले, ईडी की बात सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है और उसने पुनरीक्षण याचिका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था।

जम्मू-कश्मीर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन

एजेंसी ■ जम्मू

पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) और सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कई अग्रिम इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया।

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के सांबा और राजौरी जिलों में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई अग्रिम इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यह कार्रवाई रात में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद की गई। अधिकारियों ने कहा, 'सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नंदपुर और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तरकुंडी-साज में सतर्क सेना के जवानों ने ड्रोन की गतिविधि देखी। दोनों इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई और सेना व बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद से सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि संदिग्ध ड्रोन से कोई नशीला पदार्थ या हथियार तो नहीं गिराया गया है। शाम तक तलाशी अभियान जारी था।'उन्होंने बताया कि अभी तक कोई चीज बरामद नहीं हुई है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है।

केंद्र सरकार वादा निभाए, नहीं तो होगा देशव्यापी आंदोलन

सीजेपी फंड में सांसद कपिल सिब्बल ने दिए एक करोड़

एजेंसी ■ नई दिल्ली

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 25 जुलाई को हुए समझौते के तहत किए गए वादों की लिखित कॉपी उपलब्ध नहीं कराती है तो वह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेगी। सीजेपी ने कहा कि इसी समझौते के तहत नीट पेपर लीक के विरोध में उसका 49 दिनों का आंदोलन समाप्त हुआ था।

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वॉलंटियर्स को परेशान किया जा रहा है और नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि पहले आश्वासन दिया गया था कि सभी मौजूदा एफआईआर वापस ले ली जाएंगी और कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।

सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि अगर मंगलवार तक लिखित वादे साझा नहीं किए गए तो संगठन को अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा नीट पेपर लीक से संबंधित आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों को 'अधिकतम संभव मुआवजा' देने और पार्टी के पांच सूत्री परीक्षा सुधार चार्टर पर विचार करने के कथित वादे को भी दोहराया। इससे पहले दिन में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के अपने आश्वासन का पूरी तरह उल्लंघन किया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और अन्य राज्यों में स्वयंसेवकों को निगरानी और हिरासत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी एफआईआर को तत्काल वापस लेने और नई पुलिस कार्रवाई को रोकने की मांग की। यह घटनाक्रम केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ तीन दौर की बातचीत के बाद सीजेपी द्वारा अपना आंदोलन स्थगित करने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। सीजेपी के अनुसार, समझौते में एफआईआर वापस लेना, प्रदर्शनकारियों को आगे की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा, पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा और परीक्षा सुधारों पर विचार करना शामिल था। सीजेपी सदस्य रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है, उन्होंने दावा किया कि असम में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, कोलकाता में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बिहार में 86 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कपिल सिबल ने प्रभावित प्रदर्शनकारियों के लिए कानूनी सहायता की घोषणा करते हुए एक राष्ट्रव्यापी कानूनी सहायता मंच स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया।

ट्रंप से मिलने रवाना हुए नेतन्याहू

एजेंसी ■ नई दिल्ली

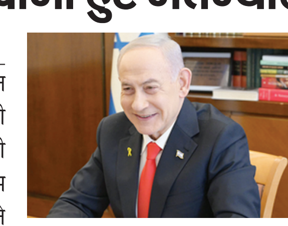

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हुए। वहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम बैठक होगी। निकलने से पहले उन्होंने बताया कि इस बैठक में ईरान समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और उनका मुख्य लक्ष्य इजरायल की सुरक्षा को और मजबूत करना तथा शांति के दायरे का विस्तार करना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ' 'मैं अभी हमारे दोस्त, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए रवाना हो रहा हूं।

भारत के नाम पांचवां मेडल

छत्तीसगढ़ की बेटी वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने प्रदेश का बढ़ाया मान, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता रजत

एजेंसी ■ ग्लासगो

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने पांचवां मेडल हासिल कर लिया है। सोमवार को महिला वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला डिडिह ने गोल्ड पर कब्जा जमाया, जबकि कनाडा की रेबेका ग्रौलक्स ब्रॉन्ज जीतने में सफल रहीं। फिलहाल भारत कुल पांच पदकों के साथ आठवें स्थान पर है।

डिडिह ने स्नैच में 93 किग्रा, जबकि क्लीन एंड जर्क में 113 किग्रा वजन के साथ कुल 206 किग्रा भार उठाया, जो गेम रिकॉर्ड के साथ कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड भी है। वहीं, ज्ञानेश्वरी ने कुल 199 किग्रा वजन (88 स्नैच और 111 क्लीन एंड जर्क) के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे पायदान पर रहने वालीं रेबेका ने कुल 178 किग्रा वजन (स्नैच 83 किग्रा और क्लीन एंड जर्क 95 क्रिगा) उठाया। एसईसी आर्मोडिलो में ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 'स्नैच' वर्ग में 88 किलोग्राम वजन उठाया। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 82 किग्रा, दूसरे प्रयास में 85 किग्रा और तीसरे प्रयास में 88 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस बीच, नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला डिडिह ने स्नैच में 93 किलोग्राम वजन उठाकर नया कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड और गेम्स रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं, कनाडा की रेबेका ग्रौलक्स 83 किग्रा वजन उठाने में सफल रहीं।

इसके बाद 'क्लीन एंड जर्क' में ज्ञानेश्वरी ने अपने तीन प्रयास में 103 किग्रा, 107 किग्रा और 111 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया। डिडिह 105 किग्रा से शुरुआत करने के बाद 110 किग्रा और 113 किग्रा वजन उठाने में सफल रहीं। रेबेका ने पहले प्रयास में 95 किग्रा वजन उठाया, लेकिन 99 किग्रा के अगले दो प्रयास में नाकाम रहीं। यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पांचवां पदक है। इससे पहले पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ देश के लिए मेडल का खाता खोला था। इसके बाद ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की वेटलिफ्टिंग (60 किग्रा) प्रतियोगिता में भारत को सिल्वर जिताया।

मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, : धर्मेन्द्र प्रधान

एजेंसी ■ नई दिल्ली

नीट परीक्षा घोटाले और व्यापक छात्र विरोध के बाद शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में वापसी पर आत्मविश्वास दिखाया। जयराम रमेश की सहानुभूति पर उन्होंने खुद को 'ज़मीनी स्तर पर लड़ने वाला नेता' बताया, जो उनके राजनीतिक भविष्य और बीजेपी में अगली अहम भूमिका की अटकलों को बढ़ा रहा है। यह बयान उनके इस्तीफे के बावजूद उनकी दृढ़ता और पार्टी में उनकी लगातार महत्ता को दर्शाता है।

छात्रों के ज़बरदस्त विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देने के दो दिन बाद, धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को संसद पहुँचे। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। जब प्रधान के साथियों ने उनका स्वागत किया, तो वे मुस्कुराते हुए नज़र आए। बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि शायद यह पहली बार है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने बिना किसी व्यक्तिगत आरोप का सामना किए इस्तीफ़ा दिया है।

इसी स्वागत-समारोह के दौरान जयराम रमेश प्रधान के पास पहुँचे और उनके इस्तीफ़े पर सहानुभूति जताई। कांग्रेस नेता ने उनसे कहा, 'ऐसा होता रहता है।' प्रधान ने तुरंत जवाब दिया, 'कुछ नहीं हुआ,' और साथ ही कहा: 'मैं ज़मीनी स्तर पर लड़ने वाला नेता हूँ,ॅष्ट कमरे में बैठकर काम करने वाला एक्टिविस्ट नहीं।' बीजेपी नेताओं ने इस छोटी सी बातचीत को इस संकेत के तौर पर देखा कि कैबिनेट से हटने के बावजूद प्रधान राजनीतिक रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपनी अगली ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं।

इससे बीजेपी में उनकी अगली भूमिका को लेकर भी अटकलें तेज़ हो गई हैं। ओडिशा में पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक होने के अलावा, प्रधान को बार-बार संगठन और चुनाव से जुड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

उधमपुर जिले में भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग बंद

एनएच-44 पर यात्रा न करने की अपील

विश्व केसरी

श्रीनगर। उधमपुर जिले में भूस्खलन की वजह से सोमवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि बिना जानकारी के राजमार्ग पर न करें। लेटेस्ट अपडेट के के लिए जम्मू और श्रीनगर में यातायात नियंत्रण कक्ष से संपर्क की सलाह दी गई है।

उधमपुर जिले के देवल इलाके में भूस्खलन के बाद राजमार्ग बाधित हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि बाधित राजमार्ग को यातायात के लिए चालू करने के लिए अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यातायात को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए प्रभावित स्थल पर सड़क निकासी टीमों और मशीनरी की तैनाती की गई है।

अस्थिर मौसम और इलाके की स्थिति के कारण यह क्षेत्र ताजा भूस्खलन और पत्थरों के गिरने की चपेट में है। जिसके देखते हुए अधिकारियों की ओर से यात्रियों को फिलहाल एनएच-44 पर यात्रा न करने की अपील की गई है।

ट्रैफिक पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सड़क संपर्क के संबंध में असत्यापित जानकारी या अफवाहों पर भरोसा न करें। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी यात्रा से पहले आधिकारिक जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नवीनतम राजमार्ग स्थिति की जांच करें या श्रीनगर, रामबन और जम्मू में यातायात नियंत्रण इकाइयों से संपर्क करें।

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग भूमि से घिरी घाटी तक एकमात्र सड़क संपर्क का माध्यम है। इस राजमार्ग का उपयोग श्री अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों की ओर से भी घाटी तक पहुंचने के लिए किया जाता है।

वहीं, डोडा जिले में कई दिनों की भारी बारिश के बाद डोडा के पुराने गाड़ी पुल में दरारें आने की खबर के बाद ट्रैफिक रोक दिया गया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी गई है, और एक एक्सपर्ट टीम डिटेल में स्ट्रक्चरल असेसमेंट कर रही है। लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए अगली सूचना तक ट्रैफिक को गणपत ब्रिज से डायवर्ट कर दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल मेहरा ने कहा, 'अभी हम पुल डोडा ब्रिज पर खड़े हैं। कुछ अंदाजा था कि ब्रिज पर दरारें आ गई हैं। सावधानी के तौर पर और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हमने कल रात ब्रिज को गाड़ियों के आने-जाने के लिए बंद कर दिया।'

सिर्फ पेपर लीक कानून से संकट हल नहीं होगा, राज्यों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर करें चर्चा : दिग्विजय सिंह

विश्व केसरी

नई दिल्ली/भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कहा कि 'सिर्फ परीक्षा का पेपर लीक होने के खिलाफ सख्त कानून बनाने से देश में परीक्षा से जुड़े संकट का समाधान नहीं होगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर व्यापक चर्चा की मांग की।

सिंह का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की घोषणा के एक दिन बाद आया है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणि करेंगे और यह देश की परीक्षा प्रणाली को लीक-प्रूफ और टेक्नोलॉजी-आधारित बनाने के उपाय सुझाएगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार संसद में पेपर लीक रोकने के लिए एक सख्त कानून लाएगी।

इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह के ऑफिस ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'पेपर लीक कानून को सख्त बनाने से समस्या हल नहीं होगी। आपको संसद में 'नई शिक्षा नीति 2020' पर पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए और उससे पहले, देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ शिक्षा नीति पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आपने संसद में 'नई शिक्षा नीति 2020' पर चर्चा की होती, तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती।'

एक और पोस्ट में दिग्विजय सिंह कहा, 'भारत जैसे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है, न कि केंद्रीकरण। शिक्षा को पूरी तरह से भारतीय संविधान की राज्य सूची में रखा जाना चाहिए।'

खास बात यह है कि रविवार को पीएम मोदी ने कहा कि नीलेकणि की अगुवाई वाला एक्सपर्ट पैनल परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगा। प्रस्तावित समिति में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी. कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और सीनियर ब्यूरोक्रेट अमृत लाल मीणा समेत कई लोग शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है और संसद में पेपर लीक रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाएगी। यह ताजा बयानबाजी नीट-यूजी 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर मचे राजनीतिक हंगामे के बीच सामने आई है।

संक्षिप्त खबरें

झारखंड ट्रेजरी घोटाले की सीआईडी जांच पर भाजपा ने उठाए सवाल

विश्व केसरी

रांची। झारखंड प्रदेश भाजपा ने राज्य के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी की प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार झारखंड कोषागार संहिता, 2016 और वित्तीय नियमों के विपरीत अपने चहेते अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईडी इस मामले में निष्पक्ष जांच करने के बजाय सरकार की 'एजेंसी ऑफ चॉइस' बन गई है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान करीब 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी धन का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद जांच में बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है और केवल निचले स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से आशंका जताती रही है कि सरकार अपने पसंदीदा अधिकारियों को बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया, जो उन जिलों में पुलिस अधीक्षक रह चुके थे, जहां कथित घोटाले से संबंधित चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

तीन वर्ष के बच्चे पर हमले के बाद लावारिस कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी अभियान तेज

विश्व केसरी

चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में हाल ही में तीन वर्ष के एन. ऋत्विक पर लावारिस कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था। इस घटना के बाद से वेल्लोर, रानीपेट और तिरुवन्नामलाई जिलों की नगर निकायों की ओर से बड़े पैमाने पर सामुदायिक कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी अभियान तेज कर दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को बेहतर बनाने और लावारिस कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर घटना का फुटेज वायरल हुआ था, जिसके बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थानीय प्रशासन को एनिमल बर्थ कंट्रोल और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए कहा गया। सरकार की ओर से चलाए जाने वाले इस अभियान का लोगों ने स्वागत किया है; उनका कहना है कि लगातार वैक्सीनेशन और नसबंदी से आवारा कुत्तों की आबादी धीरे-धीरे कम होगी और रहने की जगहें बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। यह प्रोग्राम एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट, तमिलनाडु एनिमल वेलफेयर बोर्ड और नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन मिलकर चला रहे हैं। वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई कॉर्पोरेशन समेत बड़ी शहरी लोकल बॉडी पिछले एक महीने से हर शनिवार को वीकली वैक्सीनेशन और नसबंदी कैंप लगा रही हैं।

बोकारो की छह साल से लापता किशोरी मामले में हाईकोर्ट सख्त, सीबीआई एसपी को किया तलब

विश्व केसरी

रांची। बोकारो जिले से छह वर्ष से लापता किशोरी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जांच की धीमी प्रगति पर एक बार फिर गंभीर नाराजगी जताई है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और जांच की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने के बाद सीबीआई के एसपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 2:15 बजे होगी। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीआईडी और सीबीआई की ओर से जांच की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई। अदालत ने अब तक की जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तार से परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह जानना चाहा कि छह वर्ष बीत जाने के बावजूद किशोरी का अब तक पता क्यों नहीं चल सका और जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सीबीआई के एसपी को अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित होकर जांच की प्रगति और आगे की कार्ययोजना से अवगत कराने का निर्देश दिया। यह मामला बोकारो जिले के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र का है, जहां 14 वर्षीय किशोरी 16 अक्टूबर 2020 से लापता है। घटना के बाद दर्ज प्राथमिकी की सुपरविजन रिपोर्ट में इसे अपहरण का मामला माना गया था। घटनास्थल के पास से किशोरी की साइकिल, चप्पल और किताबें बरामद हुई थीं, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने झारखंड हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इससे पहले 2 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। अदालत ने सीबीआई और सीआईडी को आपसी समन्वय के साथ जांच आगे बढ़ाने तथा सीबीआई की तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करने को कहा था। सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया था कि ई-केवाईसी मिलान के दौरान बिहार के गोपालगंज में एक बच्ची का चेहरा लापता किशोरी से करीब 90 प्रतिशत तक मेल खाता मिला था, लेकिन अंगूठे के निशान और अन्य पहचान संबंधी विवरण मेल नहीं खाने के कारण उसकी पुष्टि नहीं हो सकी। हाईकोर्ट पहले भी जांच में हो रही देरी पर चिंता जता चुका है।

राउत ने किया दावा- फडणवीस होंगे अगले केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सीएम फडणवीस ने किया खारिज

विश्व केसरी

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने सोमवार को फिर से दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद संभालने के लिए दिल्ली जाएंगे, जबकि फडणवीस ने इन अटकलों को सख्ती से खारिज कर दिया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाहर के किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। 1991 का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी डॉ. मनमोहन सिंह को सौंपी थी।

राउत ने कहा, 'शिक्षा मंत्रालय नंदन नीलेकणि जैसे किसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देवेंद्र फडणवीस के बारे में सोच रहे हैं, तो वे एक उपयुक्त विकल्प हैं।' राज्यसभा सांसद ने कहा, 'मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि चाहे वे कितना भी इनकार करें, वे ही अगले केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे।' फडणवीस के इस दावे को खारिज करते हुए कि वे महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहेंगे। राउत ने कहा कि यह फैसला आखिरकार मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथ में नहीं है। उन्होंने दावा किया, 'वे कहते हैं कि वे महाराष्ट्र में रहेंगे लेकिन वे कहां रहेंगे, यह उनके हाथ में नहीं है। 2022 में उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना भी उनकी अपनी पसंद नहीं थी। जब उनका पद घटाया गया, तो आदेश सीधे मोदी और शाह की ओर से आए थे। भाजपा में आत्मसम्मान या योग्यता कहां है।

बंगाल में हर प्राकृतिक आपदा के बाद हुआ भ्रष्टाचार, अम्फान राहत घोटाले की हो गहन जांचः रिजु दत्ता

विश्व केसरी

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रिजु दत्ता ने अम्फान से जुड़ी अनियमितताओं की गहन जांच की मांग की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन किया।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 28 रिपोर्ट कहा गया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली टीएमसी सरकार ने अम्फान सुपर-साइक्लोन (2020) के बाद हुए नुकसान का अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था, ताकि केंद्र से ज्यादा राहत राशि मिल सके। इस पर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रिजु दत्ता ने दावा किया है कि जब भी बंगाल में प्राकृतिक आपदा आई है, तब भ्रष्टाचार हुआ है।

रिजु दत्ता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'सिर्फ अंफान ही नहीं, जब-जब प्राकृतिक आपदा आई है तो बंगाल में कुछ न कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। अब नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी इस पर नजर रख रहे हैं। बंगाल का निवासी होने के नाते में मैं चाहता हूं कि सीएजी रिपोर्ट में जिस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है,उसकी सघन जांच हो और कार्रवाई की जाए। इस भ्रष्टाचार से जुड़े नेताओं से लेकर आम आदमी को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाना चाहिए। भ्रष्टाचार का अंकुश लगना चाहिए।' रिजु दत्ता ने कहा, 'जब काक्रोच जनता पार्टी के लोग विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश के युवाओं और छात्रों को संबोधित किया और उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, नई नीतियां और सुधार लागू किए जाएंगे और एक नई हाई-पावर्ड कमेटी भी बनाई गई है। अभी संसद नया बिल भी ला रहे हैं।

मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, 10 साल पहले आया था भारत और बनवा लिए फर्जी दस्तावेज

विश्व केसरी

मुंबई। मुंबई पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 36 वर्षीय एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। उस पर फर्जी तरीके से हासिल किए गए भारतीय पासपोर्ट के जरिए यात्रा करने का आरोप है।

आरोपी की पहचान बाबू बिस्वास उर्फ तपस बिस्वास के रूप में हुई है। आव्रजन अधिकारियों को उसके भारतीय पासपोर्ट पर उस समय शक हुआ, जब उन्होंने पाया कि उसका बोलने का लहजा बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा से काफी मिलता-जुलता था।

पुलिस के अनुसार, बिस्वास वर्ष 2016 में पत्नी और परिवार के साथ पश्चिम बंगाल सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत आया था। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में रहने लगा और करीब सात साल तक कोलकाता में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता रहा।

पुलिस ने बताया कि भारत आने के बाद आरोपी ने आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे भारतीय पहचान दस्तावेज बनवा लिए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसने वर्ष 2019 में कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय से भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि उसने इसी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर विदेश यात्राएं भी कीं। वह वर्ष 2023 में दो बार मालदीव और कम से कम एक बार कोलंबो गया, लेकिन इस दौरान किसी को उस पर शक नहीं हुआ।

परेशान कतई न हों, हर उचित समस्या का निष्पक्षता से कराएंगे समाधानः मुख्यमंत्री योगी

विश्व केसरी

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से आए प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने यहां आए लोगों से कहा कि आप परेशान कतई न हों, सरकार हर उचित समस्या का निष्पक्ष समाधान कराएगी। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों के साथ आए बच्चों से भी बातचीत की, उनकी पढ़ाई और रूचि के बारे में भी जाना, फिर सभी को चॉकलेट भी दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जनता दर्शन' में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं-शिकायतें सुनीं। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि परेशान न हों, सबकी उचित समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आई शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए। मुख्यमंत्री 'जनता दर्शन' में आए फरियादियों के पास पहुंचे और एक-एक कर उनके प्रार्थना पत्र लेते हुए शिकायतों व समस्याओं को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा-परेशान न हों, सबकी उचित समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पास में खड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आई शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए। अलग-अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी का निस्तारण निष्पक्ष और समयबद्ध होना चाहिए।

अपराध व जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर उन्होंने अस्पतालों के एस्टिमेट की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा।

महबूबा मुफ्ती को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए थी : उमर अब्दुल्ला

विश्व केसरी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को जंतर-मंतर पर बल प्रयोग के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, न कि इसके लिए एआई जनरेटेड वीडियो को जिम्मेदार ठहराना चाहिए था।

मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर जम्मू-कश्मीर के बाहर के कुछ वर्गों को खुश करने की कोशिश करने और व्यापक आलोचना के बावजूद अपनी कही बात को न मानने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि मुफ्ती जंतर-मंतर पर जम्मू-कश्मीर के लोगों की बात रखने नहीं गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्ती की बातों से कश्मीर घाटी में बल प्रयोग को सही ठहराया गया और उसका समर्थन भी किया गया। उन्होंने कहा कि भले ही उग्रवाद एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन इससे आम लोगों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'अगर यहां उग्रवाद है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को बिना वजह गिरफ्तार किया जाए या उनके पासपोर्ट रोक दिए जाएं।' मुख्यमंत्री ने मुफ्ती की इस बात के लिए आलोचना की कि वे कश्मीर और नई दिल्ली में अलग-अलग रुख अपनाती हैं। वे यहां एक बात और दिल्ली में दूसरी बात कहने की अपनी आदत भूली नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती के भाषण के वीडियो से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली होती और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली होती, तो उनका राजनीतिक कद कम नहीं होता।

समता एक्सप्रेस से दो संदिग्ध युवकों से 50 लाख कैश और 25 लाख का सोना जब्त

पुलिस की सूचना पर नागपुर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई

विश्व केसरी

रायपुर। रायपुर पुलिस से मिली गुप्त सूचना पर नागपुर मंडल RPF टास्क टीम ने शनिवार को समता एक्सप्रेस 12807 से 2 संदिग्ध आरोपियों को धरदबोचा। आरोपियों के पास से 50 लाख रुपये नगद और 25 लाख रुपये का सोना जब्त किया गया है। यह मामला रायपुर के पंडरी थाने में दर्ज अप.क्र. 212/26, धारा 303(2) BNS से जुड़ा है। भौगोलिकसंदर्भ

कैसे पकड़े गए आरोपी ?

रायपुर के DOM और ASP ने सूचना दी थी कि दो आरोपी चोरी की रकम और सोना लेकर समता एक्सप्रेस से नागपुर की तरफ आ रहे हैं। RPF नागपुर मंडल की टीम ने CCTV फुटेज और फोटो के आधार पर भंडारा स्टेशन से ट्रेन की चेकिंग शुरू की। इस टीम में सउनि दिलीप केनार, प्र.आर योगेश हंबरे, प्र.आर इंशांत दिक्षित शामिल थे। ट्रेन नागपुर स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंची तो कोच स्–3 में तैनात आरक्षक विजय बहादुर सिंह और आरक्षक लोकेश डोरले ने दुर्ग से नागपुर तक सघन चेकिंग की। इसी दौरान दोनों संदिग्धों को चोरी की संपत्ति के साथ हिरासत में लिया गया। बाद में आगे की कार्रवाई के लिए दोनों आरोपियों को RPF पोस्ट इतवारी के हवाले कर दिया गया।

मोवा के अशोका आइकन कालोनी में हुई लाखों की चोरी से जुड़ा है मामला

दरअसल राजधानी के मोवा स्थित अशोका आइकन कालोनी में 70 लाख रुपये की चोरी हुई थी। वारदात में जिस रसोइए को महज 12 दिन पहले घर में काम पर रखा गया था, उसी पर अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करने का आरोप लगा। आरोप है कि परिवार के नया रायपुर जाने का फायदा उठाकर उसने अलमारी तोड़ी और लाखों रुपये की नकदी, सोने-चांदी के जेवर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और पेन ड्राइव लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार अशोका आइकन फेस–1, मोवा निवासी कोयला कारोबारी पंकज अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने महेंद्र कुमार यादव, निवासी कटोरिया, जिला बांका (बिहार) को 14 जुलाई से अपने घर में रसोइए के रूप में रखा था। इससे पहले भी महेंद्र करीब आठ दिन तक उनके यहां काम कर चुका था। घर के कामकाज और परिवार की दिनचर्या की पूरी जानकारी होने के कारण उस पर पूरा भरोसा किया गया था। रविवार 26 जुलाई को दोपहर करीब दो बजे पंकज अग्रवाल अपने परिवार के साथ निजी कार्य से नया रायपुर चले गए। उस समय घर में केवल रसोइया महेंद्र यादव मौजूद था। शाम करीब सात बजे जब पूरा परिवार वापस लौटा तो मुख्य दरवाजा बंद था और घर के अंदर अंधेरा था। संदेह होने पर परिवार पीछे के हिस्से में पहुंचा, जहां पिछला गेट खुला मिला। पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश करने पर बेडरूम का दरवाजा खुला मिला।

अलमारी में रखी थी नकदी रकम

कमरे में रखी अलमारी के दोनों दरवाजे खुले हुए थे। जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखी 51 लाख 50 हजार रुपये की नकदी गायब थी। इसके अलावा लॉकर से पत्नी और बेटी के सोने के कंगन, गले का सेट, कान के आभूषण, दो सोने की 10–10 ग्राम की गिन्नियां, करीब 10 ग्राम का सोने का टुकड़ा, सोने के झुमके, पांच जोड़ी टाप्स, ब्रेसलेट, लगभग 20 चांदी के सिक्के, पेन ड्राइव और कार्यालय के दस्तावेज भी चोरी हो चुके थे। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपये आंकी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

त्वरित कार्रवाई से पकड़े गए अपराधी

इस मामले में पुलिस की तत्काल शुरू की गई जांच और सर्विलांस से वारदात का खुलासा हो गया और आरपीएफ की मदद से चोरी में शामिल आरोपी पकड़े गए।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के नाम पर फर्जी अकाउंट

परिचितों से मांगे पैसे

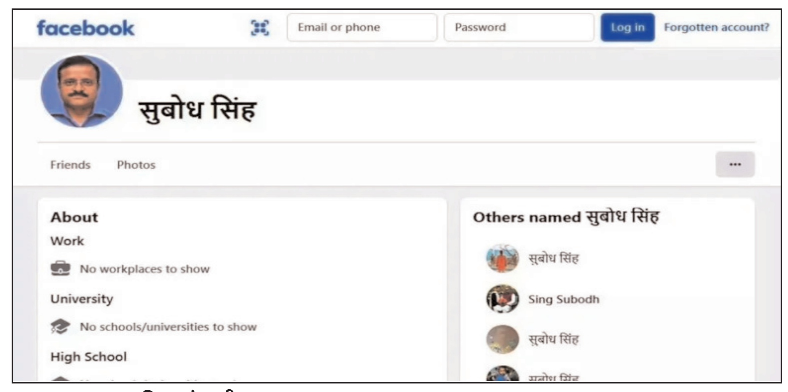

विश्व केसरी

रायपुर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रमुख सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध सिंह को निशाना बनाया है। आरोपी ने उनके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर परिचितों से पैसों की मांग शुरू कर दी।

2 घंटे में बना लिए 58 दोस्त

जानकारी के अनुसार, शातिर ठग ने सोमवार को ही आईएएस सुबोध सिंह के नाम से फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाई। हैरानी की बात यह है कि महज 2 घंटे के भीतर उस प्रोफाइल से 58 लोगों को जोड़ लिया गया। इसके बाद फर्जी प्रोफाइल के जरिए परिचित लोगों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही आईएएस सुबोध सिंह ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी।

पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फर्जी फेसबुक अकाउंट किसने बनाया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। साथ ही पुलिस और साइबर विशेषज्ञ समय–समय पर लोगों से अपील करते रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के नाम से पैसे मांगने वाले संदेश मिलने पर पहले उसकी पुष्टि करें। बिना सत्यापन के किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।

विधायक अनुज शर्मा ट्रोल केस : हाईकोर्ट सख्त, पोस्ट हटाने के आदेश

विश्व केसरी

रायपुर। अनुज शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धरसीवां विधायक और छालीवुड अभिनेता अनुज शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित ट्रोलिंग के मामले में अहम अंतरिम आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए अनुज शर्मा और उनके परिवार से जुड़े मॉर्फ फोटो, एडिटेड वीडियो, अश्लील कमेंट, कैरिकेचर और अन्य आपत्तिजनक पोस्ट तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अकाउंट संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

क्या है पूरा मामला ?

अनुज शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि Facebook, Instagram, X (पूर्व में Twitter) और YouTube पर फर्जी और बेनाम अकाउंट्स के जरिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। याचिका के अनुसार, उनकी तस्वीरों और वीडियो में कथित छेड़छाड़ कर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। साथ ही आपत्तिजनक कैरिकेचर और अश्लील टिप्पणियां भी पोस्ट की गईं। उनका आरोप है कि उनकी फिल्मों और गानों के अंशों को भी एडिट कर भ्रामक तरीके से प्रसारित किया गया, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई।

कोर्ट में क्या दलील दी गई ?

सुनवाई के दौरान अनुज शर्मा की ओर से कहा गया कि किसी व्यक्ति की फोटो, आवाज, पहचान या व्यक्तित्व का उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करना उसके पर्सनैलिटी राइट्स और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले गरिमा और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह केवल राजनीतिक आलोचना का मामला नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए ?

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए अनुज शर्मा और उनके परिवार से जुड़ा कथित आपत्तिजनक कंटेंट तत्काल हटाने के निर्देश दिए जाए। साथ ही संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अकाउंट संचालकों को नोटिस जारी किया जाए। इसके अलावा बिना अनुमति किसी व्यक्ति की पहचान, फोटो या अन्य निजी सामग्री के इस्तेमाल पर भी जवाब प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए हैं।

जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए एक करोड़ का इकरारनामा, फिर भी रजिस्ट्री नहीं

विश्व केसरी

रायपुर। मंदिर हसौद से लगे ग्राम भानसोज में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जहां तहसीलदार और जनपद सदस्य जमीन का सौदा कर बाकायदा एक करोड़ एक लाख रूपए लेकर नियत समय में रजिस्ट्री कराने का एकरारनामा कराकर अब बैनामा रजिस्ट्री कराने के एवज में 30 लाख की एक्सटा डिमांड मांडले परिवार की जा रही है। एसपी से शिकायत में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच की मांग पीड़ित ने की है।

प्रेसवार्ता के दौरान पीड़ित कुलदीप पांडेय ने बताया कि मौजा ग्राम भानसोज हल्का नं. 00008 राजस्व निगम मंडल मंदिर हसौद, जिला रायपुर छग में स्थित है खसरा 1378/1, रकबा 03900 हे.खसरा नंबर 1378/2 रकबा 0.2000 हे. 1354/1 रकबा 0.0716 हे.खसरा नं.1354/4 रकबा 0.1000 हे.भूमि स्थित है। बैनामा इकरारनामा के अनुसार दिनांक 30/07/2025 को अमर आशीष मांडले पिता राजेद्र मांडले (जनपद सदस्य), राज आशीष मांडले पिता राजेन्द्र मांडले तहसीलदार द्वारा लिखित तौर पर एकरारनामा पूरी जमीन की एक करोड़,नब्बे लाख रुपए में किया गया था मेरा द्वारा अग्रिम राशि एक करोड़ 1 लाख दे दिया गया है बाकी राशि जमीन की रजिसिट्री के बाद दोनों क्रेता और विक्रेता के बीच पक्का सौदा हुआ यह सौदा जमीन ब्रोकर गुमेश साहू के मध्य हुआ गवाह बतौर राकेश बागरेचा और शशांक बागरेगा के बीच हुआ। एक माह में जमीन की सीमांकन कर बैनामा पंजीयन करा देंगे। लेकिन आज दिनांक तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है। जब बोलता हूं तो जमीन पर फसल का बहाना बनाकर टाल–मटोल करते–करते आज साल गुजर गया। इस बीच मैंने अपने वकील के माध्यम से रजिस्ट्री को लेकर कानूनी नोटिस भी भेजा गया लेकिन नोटिस का जवाब आज तक नहीं दिया गया है। वहीं जमीन की रजिस्ट्री के लिए संबंधित विषय को विभाग के मंत्री, सचिव और आलाधिकारियों समेत एसपी को भी अवगत करा चुका हूं। कुलदीप पांडेय ने कहा कि जमीन की जब सौदा हो रहा था तो अमर आशीष मांडले को चुनाव लडना था, पैसे के लिए सुबह–शाम गिड़गिड़ता था, आज चुनाव जीत गया तो राजनीति संरक्षण मिल रहा रजिस्ट्री के लिए बात करता हूं तो मुझे धमकाता हैं कि तुम मुझे जानता नहीं मैं मंत्री का आदमी हूं, वहीं उसका बड़ा भाई तहसीलदार को फोन लगाता हूं तो वे भी मुझे अपनी कुर्सी और पावर का धौंस दिखाता है। वहीं मेरी रजिस्ट्री नहीं करने की एवज में मेरे द्वारा दिया गया राशि को वापस मांगने पर एससी एक्ट में फंसाने की बार–बार धमकी देता है। इससे में बहुत ज्यादा परेशान हूं। मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हूं।

आरटीजीएसके माध्यम से राशि का हस्तांतरण

जमीन खरीदी–बिक्री के मामले में जितने भी राशि दी वह आरटीजीएस के माध्मय से अब तक एक करोड़ एक लाख राशि राज आशीष, अमर आशीष त्रिविहार आशीष और अगर बाई द्वारा लिया गया है। इसका पूरी राशि का बैंक ट्रांजेक्शन, आन लाइन ट्रांसफर राशि का दस्तावेज रिकार्ड मौजूद है।

कांकेर में मलेरिया पर स्वास्थ्य विभाग एलर्ट, बच्चों की हो रही है नियमित जांच

विश्व केसरी

रायपुर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है। जिले के सभी विकासखंडों में एक्टिव सर्विलांस (सक्रिय निगरानी) और सोर्स रिडक्शन का काम चल रहा है। साथ ही आश्रम और छात्रावासों में नियमित रूप से जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जांच में जो भी मरीज पॉजिटिव मिले हैं, उन सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है और नियमित फॉलोअप लिया जा रहा है। बीते कुछ हफ्तों में जिले के हजारों बच्चों और ग्रामीणों की मलेरिया जांच की गई। विकासखंड कोयलीबेड़ा में 4 से 25 जुलाई के बीच 12 गांवों में 996 लोगों की जांच हुई, जिनमें से 116 मरीज मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। इनका समूल उपचार कर दवा दी गई है। इसी विकासखंड के 30 छात्रावास और आश्रमों में 1546 छात्र–छात्राओं की जांच में 14 बच्चे पॉजिटिव मिले। विकासखंड भानुप्रतापपुर में 9 से 26 जुलाई के दौरान 16 आश्रम–छात्रावासों के 866 बच्चों की जांच हुई, जिनमें 7 बच्चे पॉजिटिव पाए गए।

करोड़ों भारतीयों को नहीं पता कि वे हेपेटाइटिस से संक्रमित हैं : रामकृष्ण केयर

विश्व केसरी

रायपुर। रोकथाम, जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद वायरल हेपेटाइटिस आज भी दुनिया की सबसे अधिक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की थीम 'हेपेटाइटिस: आइए, इसे समझें और हर बाधा दूर करें' के साथ मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जांच, वैक्सीनेशन, इलाज और देखभाल तक पहुंच में मौजूद बाधाओं को दूर करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ड्ढ्ढ।ह्र के अनुसार, वायरल हेपेटाइटिस से हर वर्ष लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु होती है और यह दुनिया में संक्रमण से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है।

भारत आज भी हेपेटाइटिस से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। डब्ल्यूएचओ और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी अनुमानों के अनुसार, देश में लगभग 2.9 करोड़ लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस–बी तथा करीब 55 लाख लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस–सी संक्रमण के साथ जीवन जी रहे हैं। अधिकांश संक्रमित लोगों को अपनी बीमारी का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हेपेटाइटिस लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के चुपचाप लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर रामकृष्ण केयर अस्पताल के विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में जागरूकता की कमी और देर से बीमारी की पहचान भारत में हेपेटाइटिस से होने वाली लिवर संबंधी गंभीर बीमारियों को रोकने में सबसे बड़ी चुनौती है। भारत सरकार के नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनजागरूकता बढ़ाना, नियमित स्क्रीनिंग को बढ़ावा देना और वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों ने बताया कि देश में लिवर रोगों का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। एक ओर फैटी लिवर डिजीज के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्रॉनिक हेपेटाइटिस–बी और हेपेटाइटिस–सी आज भी सिरोसिस, लिवर फेल्योर और लिवर कैंसर के प्रमुख कारण बने हुए हैं। बड़ी संख्या में मरीज तब अस्पताल पहुंचते हैं जब उन्हें पीलिया, पेट में पानी भरना, पाचन तंत्र से रक्तस्राव, लिवर फेल्योर के कारण मानसिक भ्रम या लिवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं विकसित हो चुकी होती हैं। इस अवस्था में इलाज अधिक जटिल हो जाता है और अच्छे परिणाम मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। डॉ. संदीप पनेडी, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड, रामकृष्ण केयर अस्पताल, ने कहा, 'आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हेपेटाइटिस को 'साइलेंट डिजीज' कहा जाता है, क्योंकि मरीज कई वर्षों तक पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे सकता है, जबकि वायरस धीरे–धीरे उसके लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है।

स्मार्ट मीटर से बिजली खपत नहीं बढ़ती

तीन शहरों के सर्वे में सामने आई सच्चाई

विश्व केसरी

रायपुर। स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों और अफवाहों के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगे घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत का तीन माह का तुलनात्मक अध्ययन कराया है। मई, जून और जुलाई 2026 की खपत के विश्लेषण में यह सामने आया कि अधिकांश उपभोक्ताओं की बिजली खपत जुलाई माह में कम हुई है।

रायपुर शहर क्षेत्र के 3,11,374 घरेलू स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के अध्ययन में 1 जून से 26 जून 2026 के दौरान कुल बिजली खपत लगभग 10.85 करोड़ यूनिट दर्ज की गई थी, जबकि 1 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के दौरान यह घटकर लगभग 7.77 करोड़ यूनिट रह गई। अर्थात कुल 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यदि 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं की बात करें, तो 1 लाख 21 हजार 135 उपभोक्ताओ के बिलों के विश्लेषण से पता चलता है, कि उनकी खपत में लगभग 44 प्रतिशत की कमी हुई है। कारण स्पष्ट है, कि खपत का आधार स्मार्ट मीटर नहीं अपितु उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही वास्तविक खपत है। ऐसे उपभोक्ता जिनके आवासों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे उनकी खपत में भी माह अप्रैल–मई–जून में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज हुई है।

होंडा बिगविंग इंडिया ने होंडा बिगविंग रायपुर को 'रनर-अप - बेस्ट डीलर' सम्मान से नवाजा

विश्व केसरी

रायपुर। प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए होंडा बिगविंग रायपुर ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। होंडा बिगविंग इंडिया ने डीलरशिप को 'रनर–अप – बेस्ट डीलर (सेंट्रल ज़ोन)' सम्मान से सम्मानित किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रीमियम मोटरसाइकिलों की बिक्री, उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव, आफ्टर–सेल्स सेवाओं, डीलरशिप संचालन तथा समग्र प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया।

इस उपलब्धि के साथ ही हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FAD) द्वारा आयोजित Dealer Excellence Awards 2026 में भी होंडा बिगविंग रायपुर को 'बेस्ट लग्ज़री टू–व्हीलर डीलर' श्रेणी में राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया। इन दोनों प्रतिष्ठित सम्मानों ने होंडा बिगविंग रायपुर को देश की अग्रणी प्रीमियम मोटरसाइकिल डीलरशिप्स में शामिल कर दिया है। Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड ॥श्ठ्ठस्त्रड्ड ब्ल्ह्वद्दड्डब्ह्वठ्ठद्द की शुरुआत के लिए त्नय ॥श्ठ्ठस्त्रड्ड का चयन किया था। स्थापना के बाद से ही होंडा बिगविंग रायपुर ने अत्याधुनिक शोरूम, विश्वस्तरीय ग्राहक सेवाओं, प्रीमियम ओनरशिप अनुभव, ग्राहक–केंद्रित पहलों तथा सक्रिय राइडर कम्युनिटी के माध्यम से राज्य में प्रीमियम मोटरसाइकिलिंग संस्कृति को नई दिशा दी है। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, ग्राहक–केंद्रित दृष्टिकोण और निरंतर विकास के दम पर आज होंडा बिगविंग रायपुर छत्तीसगढ़ की नंबर 1 होंडा बिगविंग डीलरशिप के रूप में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर चुका है।

डीलरशिप ने प्रीमियम मोटरसाइकिलों की बिक्री में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए एक्सक्लूसिव राइड्स, राइडर एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, प्रीमियम आफ्टर–सेल्स सेवाओं तथा उत्कृष्ट ओनरशिप अनुभवों के माध्यम से ग्राहकों का विश्वास अर्जित किया है। इन्हीं सतत प्रयासों और उत्कृष्ट प्रदर्शन के परिणामस्वरूप होंडा बिगविंग इंडिया ने डीलरशिप को 'रनर–अप – बेस्ट डीलर (सेंट्रल ज़ोन)' सम्मान से सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर अपने विचार साझा करते हुए GK Group के निदेशक पुनीत परवानी ने कहा, 'होंडा बिगविंग इंडिया और स्न्रष्ठ से प्राप्त ये दोनों प्रतिष्ठित सम्मान हमारी पूरी टीम के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय हैं। यह उपलब्धि हमारे ग्राहकों के विश्वास, हमारी टीम के समर्पण और होंडा के साथ हमारी मजबूत साझेदारी का परिणाम है। हमारा उद्देश्य केवल प्रीमियम मोटरसाइकिलों की बिक्री करना नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्राहक को विश्वस्तरीय खरीद, सेवा और ओनरशिप अनुभव प्रदान करना है।

डोंगरगढ़ भाजपा में बगावत, 111 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा

विश्व केसरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के 111 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा की है।

इस्तीफे की वजह शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह बन्नोआना की कार्यशैली और कार्यकर्ताओं की कथित उपेक्षा को बताया गया है। इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विज्ञप्ति के अनुसार, इस्तीफा देने वालों में मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चा–प्रकोष्ठों के सदस्य, पूर्व पार्षद, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि लंबे समय से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही थी। इससे संगठन के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता गया।

शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया इस्तीफा

सामूहिक इस्तीफे का पत्र भाजपा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को संबोधित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि मंडल अध्यक्ष की कार्यशैली से आहत होकर सभी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं अब तक इस पूरे मामले पर भाजपा जिला संगठन या शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह बन्नोआना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

संपादकीय

आरक्षण के खिलाफ खड़ा करना होगा आंदोलन

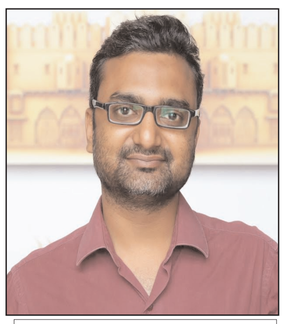

अमित बैजनाथ गर्ग

हर तरह के आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हुए सरकारों को मजबूर करना होगा, ताकि वे आरक्षण समाप्ति के लिए नियम बनाएं। यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए। हमें यह बात समझनी होगी कि किसी जाति को बचाने से ज्यादा जरूरी देश को बचाना है। जातियां रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए।

हाल ही में एक जज ने आरक्षण पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब माता-पिता पढ़े-लिखे हैं और अच्छी नौकरियों में हैं तथा उनकी अच्छी आमदनी भी हो रही है तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि आरक्षण का मकसद पिछड़े लोगों को आगे लाना था, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के सभी सदस्यों को आरक्षण देना। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में लग गया है और उस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है, तो अन्य सदस्यों को आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए? जज की इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर आरक्षण पर बहस छिड़ गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग जोर पकड़ रही है। आरक्षण का विरोध करने वालों का कहना है कि यह पूरी तरह से अप्रासंगिक व्यवस्था हो चुकी है और इसे अब जड़ से खत्म कर दिया जाना चाहिए। हाल ही में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी गई, जो कि पूरी हो गई। इस प्रदर्शन के बाहर कुछ छात्रों ने आरक्षण हटाने की मांग की थी, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। सीजेपी के नेता तो जय भीम के नारे लगा रहे थे, जिससे स्पष्ट था कि ये आरक्षण पर कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके पर स्याही फेंकने वाली एक महिला का कहना था कि छात्रों की सबसे बड़ी समस्या आरक्षण है। इसकी वजह से प्रतिभाओं को नीट पास करने के बाद भी सरकारी कॉलेज मिलने में दिक्कत आती है, इसलिए आरक्षण पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं कुछ छात्रों ने प्रदर्शन के इतर टीवी चैनलों पर डिबेट में आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आरक्षण की वजह से कई छात्रों का भविष्य खराब हो गया है। उन्हें सरकारी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल पाया है। आजाद भारत में आरक्षण की शुरुआत लगभग सन 1950 से मानी जाती है। भारत का संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इसके बाद 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू किया। साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की कुल सीमा अधिकतम 50 प्रतिशत तय की और क्रीमीलेयर की अवधारणा जोड़ी। आरक्षण लागू होने के बाद लगभग हर सरकार इसकी सीमा बढ़ाने का काम करती रही। यह काम वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर किया जा रहा था। सन 1992 तक कोई भी राजनीतिक दल एससी और एसटी के वोटों की फसल काटने से छोड़ना नहीं चाहता था। इसके लिए कोई भी दल देश को दांव पर लगाने से भी नहीं चूका। अभी कुछ समय पहले सेना के एक बड़े रिटायर्ड अफसर ने आरक्षण पर कठोर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी के साथ पूर्व में कुछ शोषण हुआ है, तो क्या उसे अगले 700 या 7000 साल तक आरक्षण दिया जाना चाहिए? क्या वह आरक्षण मिलने पर ही पढ़ेगा और नौकरी लगेगा? क्या नौकरी लगने के बाद भी प्रमोशन में आरक्षण जैसी खराब व्यवस्था को लागू किया जाना सही है? आखिर इस तरह का अन्याय कब तक जारी रहना चाहिए? गौरतलब है कि भारतीय सेनाओं में आरक्षण नहीं है, जिसके कारण भारत की सेनाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यहां कोई भी व्यक्ति पढ़-लिखकर अफसर से लेकर सैनिक बन सकता है। उसे सेना के नियमों को पूरा करना होता है। इनमें किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सेना में आरक्षण इसलिए लागू नहीं किया गया, क्योंकि इससे सेना के कमजोर होने का खतरा था। अब सवाल यह है कि फिर देश में आरक्षण लागू क्यों किया गया? क्या देश के कमजोर होने का खतरा नहीं था? अब बात करते हैं कि आरक्षण से देश को क्या मिला? अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण की वकालत की। उन्होंने शुरुआत में 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान करने और फिर उसकी समीक्षा करने की बात कही। आरक्षण लागू तो हो गया, लेकिन उसकी समीक्षा आज तक नहीं हुई। इसके उलट राजनीतिक दलों की ओर से इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा। देश में राजनीति और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है। आज इन्हीं दोनों क्षेत्रों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आरक्षण की वजह से अधिकतर कमजोर नेता और अधिकतर अयोग्य नौकरशाही देश को चला रही है और पढ़ा-लिखा व्यक्ति मूकदर्शक बने रहने को मजबूर है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। एक वैश्विक स्वास्थ्य संगठन का कहना कि भारत के 56 प्रतिशत से ज्यादा डॉक्टर अयोग्य हैं। न तो इनकी पढ़ाई पूरी है और ना ही प्रैक्टिस। ये 56 प्रतिशत लोग आरक्षण और भारी-भरकम डोनेशन देकर डॉक्टर बनने वाले लोग हैं। खेलों में आरक्षण नहीं है, तो भारत के खिलाड़ियों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण को खत्म कैसे किया जाए? पहली बात तो यह है कि आरक्षण की समीक्षा करने का समय बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, जो कि कभी की ही नहीं गई। दूसरी बात यह है कि अब आरक्षण को लागू करने की कोई भी गली नहीं निकाली जा सकती। अब तो हर तरह के आरक्षण को पूरी तरह खत्म करना ही होगा। सिर्फ इतना किया जा सकता है कि जो भी कमजोर छात्र है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, उसकी पूरी शिक्षा निशुल्क कर दी जाए। इससे ज्यादा कोई रियायत नहीं दी जा सकती।

आंदोलन, नेतृत्व और लोकतंत्र : सवालों के बीच सच्चाई की तलाश

- डॉ. सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, संवाद, असहमति और उत्तरदायित्व से भी संचालित होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन सामाजिक चेतना का माध्यम होते हैं। वे सत्ता को आईना दिखाते हैं, जनता की पीड़ा को स्वर देते हैं और नीतिगत सुधारों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किंतु इतिहास यह भी बताता है कि हर आंदोलन स्वत: पवित्र नहीं होता और न ही हर आंदोलन संदेह से परे होता है। यदि किसी आंदोलन के उद्देश्य, नेतृत्व, वित्तीय स्रोत, संगठनात्मक संरचना और कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न उठते हैं, तो उनका उत्तर भी लोकतांत्रिक पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, किसी आंदोलन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का भी मूल्यांकन प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक धारणाओं के आधार पर।

हाल के वर्षों में भारत में अनेक आंदोलनों ने राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित किया है। किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध आंदोलन तथा युवाओं से जुड़े अनेक अभियान इसका उदाहरण हैं। इन आंदोलनों ने यह स्पष्ट किया कि देश का युवा वर्ग अपने अधिकारों और भविष्य के प्रश्नों पर मुखर है। साथ ही, इन आंदोलनों ने यह प्रश्न भी उठाया कि किसी जनांदोलन की वैधता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके संचालन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से भी तय होती है।

जब कोई नया चेहरा अचानक राष्ट्रीय स्तर पर उभरता है, सोशल मीडिया पर अल्प समय में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त करता है या किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करता दिखाई देता है, तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लोग उसके जीवन, पृष्ठभूमि, वैचारिक यात्रा, आर्थिक स्रोत और संगठनात्मक क्षमता के बारे में जानना चाहते हैं। लोकतंत्र में यह जिज्ञासा अनुचित नहीं है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति से सार्वजनिक जवाबदेही की अपेक्षा भी स्वाभाविक है। किंतु जिज्ञासा और आरोप के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है, जबकि बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाना लोकतांत्रिक विवेक के विपरीत है।

आज सोशल मीडिया ने राजनीति की प्रकृति बदल दी है। पहले लोकप्रियता वर्षों के संघर्ष से मिलती थी, अब कभी-कभी कुछ दिनों में लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँच बन जाती है। एल्गोरिद्म, वायरल सामग्री, मीडिया कवरेज, समर्थकों के अभियान, विज्ञापन और डिजिटल नेटवर्क किसी व्यक्ति की पहुँच को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसलिए केवल अनुयायियों की संख्या देखकर किसी षड्यंत्र का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर यदि किसी डिजिटल अभियान में कृत्रिम प्रचार, बॉट नेटवर्क या अपारदर्शी संसाधनों के संकेत मिलते हैं, तो उनकी स्वतंत्र जाँच भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होनी चाहिए।

लोकतंत्र में आंदोलन की सफलता केवल भीड़ की संख्या से नहीं मापी जाती। कई बार छोटे आंदोलन बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं और कई बार विशाल भीड़ भी स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाती। किंतु किसी आंदोलन में यदि हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव या उकसावे की घटनाएँ सामने आती हैं, तो उनकी निष्पक्ष जाँच आवश्यक हो जाती है। यह भी उतना ही आवश्यक है कि दोषियों की पहचान व्यक्तिगत जिम्मेदारी के आधार पर हो, न कि पूरे आंदोलन या पूरे समाज को एक ही रंग में रंग दिया जाए।

भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है। साथ ही, राज्य पर यह दायित्व भी डालता है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे। इसलिए लोकतंत्र में आंदोलन और प्रशासन दोनों की परीक्षा होती है। यदि आंदोलन हिंसक होता है तो उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ता है। यदि प्रशासन आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करता है तो उसकी वैधता पर प्रश्न उठते हैं। संतुलन ही लोकतंत्र की पहचान है।

राजनीतिक दलों का आंदोलनों में शामिल होना भी भारतीय राजनीति की पुरानी परंपरा है। विपक्ष का काम केवल संसद में बहस करना नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करना भी है। इसी प्रकार सत्ता पक्ष का दायित्व केवल विरोध को राजनीतिक साज़िश बताना नहीं, बल्कि जनता के वास्तविक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करना भी है। लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष और उत्तरदायी सरकार दोनों समान रूप से आवश्यक हैं।

आंदोलनों के वित्तीय स्रोतों पर पारदर्शिता का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक चलने वाले धरने, मंच, प्रचार, परिवहन, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए यह अपेक्षा अस्वाभाविक नहीं कि बड़े आंदोलनों के आयोजक अपने वित्तीय स्रोतों के प्रति पारदर्शी रहें। इसी प्रकार यदि किसी संगठन पर विदेशी फंडिंग या अन्य अवैध आर्थिक सहायता का आरोप लगाया जाता है, तो उसका निर्णय केवल वैधानिक जाँच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होना चाहिए। लोकतंत्र में आरोप और प्रमाण समानार्थी नहीं होते।

भारत का युवा वर्ग आज अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप, भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब, बेरोज़गारी और भविष्य की अनिश्चितता युवाओं में असंतोष पैदा करती है। यदि इन वास्तविक समस्याओं का समाधान समय पर न हो, तो कोई भी आंदोलन व्यापक समर्थन प्राप्त कर सकता है। इसलिए सरकारों के लिए सबसे बड़ा उत्तर आंदोलन को दबाना नहीं, बल्कि उन कारणों का समाधान करना है जो आंदोलन की पृष्ठभूमि बनते हैं।

उधर आंदोलनकारियों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। यदि आंदोलन किसी विशेष मुद्दे पर है, तो उसका फोकस उसी मुद्दे पर रहना चाहिए। यदि विभिन्न असंबंधित राजनीतिक या वैचारिक एजेंडे उसमें शामिल होने लगें, तो आम नागरिकों के मन में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि किसी भी जनांदोलन की विश्वसनीयता उसके अनुशासन, स्पष्ट उद्देश्य और शांतिपूर्ण चरित्र से बनती है।

भारत का लोकतंत्र अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरा है। इस देश ने आपातकाल भी देखा है और शांतिपूर्ण जनांदोलन भी। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने का मार्ग न तो अंध-समर्थन है और न ही अंध-विरोध। लोकतंत्र की शक्ति आलोचनात्मक विवेक में निहित है। नागरिकों को सरकार से भी प्रश्न पूछने चाहिए और आंदोलनकारियों से भी। मीडिया को भी दोनों पक्षों की समान गंभीरता से पड़ताल करनी चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बढ़े। जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का दावा करता है, उसे अपनी पृष्ठभूमि, संगठनात्मक ढाँचे और संसाधनों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने में संकोच नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार सरकारों को भी आलोचना को राष्ट्रविरोध मानने के बजाय लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा समझना चाहिए। प्रश्न पूछना लोकतंत्र की आत्मा है, पर उत्तर साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए।

लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम मतभेदों को संवाद में बदल पाते हैं या नहीं। यदि हर विरोध को षड्यंत्र और हर सरकार को शत्रु मान लिया जाएगा, तो लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर होंगी। वहीं यदि हर प्रश्न को देशद्रोह या हर आलोचना को विदेशी एजेंडा कहकर खारिज कर दिया जाएगा, तब भी लोकतंत्र का नुकसान होगा।

भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि संस्थाओं, संविधान और नागरिक विवेक से चलता है। इसलिए किसी भी आंदोलन, नेता या सरकार के बारे में अंतिम निर्णय तथ्यों, प्रमाणों और निष्पक्ष जाँच पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति न तो भीड़ है और न सत्ता, बल्कि सत्य है। सत्य तक पहुँचने का मार्ग प्रश्नों से होकर अवश्य जाता है, किंतु उन प्रश्नों के उत्तर प्रमाणों से ही मिलते हैं। यही लोकतंत्र की परिपक्वता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी।

(पीएचडी, राजनीति विज्ञान, एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

मूर्तियाँ टूटती हैं, विचार नहीं

गोलेन्द्र पटेल

यह भाषा की रात है
चीज़ें या तो झुक रही हैं
या पीछे हट रही हैं
भाषा और भाषा के बीच की
दरार में
उत्तर और दक्षिण की तरफ़
फन पटकता हुआ
एक दोमुँहा विषधर
रेंग रहा है
रोज़ी के नाम पर
रोटी के नाम पर
जगह-जगह ज़हर
फेंक रहा है।

—धूमिल

महापंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की पीड़ा अभी समाज के मन से उतरी भी नहीं थी कि अब जनकवि धूमिल की प्रतिमा के विखंडन का समाचार सामने आया है । यह केवल एक मूर्ति को तोड़ने की घटना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक स्मृति, लोकतांत्रिक मूल्यों और असहमति के प्रति घटती सहिष्णुता का चिंताजनक संकेत है। अभी पिछले वर्ष 9 नवंबर को जन-उत्साह और साहित्यप्रेमियों की उपस्थिति में धूमिल की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ था और मुझे सार्थवाह सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया था। कुछ ही दिन पहले सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जागरण के उद्देश्य से निकली पदयात्रा में प्रेमचंद, धूमिल, राजनारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे जननायकों को स्मरण करते हुए उनके विचारों को समाज तक पहुँचाने का प्रयास किया गया था। ऐसे समय में इस प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़कर उठा ले जाना न केवल एक अमानवीय कृत्य है, बल्कि हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरी असंवेदनशीलता का परिचायक भी है। धूमिल ने कविता को सत्ता की

प्रशस्ति नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ बनाया। उनकी लेखनी ने अन्याय, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और राजनीतिक पाखंड से निर्भीक संवाद किया। यही कारण है कि उनका महत्व किसी प्रतिमा में नहीं, बल्कि उन प्रश्नों में है जो आज भी समाज के विवेक को झकझोरते हैं। पत्थर पर प्रहार करना आसान है, विचारों का सामना करना नहीं। लोकतंत्र में असहमति का उत्तर हिंसा या विध्वंस नहीं, बल्कि तर्क, संवाद और वैचारिक प्रतिवाद होना चाहिए। काशी, जिसने सदियों से बहुलता और विमर्श की परंपरा को जीवित रखा है, वहाँ इस प्रकार की घटना और भी अधिक पीड़ादायक है। यह केवल धूमिल की प्रतिमा पर नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक परंपरा पर आघात है जो प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने के अधिकार को लोकतंत्र का आधार मानती है। प्रशासन से अपेक्षा है कि दोषियों की निष्पक्ष पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए तथा धूमिल की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित किया जाए। साथ ही साहित्यिक और सांस्कृतिक समाज का भी दायित्व है कि वह वैचारिक हिंसा और सांस्कृतिक विध्वंस के विरुद्ध संगठित होकर अपनी स्पष्ट आवाज़ दर्ज करे। इतिहास गवाह है कि मूर्तियाँ खंडित की जा सकती हैं, स्मारक ढहाए जा सकते हैं, किंतु जनता के अनुभव और सत्य से जन्मे विचार कभी नष्ट नहीं होते। धूमिल की सबसे बड़ी प्रतिमा पत्थर में नहीं, बल्कि हिंदी भाषा, जनचेतना और प्रतिरोध की जीवित परंपरा में स्थापित है। उसे कोई हथौड़ा नहीं तोड़ सकते.

(टिप्पणीकार युवा कवि-लेखक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चिंतक)
डाक पता - ग्राम-खजूरगाँव, पोस्ट-साहुपुरी-221009
मो.8429249326
ईमेल :
corojivi@gmail.com

बोधकथा

सुनने की क्षमता का महत्व

एक साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेमन ही जंगल की ओर बढ़ चला। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की-हल्की सुनाई देने लगीं। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह गुरु के पास वापस लौटा और बोला- पहले तो मुझे वही ध्वनियां सुनाई दीं जो पहले देती थीं, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों के गीत और घांस द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियां सुनाएं देने लगीं। यह सुनकर गुरुजी खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले- अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है। क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है। बिना उनके बोले, उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है। कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है।

संदेश: अगर हमें अपनी फील्ड का लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना, सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया है। यानी हमें उस युवराज की तरह बिलकुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे।

तीर तेवर

सागर कुमार

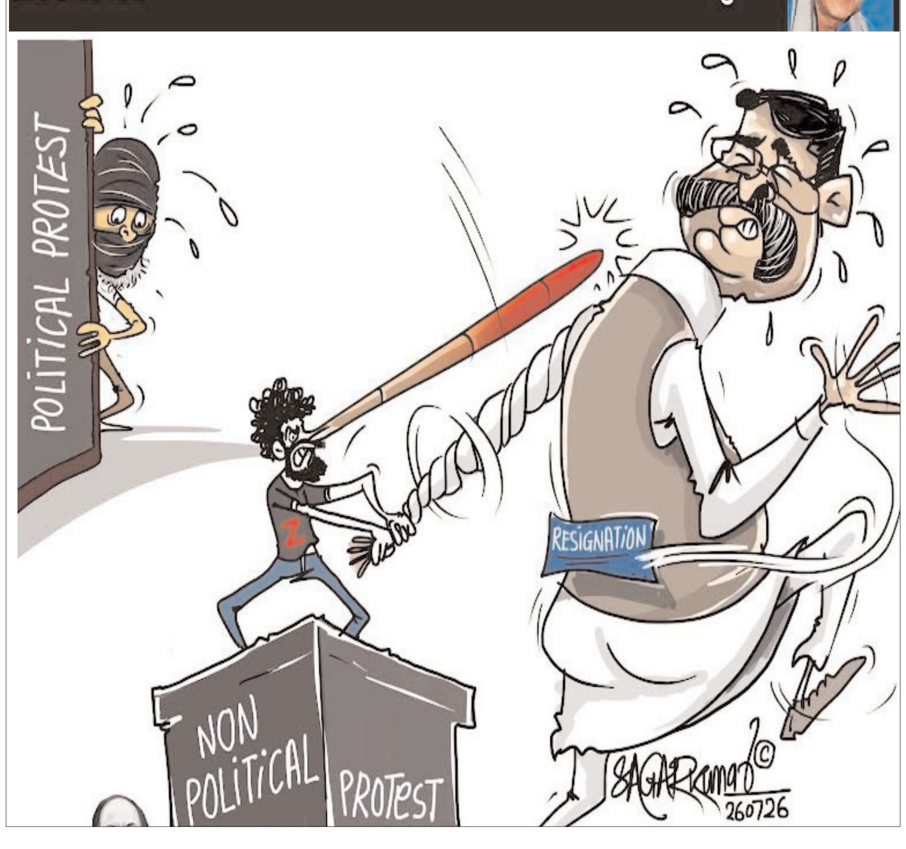

व्यंग्य केसरी

सिंकती रहीं रोटियां..

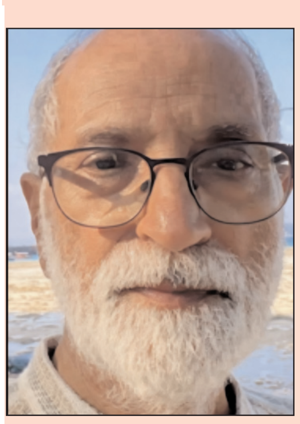

डॉ. रामेश्वरम तिवारी

नीट की परीक्षा का पर्चा क्या ऑउट हुआ था, वह सरकार की नज़र में ये छोटी-मोटी घटना-दुर्घटना थी । जिसका सरकार की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वैसे, होना तो यह चाहिए था कि स्थिति की गंभीरता और नैतिक ज़िम्मेदारी को देखते हुए मानव संसाधन मंत्री प्रधान को खुद आगे बढ़कर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, पर पता नहीं जाने क्या सोचकर हाथ पर हाथ धरे कुर्सी पर चिपके रहे। (बाद में इस्तीफा दें ही दिया.) वैसे देश के प्रधान को चाहिए था कि अपने अधीन प्रधान को समय पर पदच्युत कर देना चाहिए था पर हो सकता है कदाचित् उन्होंने सोचा होगा कि दोबारा परीक्षा आयोजन करने से निर्दोष छात्रों की आत्महत्या का पाप उनके सिर से धुल जाएगा।

दूसरी ओर देश की विपक्षी पार्टी जो पिछले दशक से सत्तारूढ़ सरकार को मात देने के लिए घात लगाकर बैठी थी. दिल्ली का स्वघोषित पूर्व मालिक मौक़े की तलाश में सत्ता को खोकर पगलाए बैठा था। विदेश में बैठे अपने छुटभैया चेले के नाम से कॉकरोचों की एक नई पार्टी खड़ी की और पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामले को छात्रों के भविष्य से जोड़कर देवराज का अमोघ वज्र बनाकर प्रधान के सिर पर दे मारा। साथ ही, अपने समर्थन में लद्दाख के वाँगचुक नाम के एनजीओ चलाकर अपना पेट पालने वाले आंदोलनजीवी को बरसाती मौसम में आग भड़काने के लिए अनशन पर बैठा दिया।

इधर जैसे ही मानसून क़ालीन सत्र शुरू हुआ सरकार पर एक साथ सारे के सारे कॉकरोच, उसका छद्म संरक्षक और विपक्ष का मुखिया पागल श्वान की तरह टूट पड़ा। कॉकरोचों ने संसद पर हमले की योजना बनाई, उधर सरकार की ओर से पुलिस ने मोर्चा सँभाला और देखते ही देखते दोनों ओर से मारामारी का खेल शुरू हो गया। बस! फिर क्या था कैमरे वालों ने दूरदर्शन पर लाईव दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ानी शुरू कर दी। दोनों ओर से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने शुरू हो गए। एलओपी इसी मौक़े की तलाश में बैठा था। उसने कॉकरोचों के आंदोलन को हाईजेक किया और देश के प्रधान के आवास के सामने धरना देने पहुँच गया। तभी पुलिस को भनक लगी। उसने हाथ-पैर पकड़कर उठाया और थाने ले जाकर छोड़ दिया, पर बँदे ने हार नहीं मानी और दूसरे दिन अपने चेले-चपाटों के साथ गाँधी स्मृति धाम पहुँच गया।

दरअसल इन बहुरूपियों में बेचारे रट्टामार छात्रों बनाम कीरों का सच्चा शुभचिंतक कोई नहीं है। कॉकरोच जिसका छद्मवेशी सपोर्टर झाड़ू था, पर पँजा छाप पार्टी का मुखिया आंदोलन की दिशा को मोड़कर संसद की लड़ाई सड़क पर ले आया। दोनों अपने-अपने तरीक़ों से अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने में लगे रहे । और हाँ! प्रधान का इस्तीफ़ा पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या को लेकर नहीं बल्कि इसलिए माँगा जा रहा था कि वह पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिखे गए गलत इतिहास को दुरस्त करने की मुहिम में लगा हुआ था ।

इतिहास

28 जुलाई के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, पेरू की स्वतंत्रता, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस जैसी प्रमुख घटनाएँ शामिल हैं।मुख्य ऐतिहासिक घटनाएँ1914: ऑस्ट्रिया-हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ।1821: पेरू ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।

1976: चीन के तांगशान में 8.3 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें लाखों लोग मारे गए।1979: चरण सिंह भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने।1958: अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पारित हुआ, जिससे नासा की नींव पड़ी। दिवसबारुक ब्लमबर्ग हेपेटाइटिस बी का टीका खोजने वाले वैज्ञानिक का जन्म हुआ। इनकी जयंती पर हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।सर विलियम जेम्स हर्शेल: फिंगरप्रिंट (उंगलियों के निशान) की पहचान का तरीका बताने वाले अधिकारी का जन्म हुआ।

धमतरी के पते वाले सप्लायर को लाखों का भुगतान, पंचायत की पारदर्शिता पर सवाल

रॉयल्टी और सीमेंट खरीदी में मिली खामियां और गड़बड़ी

विश्व केसरी

कवर्धा (जगदंबिका साहू)। ग्राम पंचायत खड़ौदा कला में पंद्रहवें वित्त आयोग (जनपद स्तर) की राशि से कराए गए निर्माण कार्यों में उपयोग की गई निर्माण सामग्री के भुगतान संबंधी दस्तावेज अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गए हैं। पंचायत के अभिलेखों में संलग्न दो बिलों ने न केवल सामग्री खरीदी की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाया है, बल्कि बिल में दर्ज दुकान के पते ने भी पूरे मामले को संदेहास्पद बना दिया है। ग्रामीण अब पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।

दस्तावेजों के अनुसार बिल क्रमांक-28, दिनांक 16 अप्रैल 2026 में बड़े तालाब मंदिर के पास होलिका दहन स्थल पर मिट्टी एवं डस्ट मिक्स मटेरियल डालने का उल्लेख है। इसमें 130 ट्रिप मिट्टी 300 रुपये प्रति ट्रिप की दर से 39 हजार रुपये तथा 2 ट्रिप डस्ट मिक्स 5 हजार रुपये प्रति ट्रिप की दर से 10 हजार रुपये, कुल 49 हजार रुपये का भुगतान दर्शाया गया है।

वहीं बिल क्रमांक-29, दिनांक 15 मई 2026 में भोला पटेल के घर से मुख्य सड़क तक सीसी रोड निर्माण के लिए रेत 5 ट्रिप, गिट्टी 5 ट्रिप तथा 100 बोरी सीमेंट की खरीदी

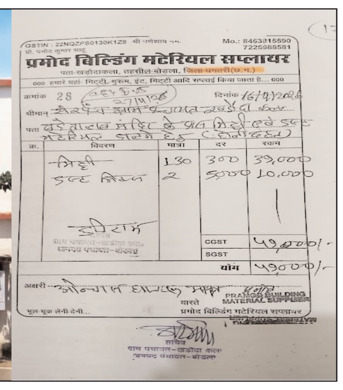

दर्शाते हुए कुल 94 हजार 500 रुपये खर्च होना बताया गया है। दोनों बिलों का भुगतान पंद्रहवें वित्त आयोग (जनपद स्तर) की राशि से किया जाना उल्लेखित है।

सबसे बड़ा सवाल बिल जारी करने वाले प्रमोद बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर पर खड़ा हो रहा है। बिल में दुकान का पता खड़ौदा कला, तहसील-बोड़ला, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़) अंकित है, जबकि बोड़ला विकासखंड कबीरधाम जिले में स्थित है। बिल पर दर्ज इस विसंगति ने दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामला केवल पते तक सीमित नहीं है। यदि पंचायत को वास्तव में रेत, गिट्टी और मिट्टी की आपूर्ति की गई है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि सामग्री किस खदान या घाट से लाई गई, उसकी रॉयल्टी पर्चियां, परिवहन चालान और वाहन विवरण कहां हैं। बिना वैध रॉयल्टी के खनिज सामग्री का परिवहन नियमों के विरुद्ध माना जाता है।

इसी प्रकार 100 बोरी सीमेंट उपयोग किए जाने का उल्लेख भी जांच का विषय बन गया है। संबंधित सप्लायर के पास सीमेंट कंपनी का मूल खरीद बिल, जीएसटी चालान, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री का रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। यदि यह सामग्री वास्तव में पंचायत कार्य में लगी है तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि गांवों के विकास के लिए दी जाती है, इसलिए प्रत्येक भुगतान पूरी तरह दस्तावेजी और पारदर्शी होना चाहिए। यदि भुगतान के आधार बने बिलों में ही ऐसी विसंगतियां सामने आ रही हैं तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत, खनिज विभाग, जीएसटी विभाग तथा संबंधित जांच एजेंसियां पूरे मामले की संयुक्त जांच करें। साथ ही संबंधित सप्लायर से रेत, गिट्टी और मिट्टी की रॉयल्टी पर्चियां, परिवहन दस्तावेज, सीमेंट की मूल खरीदी बिल और जीएसटी रिकॉर्ड प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए जाएं।

यदि जांच में सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यदि बिलों और वास्तविक अभिलेखों में अंतर मिलता है तो यह सरकारी धन के उपयोग से जुड़ी गंभीर अनियमितता का मामला बन सकता है। फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब संबंधित सप्लायर और जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा। निष्पक्ष जांच से ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आएगी।

भोरिंग पंचायत के पंचों ने सरपंच के खिलाफ खोला मोर्चा, कलेक्टर से की शिकायत

विश्व केसरी

महासमुंद (अनिल चौधरी)। ग्राम पंचायत भोरिंग में विकास कार्यों में कथित गड़बड़ी, पंचों एवं ग्रामीणों की अनदेखी और पंचायत निधि के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए 18 पंचों ने कलेक्टर विनय कुमार लंगेह को ज्ञापन सौंपा। पंचों ने पंचायत में कथित अव्यवस्थाओं का हवाला देते हुए सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कलेक्टर से मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

पंचों के अनुसार, पिछले चार-पांच दिनों से वे अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देने के लिए लगातार एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। उनका आरोप है कि एसडीएम अक्षा गुप्ता द्वारा उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा था और उन्हें हर बार बाद में आने की बात कहकर लौटा दिया जाता था। इससे नाराज पंचों ने पूर्व पार्षद पंकज साहू के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने पंचों का आवेदन स्वीकार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को भेज दिया है।

कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में पंचों ने सरपंच पर पंचायत के विकास कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने और पंचों तथा ग्रामीणों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पंचों का कहना है कि पंचायत की राशि के उपयोग में अनियमितताएं की जा रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच के ससुर पंचायत के कामकाज में हस्तक्षेप करते हुए मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में पंचों ने आरोप लगाया कि ग्रामसभा की बैठकों में जानबूझकर पंचों को सूचना नहीं दी जाती और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा हटरी बाजार की राशि के कथित गबन, ठेकेदारों से कमीशन लेकर घटिया गुणवत्ता की सीसी रोड बनवाने, मनरेगा की राशि के निजी इस्तेमाल तथा पंचों के साथ जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पंचों ने कहा कि पंचायत में जारी कथित अव्यवस्थाओं के कारण गांव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और ग्रामीणों में भी नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया नियमानुसार जल्द शुरू करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान उप सरपंच भेखराम साहू सहित वार्ड क्रमांक 1 के पंच सतबई नेहरू, हितेंद्र ढीढी, रजिया चेलक, पराग आवड़े, आनंद टंडन, निर्मला साहू, चपेश्वरी साहू, चमन साहू, रुक्मणी साहू, वेद प्रकाश साहू, गीता सोनवानी, खिलेश्वरी साहू, सावित्री साहू, खोरबहरा साहू, हरि साहू, चुम्मन साहू और गायत्री साहू मौजूद रहे।

एसडीएम कार्यालय की कार्यप्रणाली पर पूर्व पार्षद ने जताई नाराजगी

पूर्व पार्षद पंकज साहू ने एसडीएम कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंचों का आवेदन स्वीकार करना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चार-पांच बार कार्यालय पहुंचने के बावजूद पंचों का आवेदन नहीं लिया गया और उन्हें बार-बार बाद में आने के लिए कहा गया।

नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को मिली मंजूरी, जनप्रतिनिधियों ने मंत्री को दी बधाई

विश्व केसरी

महासमुंद (अनिल चौधरी)। प्रदेश में पांच नए शासकीय मेडिकल कॉलेज, 14 नर्सिंग कॉलेज और सात स्थानों पर फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू करने की मंजूरी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से उनके निवास पर मुलाकात कर जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए उनका अभिनंदन किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचंद राठी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश रूपरेला, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष आकाश पाण्डेय, भाजयुमो शहर अध्यक्ष राकेश सचदेव और पंकज जैन मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 370 नई सीटें बढ़ी हैं। इससे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचंद राठी ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के छात्र-छात्राओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के द्वार और अधिक खुले हैं। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों का परिणाम बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार से एक साथ पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति मिलना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।

अमित चक्रवर्ती बने रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन आलम सिंह रूपरा ने दिलाई शपथ

विश्व केसरी

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर द्वारा रोटरी वर्ष 2026-27 का स्थापना समारोह सह आधिकारिक क्लब भ्रमण , अत्यंत गरिमामय, भव्य एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। समाजसेवा, नेतृत्व, मित्रता एवं रोटरी की गौरवशाली परंपराओं से परिपूर्ण इस समारोह में रोटेरियन अमित चक्रवर्ती ने रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर के अध्यक्ष (President 2026-27) के रूप में विधिवत शपथ लेकर पदभार ग्रहण किया। उनके साथ क्लब के अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भी अपने-अपने दायित्वों का विधिवत निर्वहन करने का संकल्प लिया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला गवर्नर रोटेरियन आलम सिंह रूपरा एवं फर्स्ट लेडी रोटेरियन हरपाल रूपरा थे। उनके साथ सहायक गवर्नर रोटेरियन एस. नवीन, डीएसजी रोटेरियन अजय अग्रवाल,

पूर्व प्रांतपाल रोटेरियन एस. पी. चतुर्वेदी, पूर्व प्रांतपाल डॉ. आर. ए. शर्मा, तत्कालीन अध्यक्ष रोटेरियन शैलजा शुक्ला, तत्कालीन सचिव रोटेरियन कृतिका मोदी, क्लब के पूर्व अध्यक्षगण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वरिष्ठ रोटेरियन्स, विशिष्ट अतिथिगण एवं बड़ी संख्या में सदस्य तथा उनके परिवारजन उपस्थित रहे। क्लब सचिव रोटेरियन रंजीत पाल सिंह बाली एवं कोषाध्यक्ष रोटेरियन राजीव भारद्वाज के समर्पण, उत्कृष्ट समन्वय एवं अथक परिश्रम की सभी अतिथियों ने सराहना की। समारोह की शोभा बढ़ाने वालों में मोतीलाल सुल्तानिया, प्रो. आर. के. सक्सेना, पवन नलोतिया, अनुज शाह, मोहम्मद वानक, दीपक खंडेलवाल, डॉ. जी. बी. सिंह, डॉ. संजय धंधारिया, रोहित शिवहरे, एस. एस. डी. बड़गैय्या, डॉ. नवनीत सिंह, डॉ. प्रभात श्रीवास्तव, देबाशीष घटक, प्रेसिडेंट इलेक्ट श्याम मित्तल, नवनीत अग्रवाल, देवज्योति चटर्जी, महुआ चटर्जी, डॉ. आर. सी. बावरिया, डॉ. सी. पी. करण, स्वाति वर्मा, आभा वर्मा, चंदन गांगुली, सिद्धार्थ भट्टाचार्य, सुनील सुल्तानिया सहित क्लब के अनेक वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।

31 जुलाई तक होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा का पंजीयन

विश्व केसरी

सरसींवा (राकेश सोनी)। सारंगढ़ बिलाईगढ़, 26 जुलाई 2026/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ 2026 में ऋणी एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। किसान 31 जूलाई 2026 तक बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के माध्यम से अपने अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे - बाधित रोपाई, रोपण जोखिम- अधिसूचित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अधिसूचित मुख्य फसल की बोआई, रोपण, अंकुरण नहीं हो पाने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा, साथ ही ओलावृष्टि, जलभराव, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम होने वाली बरसात से फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले के ऋणी एवं अऋणी कृषक बीमा का लाभ लेने हेतु जिला के सहकारी बैंकों में तथा सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर फसल बीमा करा सकते है। उप संचालक कृषि जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष खरीफ सीजन के धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, मूंगफली,उड़द एवं मूंग फसल शामिल है>

डेंगू-मलेरिया की रोकथाम को लेकर पालिका चलाया अभियान, फैलाव वाले क्षेत्रों में दवा का छिड़काव

विश्व केसरी

महासमुंद (अनिल चौधरी)। बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत अन्य मच्छरजनित बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए नगर पालिका द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नगर के घनी आबादी वाले इलाकों, मुख्य बस स्टैंड, नालियों, जलभराव वाले स्थानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सफाई अमले द्वारा एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया गया।

अभियान के दौरान ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया, जहां मच्छरों के लार्वा पनपने की आशंका अधिक रहती है। इन जगहों पर तत्काल दवा का छिड़काव कर मच्छरों के प्रजनन को रोकने का प्रयास किया गया। नगर पालिका की ओर से आने वाले दिनों में सभी वार्डों में चरणबद्ध तरीके से एंटी लार्वा दवा का छिड़काव करने के साथ फॉगिंग और विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने कहा कि नागरिकों को मच्छरजनित बीमारियों से सुरक्षित रखना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बरसात के दौरान इन बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी वार्ड में स्वच्छता या मच्छर नियंत्रण के कार्य में लापरवाही न हो तथा नियमित रूप से एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग कराई जाए। अध्यक्ष के निर्देश पर नगर पालिका की टीम लगातार शहर के अलग-अलग वार्डों का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान जहां भी जलभराव या मच्छरों के पनपने की संभावना दिखाई दे रही है, वहां तत्काल एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। नगर पालिका ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अपने घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, पानी की टंकियों और अन्य जल पात्रों की नियमित सफाई करें तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखें। नगर पालिका ने कहा कि प्रशासन के प्रयासों के साथ नागरिकों की जागरूकता और सहभागिता से ही मच्छरजनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

यातायात पुलिस ने छात्र-छात्राओं को पढ़ाया यातायात नियम का पाठ, मिली सीख

विश्व केसरी

कसडोल (प्रवीण कुमार)। जागरूकता कार्यक्रम में अबतक 1800 छात्र छात्राये हुये लाभान्वित जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने और बच्चों में प्रारंभ से ही यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार गौरव राय के निर्देशन तथा उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) संजय कुमार साहू के मार्गदर्शन में ग्राम रोहरा, हथबंद नगर पंचायत कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को

यातायात नियमों का महत्व समझाया गया। उन्हें बताया गया कि मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। यातायात संकेतों का पालन करना, तीन सवारी से बचना, स्टंटबाजी न करना और बिना लाइसेंस वाहन न चलाना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान तथा सिटी सर्विलांस कैमरों से निगरानी की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम में बच्चों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई और उसके शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्हें पी.एम. राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ?1.5 लाख तक कैशलेस मदद मिलने की जानकारी दी गई। राहवीर योजना के अंतर्गत घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को ?25,000 का पुरस्कार तथा हिट एंड रन योजना के अंतर्गत मृतक को ?2 लाख एवं घायल को ?50,000 की सहायता प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई।

अब तक इस अभियान से लगभग 1800 छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हो चुके हैं। यह कार्यक्रम जिले के प्रत्येक स्कूल में निरंतर जारी रहेगा। अंत में अपील की गई कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में संकोच न करें, क्योंकि समय पर सहायता से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है।

देश सेवा करने कलेक्टर-एसपी ने युवाओं को किया प्रोत्साहित, हुए सम्मानित

विश्व केसरी

सरसींवा (राकेश सोनी)। सारंगढ़ बिलाईगढ़, 26 जुलाई 2026/ खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सारंगढ़ के सीपीएम कॉलेज में कारगिल विजय दिवस पर 'माय भारत' कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के छात्र छात्राओं की उपस्थिति में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू एवं पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा शामिल हुए।

अतिथियों ने युवाओ को देश सेवा के लिए प्रोत्साहित किया और माय भारत पोर्टल में पंजीयन करने की अपील की। इस अवसर पर प्रभारी खेल अधिकारी सह डिप्टी कलेक्टर शिक्षा शर्मा, कालेज के प्राचार्य आदि उपस्थित थे। माय भारत, यह एक फिजीकल इकोसिस्टम (भौतिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिश्रण) के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही अनुभवात्मक शिक्षण के अवसर, स्वयंसेवा के अवसर और मेगा इवेंट्स में भाग लेने जैसे सार्थक अवसर प्रदान करता है , इसके अलावा माय भारत प्रोफाइल, सीवी बिल्डर और मेंटरशिप जैसे मूल्यवान संसाधन भी उपलब्ध कराता है।

माय भारत पोर्टल लिंक https:// mybharat.gov.in/ है। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय, माय भारत की स्थापना युवा विकास, सहभागिता और राष्ट्र निर्माण के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।

इसका उद्देश्य नेतृत्व, स्वयंसेवा, अनुभवात्मक शिक्षा, नवाचार और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर युवाओं को सशक्त बनाना है, साथ ही 'सेवा भाव' और 'कर्तव्य बोध' के मूल्यों को पोषित करना है।

साझेदारी और युवा-केंद्रित पहलों के माध्यम से, एमवाई भारत युवाओं को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाता है ।

एक परिवार के तीन लोगों पर जानलेवा हमला, एक की मौत, दो घायल

विश्व केसरी

कोरबा (बबलू श्रीवास)। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के हर्राडीह गांव में एक ही रात हुई हत्या और जानलेवा हमले की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 65 वर्षीय महिला की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया, जबकि उनके बेटे और बहू पर घर में सोते समय हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी हीरालाल धनुहार को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया।

घर में सो रहे दंपति पर किया हमला

पुलिस के अनुसार, चैतराम धनुहार और उनकी पत्नी परमिला धनुहार घर में सो रहे थे। देर रात उन पर कथित रूप से लाठी से हमला किया गया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है।

वृद्धा की हत्या कर शव जंगल में फेंका

हमले के बाद आरोप है कि 65 वर्षीय समारिन बाई, जो पास में अकेले रहती थीं, की हत्या कर उनका शव नजदीकी जंगल में फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

कुछ घंटों में आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच, तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी हीरालाल धनुहार को गिरफ्तार कर लिया।

लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में जोरदार वापसी, सेंसेक्स 776 अंक उछला

विश्व केसरी

मुंबई। अमेरिका और ईरान द्वारा हमलों को स्थगित करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ। इस बीच घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्कों सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1 प्रतिशत तक की बढ़त देखने को मिली। बाजार में यह तेजी पिछले लगातार 5 कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद आई है।

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 776.01 अंक यानी 1.02 प्रतिशत बढ़कर 76,835.78 पर पहुंच गया, तो वहीं एनएसई का निफ्टी 50 228.50 अंक यानी 0.96 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 23,995.95 पर बंद हुआ।

व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 1.11 प्रतिशत और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 1.31 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। वहीं, सेक्टरवार देखें तो दिन के कारोबार में सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी मीडिया 2.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा, इसके बाद निफ्टी आईटी 2.3 प्रतिशत की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर रहा। निफ्टी रियल्टी में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा में क्रमशः 1.6 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

इसके अलावा, निफ्टी एफएमसीजी में 1 प्रतिशत, निफ्टी बैंक में 0.7 प्रतिशत, निफ्टी इंफ्रा में 0.66 प्रतिशत, निफ्टी मेटल में 0.6 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.45 प्रतिश, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.42 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

सेक्टरवार विश्लेषण करें तो निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियल्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि निफ्टी ऑयल एंड गैस का प्रदर्शन खराब रहा। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी मेटल ने लगातार तीन दिनों से जारी गिरावट को तोड़ते हुए अपने बाजार में तेजी दर्ज की।

निफ्टी में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में इटरनल, इंटरग्लोब एविएशन, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, मैक्स हेल्थ और श्रीराम फाइनेंस शामिल रहे, जबकि नुकसान उठाने वाले शेयरों में ओएनजीसी, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और डॉ रेड्डीज लैब्स शामिल रहे।

बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) पिछले सत्र के लगभग 476 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 481 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे निवेशकों को एक ही सत्र में 5 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

इस बीच, एक मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि पश्चिम एशिया में हमलों पर फिलहाल विराम लगने से आयात लागत और महंगाई बढ़ने की आशंकाएं कम हुई हैं, जिससे शेयर बाजार में राहत भरी तेजी देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट और लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड में कमी ने भी इस उम्मीद को मजबूत किया है कि स्थिति का स्थायी समाधान निकल सकता है। साथ ही, बाजार में लॉन्ग अनवाइंडिंग के संकेत भी देखने को मिले हैं, जो निवेशकों की धारणा में सुधार का संकेत देते हैं।

सरकार ने आरबीआई को 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलिमर करेंसी नोटों के फील्ड ट्रायल को दी मंजूरी

विश्व केसरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद को सोमवार को बताया कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 10 रुपए और 20 रुपए मूल्यवर्ग के पॉलिमर करेंसी नोटों के फील्ड ट्रायल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से दी।

सरकार ने हालांकि स्पष्ट किया कि इस फैसले का मतलब कागज के नोटों को बंद करना नहीं है। पॉलिमर नोट मौजूदा कागजी नोटों के साथ ही चलन में रहेंगे और फिलहाल कागज-आधारित बैंक नोटों को पूरी तरह पॉलिमर नोटों से बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार के अनुसार, आरबीआई फील्ड ट्रायल के तहत 10 रुपए और 20 रुपए के एक-एक अरब (1 बिलियन) पॉलिमर नोट जारी करेगा। इन नोटों को परीक्षण के आधार पर बाजार में उतारा जाएगा ताकि भारतीय परिस्थितियों में इनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। यदि ट्रायल सफल रहता है, तभी इनके व्यापक स्तर पर जारी किए जाने पर विचार किया जाएगा।

आरबीआई का कहना है कि पॉलिमर नोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर केंद्रीय बैंक का मानना है कि इनकी उम्र अधिक होती है, जिससे अधिक नकदी वाले देशों के लिए यह बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।

आरबीआई ने यह भी बताया कि कम मूल्यवर्ग के नोट जल्दी खराब हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बार-बार छापना और नष्ट करना पड़ता है। पॉलिमर नोट इस समस्या को कम कर सकते हैं और लंबे समय में नोटों की छपाई और प्रतिस्थापन पर होने वाला खर्च भी घटा सकते हैं। इसके अलावा, पॉलिमर नोटों में पारदर्शी 'सी-थ्रू' विंडो और विशेष सुरक्षा धागे (सिक्योरिटी थ्रेड) जैसे उन्नत सुरक्षा फीचर शामिल किए जा सकते हैं, जिससे नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। डिजिटल भुगतान पर संभावित प्रभाव को लेकर आरबीआई ने कहा कि अभी इस बारे में कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। पॉलिमर नोट नियमित रूप से चलन में आने के बाद ही इसका आकलन किया जा सकेगा।

केंद्रीय बैंक का मानना है कि नकद मुद्रा और डिजिटल भुगतान दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और भविष्य में भी दोनों माध्यम साथ-साथ चलते रहेंगे।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में दोहराया कि फिलहाल कागज आधारित बैंक नोटों को पूरी तरह पॉलिमर नोटों से बदलने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

ई20 पेट्रोल से बेहतर एक्सेलरेशन और कम कार्बन उत्सर्जन, इंजन को नुकसान का कोई सबूत नहीं : सरकार

विश्व केसरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि ई20 पेट्रोल से वाहन को बेहतर एक्सेलरेशन, स्मूद राइड क्वालिटी और ई10 पेट्रोल की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन मिलता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन और वास्तविक उपयोग के आंकड़ों में एथेनॉल की वजह से इंजन में जंग, असामान्य घिसावट या वाहन की उम्र कम होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, यहां तक कि उन लाखों पुराने वाहनों में भी नहीं, जिन्हें मूल रूप से ई20 के लिए प्रमाणित नहीं किया गया था।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि ई20 ईंधन वाहन की राइड क्वालिटी को बेहतर बनाता है और ई10 की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन करता है। मंत्रालय के

अनुसार, अधिक एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन अधिक स्वच्छ और पूर्ण दहन सुनिश्चित करता है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) का उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है और शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।

सरकार ने बताया कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (आईआईपी) और विभिन्न वाहन निर्माताओं ने ई20 ईंधन लागू करने से पहले प्रयोगशाला परीक्षण और फील्ड ट्रायल किए थे। इन परीक्षणों में इंजन की मजबूती, वाहन प्रदर्शन, स्टार्ट होने की क्षमता, जंग-रोधी क्षमता, सामग्री की अनुकूलता, उत्सर्जन और ईंधन दक्षता जैसे कई पहलुओं का मूल्यांकन किया गया। इन सभी अध्ययनों ने पुष्टि की कि निर्धारित मानकों के तहत ई20 ईंधन पूरी तरह सुरक्षित है।

सरकार ने यह भी कहा कि परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि पुराने वाहनों के प्रदर्शन में ई20 ईंधन के कारण कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आता और न ही इंजन या अन्य पुर्जों में असामान्य घिसावट देखने को मिली है।

अपने दावे के समर्थन में सरकार ने बड़े स्तर पर जुटाए गए आंकड़ों का भी हवाला दिया। सरकार के अनुसार, एक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें से लगभग 1.5 करोड़ वाहन ऐसे थे जिन्हें मूल रूप से ई20 के अनुकूल प्रमाणित नहीं किया गया था। इसके बावजूद किसी भी वाहन में ई20 के कारण जंग, असामान्य घिसावट या पुर्जों की उम्र कम होने की शिकायत सामने नहीं आई।

इसी तरह, एक प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता ने भी ऐसे ही परिणाम दर्ज किए हैं। वहीं, एक अन्य बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी (ओईएम) ने लंबे समय तक 1.4 करोड़ ई20 ईंधन से चलने वाले वाहनों की निगरानी की और उसमें भी एथेनॉल के कारण इंजन में जंग या किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का कोई प्रमाण नहीं मिला।

मंत्रालय ने कहा कि एआरएआई ने भी दोहराया है कि किसी भी वाहन को ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कड़े परीक्षणों और सत्यापन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी सुरक्षा और प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाता है।

100 करोड़ रुपए से अधिक आय घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या 5 साल में 300 प्रतिशत बढ़ी: सरकार

विश्व केसरी

नई दिल्ली। देश में 100 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय घोषित करने वाले आयकरदाताओं की संख्या पिछले 5 वर्षों में लगभग चार गुना हो गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 में 576 लोगों ने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपए से अधिक घोषित की, जबकि आकलन वर्ष 2021-22 में यह संख्या 142 थी। इस तरह पांच वर्षों में ऐसे उच्च आय वाले करदाताओं की संख्या में करीब 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि आकलन वर्ष 2022-23 में 100 करोड़ रुपए से अधिक आय घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या 301 थी। इसके बाद आकलन वर्ष 2023-24 में यह मामूली घटकर 284 रह गई, लेकिन आकलन वर्ष 2024-25 में बढ़कर 415 हो गई

और आकलन वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 576 तक पहुंच गई।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम, 2025 के तहत 'अरबपति' शब्द की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। इसलिए सरकार ने आयकर रिटर्न के आधार पर केवल उन व्यक्तियों का आंकड़ा साझा किया है, जिन्होंने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपए से अधिक घोषित की है।

आय असमानता से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा कि हालिया आंकड़े देश में आय वितरण और रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत देते हैं।

सरकार ने हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे (एचसीईएस) 2023-24 का हवाला देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनी गुणांक घटकर 0.237 रह गया है, जो 2022-23 में 0.266 था। वहीं, शहरी क्षेत्रों में यह 0.314 से घटकर 0.284 हो गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आय असमानता का अंतर कम होने का संकेत मिलता है।

सरकार ने श्रम बाजार की स्थिति में भी सुधार का दावा किया। पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023-24 में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई है।

सरकार ने कहा कि वह आय असमानता को कम करने के लिए प्रगतिशील कर व्यवस्था, रोजगार सृजन कार्यक्रमों और स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने जैसे कदम उठा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा विकास पर आधारित निवेश और लक्षित कर प्रोत्साहनों के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल हुए : आयकर विभाग

विश्व केसरी

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने सोमवार को ऐलान किया कि असेसमेंट ईयर (एवाई) 2026-27 के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हो चुके हैं। साथ ही पात्र करदाताओं से अपील की कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करें।

आईटीआर फाइलिंग का यह आंकड़ा ऐसे समय पर आया है, जब एक सप्ताह से भी कम समय पहले आयकर विभाग ने जानकारी दी थी कि आईटीआर फाइलिंग का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया है और एक ही दिन में 15 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए थे।

इस महीने की शुरुआत में विभाग ने बताया था कि 1.7 करोड़ से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, जिससे यह संकेत मिला कि आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आने के साथ आईटीआर दाखिल करने की रफ्तार लगातार तेज हो रही है।

आयकर विभाग ने करदाताओं से 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले आईटीआर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

विभाग ने बार-बार करदाताओं से आग्रह किया है कि वे अंतिम कुछ दिनों तक इंतजार न करें। विभाग का कहना है कि समय रहते आईटीआर दाखिल करने से ई-फाइलिंग पोर्टल पर अत्यधिक ट्रैफिक से बचा जा सकता है और रिटर्न की प्रोसेसिंग भी अधिक सुचारु रूप से होती है।

आईटीआर-1 (सहज) उन निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और आय का स्रोत वेतन, एक मकान तथा अन्य स्रोत हैं। इसमें 5,000 रुपये तक की कृषि आय भी शामिल हो सकती है।

वहीं, आईटीआर-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए लागू होता है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं होती, लेकिन कैपिटल गेन जैसे स्रोतों से आय होती है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में अब तक विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन से जुटाए 26,639 करोड़ रुपए से ज्यादा

विश्व केसरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में (22 जुलाई तक) विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए कुल 26,639.33 करोड़ रुपए जुटाए हैं। संसद में सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, इसमें 20,272.40 करोड़ रुपए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में हिस्सेदारी बेचने (ऑफर फॉर सेल- ओएफएस) से प्राप्त हुए हैं, जबकि 6,366.93 करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइजेशन से हासिल किए गए हैं।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से अलग से विनिवेश लक्ष्य तय करना बंद कर दिया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान (बीई) में 80,000 करोड़ रुपए को 'मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स' के तहत रखा गया है, जिसमें सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन से विभिन्न माध्यमों के जरिए मिलने वाली अनुमानित आय शामिल है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है और किसी भी सौदे को पूरा करने का समय बाजार की स्थिति, घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, भू-राजनीतिक घटनाक्रम, निवेशकों की रुचि और प्रशासनिक तैयारियों जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। साथ ही, चूंकि विनिवेश से जुड़े लेनदेन बाजार के लिहाज से संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनके लिए पहले से कोई निश्चित समयसीमा तय करना संभव नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के शुरुआती तीन महीनों से कुछ अधिक समय में ही सरकार की विनिवेश से हुई आय पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक रही है।

वर्तमान में शेयर बाजार में 68 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) सूचीबद्ध हैं, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी का कुल मूल्य 22.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा, 16 सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (बैंक और बीमा कंपनियां) भी सूचीबद्ध हैं, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 19 लाख करोड़ रुपए है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में सात कंपनियों में ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए हिस्सेदारी बेची गई, जिनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 2,200 करोड़ रुपए से अधिक, कोल इंडिया से 5,500 करोड़ रुपए से अधिक, एनएचपीसी से 4,300 करोड़ रुपए से अधिक, एनएलसी इंडिया से 1,200 करोड़ रुपए से अधिक, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) से 2,000 करोड़ रुपए से अधिक और कोचीन शिपयार्ड से 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई गई। ओएफएस एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर या बड़े शेयरधारक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी आम निवेशकों को बेच सकते हैं। यह प्रक्रिया आईपीओ (आईपीओ) या एफपीओ (एफपीओ) की तुलना में कम दस्तावेजी औपचारिकताओं वाली और अधिक तेज मानी जाती है।

डेटा लीक पर बोला बैंक ऑफ बड़ौदा; कोर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित, फॉरेंसिक जांच शुरू

विश्व केसरी

मुंबई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोमवार को डेटा लीक को लेकर बयान जारी किया, जिसमें सरकारी बैंक ने कहा कि उसका कोर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और उसने मामले की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है।

बैंक ऑफ बड़ौदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी किए बयान में कहा, 'बैंक में मजबूत इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू हैं। यह घटना बैंक के एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट से कम्प्रोमाइज होने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप कुछ डेटा तक अनधिकृत पहुंच बनाई गई है। इस मामले की तुरंत पहचान कर ली गई थी और तत्काल

आवश्यक सुरक्षा एवं नियंत्रण संबंधी कदम उठाए गए हैं। इसमें बैंक की कोर बैंकिंग प्रणालियों तक कोई पहुंच नहीं बनाई गई और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं।

बैंक ने आगे कहा, 'इस घटना की विस्तृत फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है और बैंक लागू नियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बैंक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा अपने ग्राहकों और पक्षकारों का विश्वास कायम रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब एक टीबी संवेदनशील डेटा डार्क वेब पर उपलब्ध है। इस डेटा में पर्सनल और कॉरपोरेट बैंकिंग से संबंधित जानकारी थी।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि हैकर का दावा किया है कि उसके पास 1 टीवी संवेदनशील डेटा है। इसमें सेविंग्स और करंट अकाउंट के रिकॉर्ड, लोन का डेटा, नेटबैंकिंग यूजर की जानकारी, एनआरआई और कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विस के रिकॉर्ड, कस्टमर सपोर्ट से जुड़ी जानकारी और ब्रांच या एटीएम से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं।

हालांकि, अभी तक किसी हैकर ने सार्वजनिक तौर पर इस डेटा लीक की जिम्मेदारी नहीं ली है।

इस डेटा लीक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 0.91 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 244.20 रुपए पर बंद हुए।

जिन इलाकों में लगे होते हैं खूब सारे पेड़, वहां बुजुर्ग आबादी रहती है डिप्रेशन से कोसों दूर: स्टडी में खुलासा

सिडनी । संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, डिप्रेशन एक आम मानसिक विकार है। इससे दुनिया के लगभग 28.0 करोड़ लोग जूझ रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो दुनिया के 5.7 फीसदी बुजुर्ग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। डिप्रेशन की वजह अनगिनत हैं, लेकिन हाल की एक स्टडी कैसे इससे बचा जा सकता है इस ओर ध्यान दिलाती है। ऑस्ट्रेलिया में हुए एक लंबे समय तक चले अध्ययन में पाया गया है कि अधिक वृक्षों वाले इलाकों में रहने से बुजुर्गों में बढ़ती उम्र के दौरान अवसाद (डिप्रेशन) से बचाव में मदद मिल सकती है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया की 'न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के सिडनी सेंटर फॉर हेल्दी ब्रेन एजिंग' (सीएचईबीए) की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 'जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स' में प्रकाशित यह शोध स्वस्थ उम्र बढ़ने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अर्बन प्लानिंग की संभावित भूमिका को रेखांकित करता है।

सीएचईबीए ने ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी के सहयोग से यह अध्ययन किया। इसमें 70 से 90 वर्ष की आयु के 1,000 से अधिक बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोगों को शामिल किया गया और 12 वर्षों तक उनका अध्ययन किया गया। शोध में पाया गया कि जिन लोगों ने ऐसे इलाकों में जीवन बिताया जहां पेड़ों की छाया और हरियाली अधिक थी, उनमें समय के साथ अवसाद के लक्षण कम देखने को मिले।

शोधकर्ताओं ने यह जांच की कि आसपास के पर्यावरण से जुड़ी कौन-कौन सी चीजें जैसे पेड़ों की छतरी (ट्री कैनोपी), पार्क, समुद्र, नदियों और झीलों तक पहुंच, जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता और वायु प्रदूषण अवसाद के लक्षणों में बदलाव से जुड़ी हैं।

अध्ययन में कहा गया कि लंबे समय तक अधिक पेड़ों वाले वातावरण में रहने का संबंध लगातार कम अवसाद स्तर से पाया गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि दुनिया भर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग हर पांच वयस्कों में से एक व्यक्ति अवसाद से प्रभावित होता है।

हालांकि, अध्ययन में यह पाया गया कि अन्य पर्यावरणीय कारकों, जैसे पार्कों की उपलब्धता, समुद्र या जल क्षेत्रों (ब्लू स्पेस) तक पहुंच, सेवाओं की उपलब्धता या लंबे समय तक कम स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क का अवसाद के लक्षणों पर कोई स्पष्ट और लगातार प्रभाव नहीं दिखा।

शोधकर्ताओं के अनुसार, शहरों में अधिक पेड़ लगाने और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने जैसी योजनाएं बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

सूंघने की क्षमता में गिरावट भी अल्जाइमर्स का शुरुआती संकेत

नई दिल्ली। अल्जाइमर एक ऐसी अवस्था है जिसमें ढलती उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होती चली जाती है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, अल्जाइमर डिमेंशिया (मस्तिष्क क्षीणता) का एक प्रकार है। इसमें याददाश्त के साथ-साथ सोचने-समझने, निर्णय लेने, और पहचानने व बोलने और समझने की क्षमता में गिरावट आती है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन पर गौर किया जाए तो इसको काबू में किया जा सकता है। इसमें से एक सूंघने की क्षमता भी है।

एक नए शोध में संकेत मिला है कि सूंघने की क्षमता में कमी अल्जाइमर्स के शुरुआती संकेत हो सकते हैं, जो याददाश्त में गिरावट के स्पष्ट लक्षणों से पहले ही दिखाई दे सकती है।

यह निष्कर्ष प्रतिष्ठित जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित हुआ है, जिसमें बताया गया कि दिमाग में होने वाले शुरुआती बदलाव इंद्रियों, विशेष रूप से सूंघने की क्षमता पर असर डालते हैं।

जर्मनी के डीजेडएनई और लुडविंग-मैक्सिमिलियंस-यूनिवर्सिटी म्यूनिख के वैज्ञानिकों ने पाया कि दिमाग की प्रतिरक्षा प्रणाली इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शोध के अनुसार, माइक्रोग्लिया नामक प्रतिरक्षा कोशिकाएं गलती से उन तंत्रिका रेशों पर हमला कर सकती हैं, जो सूंघने की क्षमता के लिए जरूरी होते हैं।

अध्ययन में बताया गया कि सूंघने से जुड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है, जब दिमाग के दो अहम हिस्सों के बीच संचार बाधित हो जाता है। इनमें ओलफैक्ट्री बल्ब, जो नाक से आने वाले गंध संकेतों को प्रोसेस करता है, और लोकस कोरुलियस शामिल हैं, जो इस प्रक्रिया को तंत्रिका कनेक्शनों के जरिए नियंत्रित करता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, जब माइक्रोग्लिया इन दोनों हिस्सों के बीच संपर्क को प्रभावित करती हैं, तो गंध पहचानने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। यही बदलाव आगे चलकर अल्जाइमर के अन्य लक्षणों का संकेत बन सकते हैं।

इस अध्ययन में चूहों और इंसानों, दोनों पर आधारित साक्ष्य शामिल किए गए। शोधकर्ताओं ने दिमाग के ऊतकों के विश्लेषण और पीईटी स्कैनिंग के जरिए यह समझने की कोशिश की कि बीमारी के शुरुआती चरणों में ये परिवर्तन कैसे होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सूंघने की क्षमता में कमी को समय रहते पहचाना जाए, तो यह अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी के शुरुआती निदान में मददगार साबित हो सकता है, जिससे इलाज और देखभाल के बेहतर विकल्प विकसित किए जा सकते हैं।

बालों के झड़ने से है परेशान, जानें तेल लगाने का सही समय और तरीका

नई दिल्ली। बालों की देखभाल को लेकर लोगों की अपनी-अपनी राय हैं। कोई बालों में घंटों तेल लगाकर रखने को सबसे अच्छा तरीका मानता है, तो कोई जल्दी-जल्दी तेल लगाकर धो लेना पसंद करता है। लोग बालों को मजबूत बनाने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। इन्हीं उपायों में सबसे पुराना तरीका है बालों में तेल लगाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ज्यादा देर तक तेल लगाए रखना बालों के लिए फायदेमंद होता है?

विशेषज्ञों के अनुसार, हमारे बाल मुख्य रूप से केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। बालों की बाहरी परत कई छोटी-छोटी कोशिकाओं से बनी होती है, जो पानी को सोखने की क्षमता रखती हैं। जब बाल बार-बार पानी के संपर्क में आते हैं तो ये कोशिकाएं फूल जाती हैं और सूखने के बाद वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौटती हैं। यह प्रक्रिया लगातार होने पर बालों की मजबूती धीरे-धीरे कम हो सकती है। इस वजह से बाल कमजोर होने लगते हैं, आसानी से टूट सकते हैं और दोमुंहे बालों की समस्या भी बढ़ सकती है। बालों को धोने से पहले तेल लगाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। नहाने से कुछ समय पहले बालों और स्कैल्प पर तेल लगाने से बालों के ऊपर एक हल्की सुरक्षा परत बन जाती है। यह परत बालों को जरूरत से ज्यादा पानी सोखने से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा शैंपू में मौजूद कुछ रसायनों का सीधा असर बालों पर कम हो सकता है, जिससे बालों की प्राकृतिक नमी बनी रहती है और वे ज्यादा रूखे नहीं होते। कई लोग रातभर बालों में तेल लगाकर सोते हैं। उनका मानना होता है कि ज्यादा समय तक तेल लगा रहने से बालों को ज्यादा पोषण मिलेगा। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि हर व्यक्ति के लिए यह तरीका सही नहीं होता। खासकर जिन लोगों की स्कैल्प ज्यादा तैलीय रहती है, उनके लिए लंबे समय तक तेल लगा रहना परेशानी बढ़ा सकता है। स्कैल्प पर प्राकृतिक रूप से एक तेल बनता है, जिसे सीबम कहा जाता है। जब इसके ऊपर लंबे समय तक अतिरिक्त तेल जमा रहता है तो कुछ लोगों में फंगल ग्रोथ बढ़ सकती है। इससे डैंड्रफ, सिर में खुजली और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में स्कैल्प की यह परेशानी बालों के झड़ने को भी बढ़ा सकती है। इसलिए तेल को जरूरत से ज्यादा देर तक लगाए रखना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं माना जाता। बालों में तेल लगाने के लिए विशेषज्ञ आमतौर पर नहाने से करीब 15 से 30 मिनट पहले का समय बेहतर मानते हैं। इतने समय में तेल बालों पर अपनी सुरक्षा परत बना लेता है और धोने के दौरान बालों को नुकसान से बचाने में मदद करता है। तेल लगाते समय इसे धीरे-धीरे बालों की लंबाई और स्कैल्प पर लगाना चाहिए। हल्के हाथों से मसाज करने से आराम भी मिलता है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है।

मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग की दस्तक, मार्मोट का मांस खाने से हुआ संक्रमण

उलानबटार। मंगोलिया के पश्चिमी खोव्द प्रांत में ब्यूबोनिक प्लेग के एक संदिग्ध मामले की प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय जूनोटिक रोग केंद्र (एनसीजेडडी) ने शुक्रवार को बताया कि अंतिम बैक्टीरियोलॉजिकल जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई।

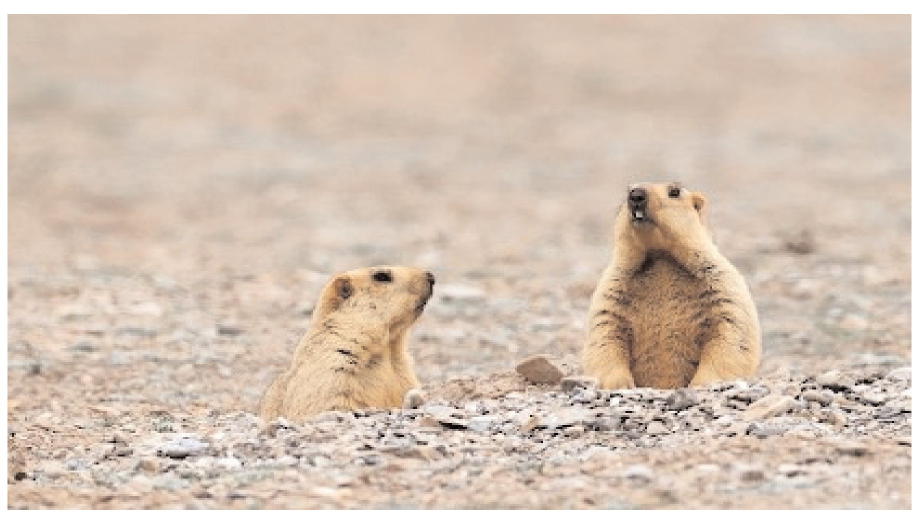

एनसीजेडडी के अनुसार, संक्रमित व्यक्ति को पड़ोसी बायान-उल्गी प्रांत के उलानखुस क्षेत्र की यात्रा के दौरान मार्मोट (एक प्रकार की जंगली गिलहरी) का मांस खाने के बाद संक्रमण हुआ। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से मार्मोट का शिकार न करने, उसका मांस या आंतरिक अंग न छूने और मृत या बीमार जंगली कृंतकों के संपर्क से बचने की अपील की है। केंद्र ने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों से संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। हालांकि मंगोलिया में मार्मोट के शिकार पर कानूनी प्रतिबंध है, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे स्वादिष्ट भोजन मानते हैं, जिसके कारण अवैध शिकार जारी है।

एनसीजेडडी के अनुसार, गर्मियों के महीनों में प्लेग फैलने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण इलाकों की यात्रा करते हैं और कुछ लोग मार्मोट का मांस भी खाते हैं। पिछले वर्षों में भी इसी अवधि के दौरान मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ मरीजों की मौत भी हुई थी। केंद्र ने बताया कि मंगोलिया के 21 में से 17 प्रांत वर्तमान में प्लेग प्रभावित या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की श्रेणी में हैं।

पिछले वर्ष सितंबर में देश में ब्यूबोनिक प्लेग के तीन मामलों की पुष्टि हुई थी, जिनमें से दो खुव्सगुल प्रांत के थे। सभी मरीजों का उपचार खुव्सगुल प्रांतीय जनरल अस्पताल में किया गया था। संक्रमितों के संपर्क में आए 80 लोगों को पृथक (आइसोलेट) कर स्थानीय अस्पतालों में इलाज दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, ब्यूबोनिक प्लेग एक जीवाणुजनित (बैक्टीरियल) बीमारी है, जो जंगली कृंतकों, विशेषकर मार्मोट जैसे जानवरों पर रहने वाले पिस्सुओं के माध्यम से फैलती है। समय पर इलाज न मिलने पर यह बीमारी 24 घंटे के भीतर जानलेवा साबित हो सकती है।

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इतिहास में प्लेग ने कई बड़ी महामारियों को जन्म दिया, जिनमें 14वीं शताब्दी की 'ब्लैक डेथ' भी शामिल है, जिससे यूरोप में 5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। हालांकि आज एंटीबायोटिक दवाओं और सामान्य सावधानियों की मदद से इस बीमारी का प्रभावी इलाज संभव है।

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, प्लेग ओशिनिया को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। 1990 के दशक के बाद से इसके अधिकांश मानव मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में डीआरसी, मेडागास्कर और पेरू इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल हैं।

दक्षिण कोरिया: लगभग आधे कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही पैरेंटल लीव, सर्वे में खुलासा

सोल। पिछले साल (2025) दक्षिण कोरिया से एक ऐसी खबर आई जो इस देश के लिए राहत भरी थी। आंकड़ों में पैरेंटल लीव की कहानी थी। देश ने कहा कि बर्थरेट बढ़ने की वजह से 2024 मेंआंकड़ा बढ़ा है। जन्मदर में 2023 के मुकाबले 3.6 प्रतिशत की वृद्धि थी। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि ऐसा उसकी पॉलिसी की वजह से संभव हो पाया है। लेकिन 2026 में एक सर्वे सरकारी दावों की हवा निकालता है।

ये बताता है कि दक्षिण कोरिया में कामकाजी लोगों के लिए मातृत्व और पैरेंटल लीव (बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश) का लाभ उठाना आसान नहीं है। एक नए सर्वेक्षण में सामने आया है कि देश के करीब आधे कर्मचारी जरूरत पड़ने पर भी स्वतंत्र रूप से पैरेंटल लीव या बच्चों की देखभाल के लिए कम कार्य घंटे की सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते।

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह सर्वे 1 जून से 9 जून के बीच 19 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,000 कार्यालय कर्मचारियों पर किया गया। सर्वेक्षण गैपजिल 119 नामक नागरिक संगठन की ओर से कराया गया, जो कार्यस्थलों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करता है। इसे ग्लोबल रिसर्च एजेंसी ने संचालित किया। सर्वे के अनुसार, 46.7 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि वे जरूरत पड़ने पर भी स्वतंत्र रूप से पैरेंटल लीव नहीं ले सकते।

यह आंकड़ा बताता है कि कानूनी प्रावधान होने के बावजूद कई कर्मचारियों को कार्यस्थल पर ऐसी सुविधाओं का लाभ लेने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूत हिम्मत शाह का बचपन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के बीच बीता

नई दिल्ली। 22 जुलाई 1933 को गुजरात के लोथल में जन्मे हिम्मत शाह भारतीय आधुनिक मूर्तिकला और ड्राइंग के उन अग्रणी कलाकारों में रहे, जिनकी कला में इतिहास, स्मृति और मानव सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है।

हिम्मत शाह ने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के बीच बचपन बिताया, जिसने उनकी कलात्मक दृष्टि को गहराई से प्रभावित किया। कम उम्र में ही वे भावनगर चले गए और 'घरशाला' में पढ़ाई की। यह स्कूल 'दक्षिणमूर्ति' से जुड़ा था, जो गुजरात में राष्ट्रवादी पुनर्जागरण का बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र था। 'घरशाला' में ही हिम्मत शाह ने कलाकार-शिक्षक जगुभाई शाह से कला की शुरुआती शिक्षा ली। यह सब बॉम्बे के जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेने और फिर 1956 से 1960 तक सरकारी सांस्कृतिक स्कॉलरशिप पर बड़ौदा जाने से पहले हुआ था।

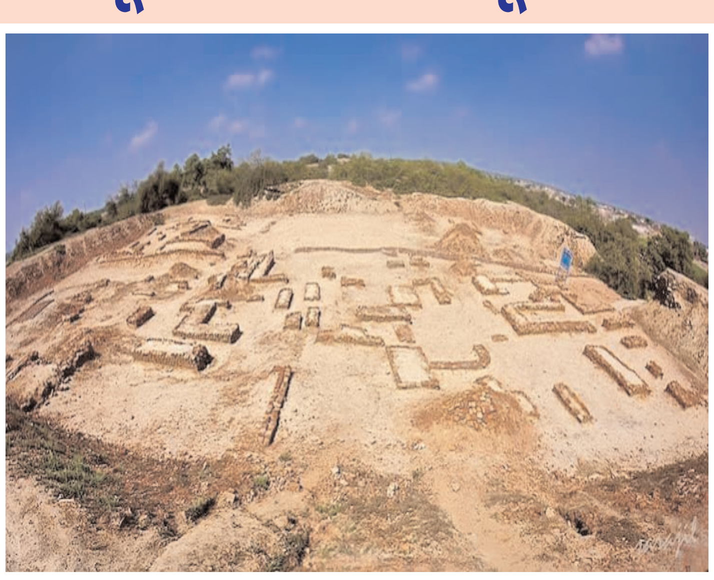

बड़ौदा में एक युवा कलाकार के तौर पर हिम्मत शाह ने एनएस बेंद्रे से बहुत कुछ सीखा, जिनमें उन्हें एक आधुनिक कलाकार की छवि दिखी। साथ ही उन्होंने केजी सुब्रमण्यन से भी सीखा, जिनकी कला की भाषा की खोज और लोक कला की समझ ने उन्हें प्रेरित किया। ड्राइंग के प्रति उनका झुकाव स्वाभाविक और जरूरी था।

शाह 'ग्रुप 1890' के सदस्य थे, जो जे. स्वामीनाथन द्वारा बनाया गया कलाकारों का एक समूह था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इस समूह की पहली और एकमात्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इसके कुछ ही समय बाद यह समूह बिखर गया और हिम्मत शाह समेत इसके सभी सदस्यों ने अपनी कला-यात्रा जारी रखी।

कवि और राजनयिक ऑक्टेवियो पाज की सिफारिश पर हिम्मत शाह को फ्रांसीसी सरकार की स्कॉलरशिप मिली। 1967 में वे पेरिस गए, जहां उन्होंने एसडब्ल्यू हेयटर और कृष्णा रेड्डी की देखरेख में 'एटेलियर 17' में एचिंग (नक्काशी) की पढ़ाई की।

हिम्मत अपनी मूर्तियों में प्रिंटमेकिंग की सतह के प्रभावों का इस्तेमाल करते थे, जिससे अलग-अलग मटीरियल को नए और प्रभावशाली ढंग से पेश करने की उनकी काबिलियत का पता चलता था। पेरिस में बिताए दो सालों के दौरान पढ़ाई करने और यूरोप के म्यूजियम्स की यात्रा करने से हिम्मत का अंतरराष्ट्रीय आधुनिकतावाद से जुड़ाव और मजबूत हुआ।

यूरोप से लौटने के बाद हिम्मत के शुरुआती कामों से उनके चुने हुए रास्ते का पता चलता है। इसमें टेराकोटा और स्टोनवेयर से बनी अलग-अलग खड़ी मूर्तियां शामिल थीं, जिनमें टोटेम जैसा एहसास था, आकृतियों का ऐसा समूह जो शायद किसी प्राचीन बस्ती के जीवन की झलक देता था।

1967 से 1971 के बीच, हिम्मत शाह ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स स्कूल में ईंट, सीमेंट और कंक्रीट से बड़े-बड़े भित्ति-चित्र (म्यूरल) डिजाइन किए और बनाए। इसके बाद, उन्होंने 'सिल्वर पेंटिंग्स' नाम की सीरीज़ में प्लास्टर पर रिलीफ (उभरी हुई नक्काशी) और जल्द ही टेराकोटा और ब्रॉन्ज (कांस्य) में मूर्तियां बनाना शुरू किया। वे दिल्ली चले गए और बाद में गढ़ी में एक स्टूडियो शुरू किया जो कलाकारों की प्रयोगशाला बन गया। यहां हिम्मत शाह टेराकोटा में एक अनोखी शैली विकसित करने के लिए मिट्टी और स्लिप (मिट्टी के घोल) के साथ प्रयोग करते थे।

2004-2005 में हिम्मत शाह ने अपनी ब्रॉन्ज की मूर्तियों पर काम किया और उन्हें लंदन की एक फाउंड्री में ढलवाया। टेराकोटा और ब्रॉन्ज में बनी उनकी 'हेड्स' (सिर की आकृतियां) उनके सबसे मशहूर काम हैं। शाह ने 2000 के दशक में जयपुर में अपना खुद का स्टूडियो शुरू किया। उनकी मूर्तियों को कई प्रतिष्ठित प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया है, जिनमें लौवर, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, बिएननेल डी पेरिस, म्यूजियम लुडविग, म्यूजियो डे ला नेसियन और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, दिल्ली शामिल हैं।

हिम्मत शाह को साहित्य कला परिषद पुरस्कार (1988), ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी पुरस्कार (1996) और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान (2003) दिया गया। शाह का 2 मार्च 2025 को जयपुर में निधन हो गया था।

मुझको राणाजी माफ करना के नए वर्जन में दिखीं माहिरा शर्मा

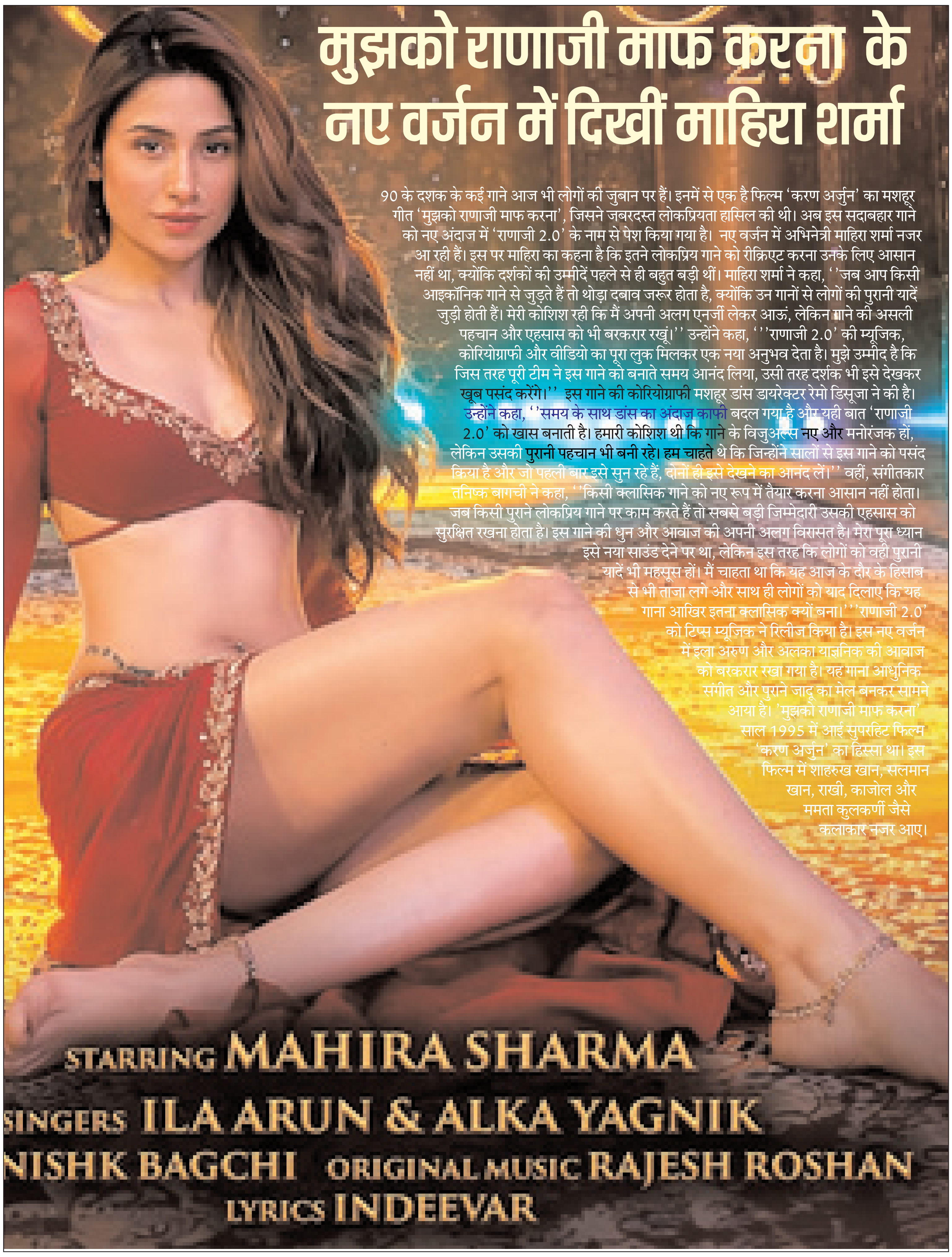

90 के दशक के कई गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इनमें से एक है फिल्म 'करण अर्जुन' का मशहूर गीत 'मुझको राणाजी माफ करना', जिसने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। अब इस सदाबहार गाने को नए अंदाज में 'राणाजी 2.0' के नाम से पेश किया गया है। नए वर्जन में अभिनेत्री माहिरा शर्मा नजर आ रही हैं। इस पर माहिरा का कहना है कि इतने लोकप्रिय गाने को रीक्रिएट करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि दर्शकों की उम्मीदें पहले से ही बहुत बड़ी थीं। माहिरा शर्मा ने कहा, ''जब आप किसी आइकॉनिक गाने से जुड़ते हैं तो थोड़ा दबाव जरूर होता है, क्योंकि उन गानों से लोगों की पुरानी यादें जुड़ी होती हैं। मेरी कोशिश रही कि मैं अपनी अलग एनर्जी लेकर आऊं, लेकिन गाने की असली पहचान और एहसास को भी बरकरार रखूं।'' उन्होंने कहा, '''राणाजी 2.0' की म्यूजिक, कोरियोग्राफी और वीडियो का पूरा लुक मिलकर एक नया अनुभव देता है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पूरी टीम ने इस गाने को बनाते समय आनंद लिया, उसी तरह दर्शक भी इसे देखकर खूब पसंद करेंगे।'' इस गाने की कोरियोग्राफी मशहूर डांस डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने की है। उन्होंने कहा, ''समय के साथ डांस का अंदाज काफी बदल गया है और यही बात 'राणाजी 2.0' को खास बनाती है। हमारी कोशिश थी कि गाने के विजुअल्स नए और मनोरंजक हों, लेकिन उसकी पुरानी पहचान भी बनी रहे। हम चाहते थे कि जिन्होंने सालों से इस गाने को पसंद किया है और जो पहली बार इसे सुन रहे हैं, दोनों ही इसे देखने का आनंद लें।'' वहीं, संगीतकार तनिष्क बागची ने कहा, ''किसी क्लासिक गाने को नए रूप में तैयार करना आसान नहीं होता। जब किसी पुराने लोकप्रिय गाने पर काम करते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी एहसास को सुरक्षित रखना होता है। इस गाने की धुन और आवाज की अपनी अलग विरासत है। मेरा पूरा ध्यान इसे नया साउंड देने पर था, लेकिन इस तरह कि लोगों को वही पुरानी यादें भी महसूस हों। मैं चाहता था कि यह आज के दौर के हिसाब से भी ताजा लगे और साथ ही लोगों को याद दिलाए कि यह गाना आखिर इतना क्लासिक क्यों बना।'' 'राणाजी 2.0' को टिप्स म्यूजिक ने रिलीज किया है। इस नए वर्जन में इला अरुण और अलका याज्ञनिक की आवाज को बरकरार रखा गया है। यह गाना आधुनिक संगीत और पुराने जादू का मेल बनकर सामने आया है। 'मुझको राणाजी माफ करना' साल 1995 में आई सुपरहिट फिल्म 'करण अर्जुन' का हिस्सा था। इस फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान, राखी, काजोल और ममता कुलकर्णी जैसे कलाकार नजर आए।

शीजान खान ने बदली डाइट, कहा- 'नॉनवेज के बिना भी बेहतर फिटनेस संभव'

विश्व केसरी ■

अभिनेता शीजान खान इन दिनों अपने शो 'गंगा मैया की बेटियां' में नजर आ रहे हैं। इस बीच अभिनेता ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में डाइट और फिटनेस को लेकर जानकारी दी। शीजान ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपनी खाने की आदतों में बड़ा बदलाव किया है और अब वह पूरी तरह शाकाहारी हो चुके हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए शीजान खान ने कहा, ''शूटिंग के दौरान कलाकारों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिसमें काफी एनर्जी खर्च होती है। मैं ऐसे में अपनी डाइट को लेकर काफी सतर्क रहता हूं। सही पोषण और संतुलित खान-पान के जरिए मैं अपनी फिटनेस बनाए रखता हूं। मैं अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा का खास ध्यान रखता हूं। मेरे लिए पनीर प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और प्रोटीन शेक भी मेरी रोज की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है।''

अभिनेता ने कहा, ''मुझे खाना बनाना काफी पसंद है। हालांकि, शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल के कारण ज्यादा समय किचन में नहीं बिता पाता। जब भी मौका मिलता है, तो मैं अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कुकिंग करता हूं।''

अभिनेता ने शाकाहारी बनने के सफर के बारे में भी विस्तार से बात की। उन्होंने बताया, ''पहले मेरे मन में धारणा थी कि अगर मैं चिकन और अंडे खाना छोड़ दूंगा तो मेरी मसल्स और फिटनेस पर असर पड़ेगा। मैंने खुद इस सोच को गलत साबित किया है। फिटनेस के लिए सिर्फ नॉनवेज खाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही मात्रा में पोषण लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है।''

उन्होंने कहा, ''अगर कोई व्यक्ति डाइट को सही तरीके से प्लान करता है तो शाकाहारी भोजन के साथ भी मसल्स बनाए रख सकता है। मुझे शाकाहारी बने हुए करीब छह महीने हो चुके हैं और यह पहली बार है, जब मैं सार्वजनिक रूप से इस बदलाव के बारे में बात कर रहा हूं। यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैंने महसूस किया कि सही तरीके से खाना खाने पर शाकाहारी डाइट के साथ भी फिटनेस और मसल्स को बनाए रखा जा सकता है।''

शीजान खान टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं। वह फिलहाल जी टीवी के शो 'गंगा मैया की बेटियां' में सिद्धू के किरदार में दिखाई दे रहे हैं।

अंजना सिंह की आगामी फिल्म 'शहीद की विधवा' का ट्रेलर 1 अगस्त को होगा रिलीज

भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अंजना सिंह अपनी आगामी फिल्म 'शहीद की विधवा' लेकर आ रही हैं। सोमवार को फिल्म के मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज की जानकारी शेयर की। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'भोजपुरी फिल्म 'शहीद की विधवा' का ट्रेलर 1 अगस्त को शनिवार सुबह 8 बजे बी4यू भोजपुरी यूट्यूब पर रिलीज हो रहा है। मेकर्स द्वारा पोस्ट पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन पर ट्रेलर रिलीज को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले मेकर्स ने फर्स्ट लुक और फिल्म से जुड़ी जानकारी शेयर की थी। हालांकि, फिल्म को लेकर विशेष जानकारी अभी मेकर्स ने नहीं दी है। यह फिल्म पारंपरिक 'सास-बहू' वाले घिसे-पिटे विषयों से हटकर एक गंभीर और मजबूत महिला किरदार पर आधारित होगी। इसमें एक शहीद के परिवार और उसकी पत्नी के जीवन की वास्तविक चुनौतियों को दिखाया जाएगा।फिल्म के जरिए अंजना सिंह पारंपरिक किरदारों से बाहर निकलकर एक सशक्त और अलग अंदाज में नजर आएंगी। इसमें अंजना सिंह एक देश के लिए जान कुर्बान करने वाले सैनिक की पत्नी (शहीद की विधवा) के संघर्ष और उसकी भावनात्मक यात्रा को पर्दे पर दिखाएंगी। प्रवीण गुडूरी द्वारा निर्देशित फिल्म का लेखन अरविंद तिवारी ने किया है जबकि इसके निर्माता संदीप सिंह और रामा प्रसाद हैं। भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अंजना सिंह अनोखी कहानियों और सशक्त महिला किरदारों की ओर बढ़ रही हैं।

लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ, मसाबा की बनाई ड्रेस पहनकर नीना गुप्ता ने किया मजेदार पोस्ट

विश्व केसरी ■

67 साल की उम्र में भी अभिनेत्री नीना गुप्ता अपने फैशन सेंस और दमदार अभिनय से लोगों को प्रभावित करती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातें साझा करती हैं। उन्होंने अपनी बेटी मसाबा गुप्ता के डिजाइन किए हुए आउटफिट को लेकर एक ऐसा मजेदार पोस्ट साझा किया है, जिसने फैंस का ध्यान खींचा।

नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं। उन्होंने बेटी मसाबा द्वारा डिजाइन की गई ब्लैक कलर की काफ्तान स्टाइल ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें उनका लुक काफी आकर्षक लग रहा है। उन्होंने अपने आउटफिट को लंबे ईयररिंग्स और स्टाइलिश ब्लैक बैग के साथ पूरा किया। वहीं, उन्होंने मेकअप को बेहद सिंपल रखा और बालों को बन में स्टाइल किया। अपने इस पोस्ट में नीना ने बेटी मसाबा के डिजाइन की जमकर तारीफ की।

नीना गुप्ता ने कैप्शन में लिखा, ''मैंने मसाबा की इस क्रिएशन को कई बार पहना है और हर बार यह नया और खास लगता है। मैं असल में खास की जगह सेक्सी कहना चाहती थी, लेकिन फिर लोग बोलेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ?'' नीना गुप्ता अक्सर अपनी बेटी मसाबा गुप्ता के काम की तारीफ करती नजर आती हैं। मसाबा फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। नीना गुप्ता लगातार फिल्मों और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काफी एक्टिव हैं। हाल ही में वह क्राइम थ्रिलर फिल्म 'वध 2' में नजर आई थीं। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को रिलीज हुई थी। इससे पहले वह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में दिखाई दी थीं। इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया था, जिसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिकाओं में थे। नीना गुप्ता आने वाले समय में ड्रामा फिल्म 'पचहत्तर का छोरा' में नजर आएंगी।

इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता रणदीप हुड्डा और संजय मिश्रा भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे।

फराह खान ने 'लॉक अप' को बताया अपना ड्रीम जॉब, बोलीं-अब तक का सबसे बेहतरीन रियलिटी शो

फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में को-होस्ट के तौर पर नजर आ रही हैं। उन्होंने इस शो के सफर को यादगार बताया। फराह ने कहा कि इस शो को होस्ट करना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा। इस शो को होस्ट करना एक ड्रीम जॉब जैसा है। फराह खान ने शो के बारे में बात करते हुए कहा, ''हर कोई जानता है कि मुझे रियलिटी टीवी का कितना शौक है। इसलिए जब मैं कहती हूं कि 'लॉक अप' अब तक देखा गया सबसे बेहतरीन रियलिटी शो है, तो मैं सच में ऐसा महसूस करती हूं। यह सिर्फ मेरे होस्ट करने की वजह से नहीं है, बल्कि एक दर्शक के तौर पर भी मुझे यह शो काफी पसंद है।''उन्होंने कहा, ''शो को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं जहां भी जाती हैं, लोग मुझसे 'लॉक अप' के बारे में बात करते हैं।

चाहे वह इंडस्ट्री के दोस्त हों, एयरपोर्ट पर मिलने वाले लोग हों, शूटिंग के दौरान मिलने वाले लोग हों या फिर फैंस, हर कोई इस शो से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है।

आमिर-शाहरुख के विज्ञापन से 'महारानी' तक, हुमा कुरैशी ऐसे बनीं बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस

विश्व केसरी ■

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। कभी वह दिल्ली में थिएटर करती थीं। उन्होंने शुरुआत विज्ञापनों से की और एक समय ऐसा भी आया, जब वह आमिर खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगीं। यही सफर आगे चलकर उन्हें 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' तक ले आया और फिर 'महारानी' से नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। हुमा कुरैशी का जन्म 28 जुलाई 1986 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता, सलीम कुरैशी, दिल्ली में रेस्टोरेंट चलाते हैं, जबकि उनकी मां, अमीना कुरैशी, गृहिणी हैं। हुमा का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ बढ़ा और उन्होंने थिएटर ग्रुप 'एक्ट 1' के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने थिएटर के दौरान अभिनय की बारीकियां सीखीं और यहीं से उनके अंदर एक्ट्रेस बनने का सपना मजबूत हुआ। साल 2008 में हुमा सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंचीं। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विज्ञापनों में काम करना शुरू किया। इसी दौरान वह कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आईं। उन्होंने आमिर खान के साथ मोबाइल और शाहरुख खान के साथ एक पेंट ब्रांड के विज्ञापन में काम किया। इन विज्ञापनों ने पहचान दिलाई और उनकी एक्टिंग को लोगों ने नोटिस किया। हुमा की किस्मत तब बदली जब एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान निर्देशक अनुराग कश्यप की नजर उन पर पड़ी। अनुराग कश्यप ने उनकी एक्टिंग देखकर अपनी फिल्म में मौका देने का फैसला किया। इसके बाद साल 2012 में हुमा ने फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में उन्होंने मोहसीना हमीद का किरदार निभाया था। छोटे शहर की लड़की के किरदार में हुमा ने ऐसी जान डाली कि दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने उनकी तारीफ की। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के बाद हुमा के करियर ने तेजी पकड़ ली। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में नामांकन मिला। इसके बाद उन्होंने 'लव शव ते चिकन खुराना', 'एक थी डायन', 'डेढ़ इश्किया', 'बदलापुर' और 'जॉली एलएलबी 2' जैसी फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में उन्होंने अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता साबित की। हुमा ने सिर्फ हिंदी फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने मराठी फिल्म 'हाइवे', तमिल फिल्म 'काला' और 'वलिमाई' जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। साल 2021 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म 'आर्मी ऑफ द डेड' से इंटरनेशनल सिनेमा में भी कदम रखा। अलग-अलग भाषाओं और इंडस्ट्री में काम करके उन्होंने खुद को एक बहुमुखी कलाकार के रूप में साबित किया।

राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिखाया आईना बौखलाए मुल्क की यूएन से अपील- डालें दबाव

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भारत के रक्षा मंत्री ने कारगिल दिवस पर पाकिस्तान को अपनी हद में रहने की नसीहत दी। इस्लामाबाद इससे बेचैन हो उठा है। नतीजतन उसने हमेशा की तरह एक बयान जारी कर दुनिया से दखल देने की गुहार लगाई है। सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राजनाथ सिंह की टिप्पणी को 'उकसावे वाली और गैर जिम्मेदाराना करार दिया।' रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर जो आईना दिखाया उसी पर पड़ोसी मुल्क को आपत्ति है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया। एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, 'पाकिस्तान सरकार जम्मू-कश्मीर विवाद के संदर्भ में भारतीय रक्षा मंत्री की उकसावे वाली और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती है।'

इसमें आगे कहा गया, 'उनका (राजनाथ सिंह) बयान जम्मू-कश्मीर विवाद से जुड़े तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करता है। यह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालती है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देते हुए भारत पर दबाव बनाना चाहिए।' पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्तक्षेप की गुहार लगाई। इसमें आगे कहा गया, 'पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करता है कि वह भारत पर दबाव डाले, उसके व्यवहार पर ध्यान दे और उसे जवाबदेह ठहराए।'

वहीं, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की 'बयानबाजी के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी स्थिति को बदलने की लगातार कोशिशें तथ्यों को नहीं बदल सकतीं और हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे।' आसिफ ने कहा कि राजनाथ सिंह के बयानों से क्षेत्रीय शांति या सार्थक बातचीत में कोई मदद नहीं मिलती।

दरअसल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कारगिल वॉर मेमोरियल के मंच से पाकिस्तान को संकेत दिया था कि उसकी तरफ जो कश्मीर है, उस पर उसका कब्जा पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'जहां तक कश्मीर के विवाद या इस मुद्दे पर बातचीत का सवाल है, तो हमारी मंशा साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी भी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी।'

गिलगित-बाल्टिस्तान से पंजाब तक बारिश का कहर, पाकिस्तान में बढ़ा मौतों का आंकड़ा

विश्व केसरी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार को बताया कि 26 जून से शुरू हुई मानसून बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। मानसून से जुड़ी घटनाओं में 344 लोग घायल हुए हैं।

पाकिस्तान के समाचार चैनल समा टीवी के अनुसार, 447 घरों को नुकसान पहुंचा है और 269 पशुओं की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में पंजाब में सात, सिंध में दो और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) और खैबर पख्तूनख्वा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

समा टीवी ने बताया कि इस दौरान 25 लोग घायल हुए, जिनमें पंजाब के 20, खैबर पख्तूनख्वा के तीन और सिंध के दो लोग शामिल हैं। एनडीएमएने लोगों, खासकर कमजोर और जोखिम वाले इलाकों में रहने वालों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और मानसून बारिश के जारी रहने के दौरान अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। पाकिस्तान के अखबार डॉन के अनुसार, इन मौतों की वजह डूबना और इमारतों का गिरना रही, जबकि छत गिरने और बिजली का करंट लगने से लोग घायल हुए। लाहौर की गढ़ी शहू रेलवे कॉलोनी, बॉबी प्लाजा, सग्गियन पिंड और काहना में छत गिरने की चार अलग-अलग घटनाओं में एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। पंजाब के कसूर जिले में अड्डा ढिंग शाह के पास एक घर की छत गिरने से दो लोगों, जिनमें एक पुरुष और एक बच्चा शामिल थे, की मौत हो गई। इस घटना में एक महिला और दो बच्चों समेत तीन अन्य लोग घायल हुए।

फैसलाबाद में भारी बारिश के कारण एक घर की छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि गुजरांवाला की पठान कॉलोनी के पास खेतों में जमा बारिश के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई।

संक्षिप्त खबर

ईरान के जहाज पर यूक्रेन के हमले का जवाब देना जरूरी : विदेश मंत्री अब्बास अराघची

विश्व केसरी

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि कैस्पियन सागर में ईरान के कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन के हमले को बिना जवाब दिए ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता।

ईरानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि उन्होंने इजरायल के कहने पर यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन करके यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने का आदेश दिया। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि उन्होंने शनिवार और रविवार को यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख काजा कैलास और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोन पर हुई बातचीत में स्पष्ट कर दिया था कि कीव में मुफ्तखोर ने जो किया, उसे बिना जवाब दिए नहीं जाने नहीं दिया जा सकता। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, अराघची ने शनिवार को ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास के साथ एक फोन कॉल में यह बात कही। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। बयान के अनुसार, अराघची ने यूक्रेनी हमले की निंदा की और ईयू, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसके गुनाहगारों और समर्थकों को जिम्मेदार ठहराने की अपील की। इसमें आगे कहा गया कि दोनों पक्षों ने होर्मुज स्ट्रेट में हो रहे घटनाक्रम पर भी बात की और क्षेत्रीय तनाव को मैनेज करने के लिए डिप्लोमैटिक पहल की जरूरत पर जोर दिया।

अराघची ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से फोन पर की बात

विश्व केसरी

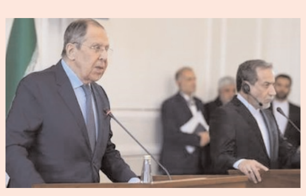

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव ने रविवार को एक फोन कॉल के दौरान कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन के हमले की निंदा की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अराघची ने यूक्रेन के इस कदम की निंदा करते हुए इसे खतरनाक और यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों का साफ उल्लंघन बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगा। बयान में आगे कहा गया कि लावरोव ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाला एक्शन और रूस और ईरान के बीच ट्रेड रूट के लिए खतरा बताया। बयान के मुताबिक, दोनों मंत्रियों ने तेहरान द्वारा अमेरिका के 'वादों को तोड़ने और होर्मुज स्ट्रेट पर असुरक्षा थोपने' के बाद हुए क्षेत्रीय डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। इसके अलावा, विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि कैस्पियन सागर में ईरान के कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन के हमले को बिना जवाब दिए ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ईरानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि उन्होंने इजरायल के कहने पर यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन करके यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने का आदेश दिया।

अमेरिका के सिएटल में फूड फेस्टिवल में हुई गोलीबारी कई लोग घायल और जांच में जुटी पुलिस

विश्व केसरी

सिएटल। अमेरिका के सिएटल से सामूहिक गोलीबारी की जानकारी सामने आई है। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका में सिएटल सेंटर के पास सालाना बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। सिएटल पुलिस ने रविवार रात (स्थानीय समय) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'पुलिस शूटिंग की जांच कर रही है। कई लोग शूटिंग के शिकार हुए हैं। सिएटल सेंटर में गोलियां चलीं। और जानकारी जल्द ही आएगी। कृपया उस इलाके से बचें।'

शूटिंग से फूड फेस्टिवल में आए विजिटर्स में घबराहट फैल गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर इमरजेंसी कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि, घायल हुए लोगों की संख्या तुरंत नहीं बताई गई। मामले के आरोपी या किसी संदिग्ध को अब तक हिरासत में लिया गया है या नहीं, इसे लेकर पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सिएटल सेंटर मनोरंजन और संस्कृति का केंद्र है, जिसमें क्लाइमेट प्लेज एरिना और मशहूर स्पेस नीडल जैसे कई आकर्षण की चीजें हैं। डब्ल्यूबीएएल-टीवी के अनुसार, उस समय वेन्यू पर बाइट ऑफ सिएटल हो रहा था, जो शहर के सबसे लंबे समय से चल रहे और सबसे पसंदीदा फूड फेस्टिवल में से एक है। अमेरिकी मीडिया सीएनएन की एक रिपोर्ट में कोमो नाम की एक एफिलिएट कंपनी का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार, फूड फेस्टिवल में मौजूद कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने वेन्यू के अंदर 7-8 गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। पुलिस ने गिरफ्तारी या किसी संभावित वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जांच चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है। यह घटना 19 जुलाई को अमेरिका के एरिजोना राज्य के टक्सन में रात भर हुई मास शूटिंग में संदिग्ध समेत दस लोगों के घायल होने की एक और घटना के ठीक बाद हुई है।

हिज्बुल्लाह का साथ देना ईरान की रणनीतिक नीति का हिस्सा : मोजतबा खामेनेई

विश्व केसरी

तेहरान। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद मोजतबा हुसैनी खामेनेई ने रविवार को हिज्बुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम को लिखे एक पत्र में कहा कि हिज्बुल्लाह के लिए ईरान का समर्थन एक 'रणनीतिक जिम्मेदारी' है।

हिज्बुल्लाह प्रमुख के उस पत्र के जवाब में, जिसमें उन्होंने ईरान के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई थी, मोजतबा खामेनेई ने संगठन की तारीफ की। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) के अनुसार, उन्होंने कहा कि हिज्बुल्लाह इजरायल की 'भयंकर आक्रामकता' के खिलाफ 'एक मजबूत चट्टान की तरह' खड़ा है।

खामेनेई ने अपने पत्र में कहा, 'इस्लामी क्रांति के महान शहीद नेता इमाम सैयद अली खामेनेई (ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखें) की तय की गई नीति के अनुसार, इस्लामी गणराज्य ईरान इन दबे-कुचले लेकिन शक्तिशाली मुजाहिदीन की रक्षा को अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है।' उन्होंने कहा कि हिज्बुल्लाह की ओर से भेजा गया पत्र प्रशंसा और सम्मान के योग्य है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मोजतबा खामनेई ने कहा था कि अमेरिका की ओर से ईरान के साथ हाल ही में किए गए शांति समझौते (एमओयू) का उल्लंघन एक बार फिर साबित करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर बेकार और अमान्य हैं। उन्होंने यह बयान ईरानी लोगों के लिए जारी एक संदेश में दिया, जिसे वहां के मीडिया ने प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका की ओर से बार-बार एमओयू का उल्लंघन ने फिर से यह साबित कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई कीमत नहीं है।

फ्रांस में जंगलों की आग से संकट गहराया, स्पेन के पीएम बोले- 'जलवायु संकट का असर झेल रहा देश'

विश्व केसरी

मैड्रिड/पेरिस। फ्रांस और स्पेन में भीषण जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मी लगातार जूझ रहे हैं। इस बीच स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि स्पेन और पूरा आइबेरियन प्रायद्वीप जलवायु संकट के गंभीर प्रभाव झेल रहा है। देश की तीसरी उप-प्रधानमंत्री और पारिस्थितिकीय परिवर्तन मंत्री सारा आगेसेन ने सोमवार से चौथे हीटवेव की आशंका के बीच अधिकतम सतर्कता बरतने की अपील की।

दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के गिरोंद क्षेत्र में शनिवार रात तेज हवाओं के कारण आग बुझाने के प्रयासों में काफी मुश्किलें आईं। यह आग अब तक पेरिस के क्षेत्रफल से लगभग चार गुना बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है, और इसके चलते करीब 2.2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मंगलवार से फ्रांस में एक और हीटवेव शुरू हो सकती है, जिसके दौरान कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। फ्रांस और स्पेन में जंगलों की आग के कारण अब तक करीब 3.75 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इनमें फ्रांस में लगभग 2.6 लाख और स्पेन में इस सप्ताह 1.16 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

बोर्दो के मेयर थॉमस काजेनाव ने बताया कि गिरोंद की आग शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर महानगरीय क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गई है। हालांकि फिलहाल पूरे शहर को खाली कराने की कोई योजना नहीं है।

स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को कहा कि रातभर आग की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही और कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं पूरी क्षमता के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

नेपाल में फिर सड़कों पर उतरे जेन-जी, एमबीएस पेपर लीक को लेकर सड़कों पर दिखा छात्रों का आक्रोश

विश्व केसरी

काठमांडू। नेपाल की जेन-जी एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुकी है। नेपाल में परीक्षा में हुए पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से नेपाल की सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। मार्च 2026 में बालेंद्र उर्फ बालेन शाह की सरकार के आने के बाद यह दूसरी बार है जब युवा सड़कों पर उतरे हैं। वहीं, नेपाल पुलिस का कहना है कि पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टर का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है।' बालेन शाह की सरकार ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का पेपर लीक होने के कुछ ही दिनों बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। भारत में हुए व्यापक प्रदर्शन के बीच नेपाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ही एक गड़बड़ सामने आई है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज (एमबीएस) के पहले सेमेस्टर का पेपर 24 जुलाई को लीक हुआ था, उसी दिन भारत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दिया था। यह घटना 25 जुलाई को सामने आई, जब सबूत मिले कि परीक्षा के दौरान पेपर ऑनलाइन उपलब्ध था। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, परीक्षा शुरू होने के ठीक पांच मिनट बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर सर्कुलेट हो गया, जिससे यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दौरान सुरक्षा और गोपनीयता प्रणाली में गंभीर कमियां सामने आईं।

कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करना हमारा लक्ष्य : दक्षिण कोरिया

विश्व केसरी

सोल। दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री ने सोमवार को दोहराया कि वह कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने के लक्ष्य पर कायम है। मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 'यथार्थवादी और व्यावहारिक' समाधान तलाशने की है।

मंत्रालय के प्रवक्ता यून मिन-हो ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर परमाणु हथियारों से मुक्त कोरियाई प्रायद्वीप के लक्ष्य को हासिल करने की हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।'

उन्होंने कहा, 'उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे को लेकर गंभीरता देखते हुए हमारी प्राथमिकता उसके परमाणु कार्यक्रमों को रोकने और इस दिशा में व्यावहारिक एवं प्रभावी समाधान तलाशने की है।' योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, यून की यह टिप्पणी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो-जोंग के उस बयान के बाद आई, जिसे सोमवार को कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने जारी किया। किम यो-जोंग ने शनिवार को मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान को खारिज कर दिया।

सिएटल शूटिंग में अब तक दो लोगों की मौत की हुई पुष्टि

विश्व केसरी

सिएटल। अमेरिका के सिएटल में फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम सिएटल सेंटर में बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए।

सिएटल फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चार और लोगों, एक दो साल का लड़का, एक 23 साल के युवा और दो महिलाओं को हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर ले जाया गया।

मामूली चोटों वाली 40 साल की एक महिला का मौके पर ही इलाज किया गया और उसे अस्पताल ले जाने से मना कर दिया गया। हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर ने कहा कि एक महिला की हालत गंभीर है और उसकी सर्जरी हो रही है, जबकि अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों की हालत ठीक है।

गोलीबारी के तुरंत बाद पुलिस और इमरजेंसी क्रू ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली करा दिया। अधिकारियों ने लोगों से कहा कि जांच जारी रहने तक वे सिएटल सेंटर न जाएं। सिएटल सेंटर मनोरंजन और संस्कृति का केंद्र है, जहां क्लाइमेट प्लेज एरिना और मशहूर स्पेस नीडल जैसे कई आकर्षण हैं। डब्ल्यूबीएएल-टीवी के अनुसार, उस समय वेन्यू पर बाइट ऑफ सिएटल हो रहा था, जो शहर के सबसे लंबे समय से चल रहे और सबसे पसंदीदा फूड फेस्टिवल में से एक है। अमेरिकी मीडिया सीएनएन की एक रिपोर्ट में कोमो नाम की एक एफिलिएट कंपनी का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार, फूड फेस्टिवल में मौजूद कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने वेन्यू के अंदर 7-8 गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे।

पुलिस ने गिरफ्तारी या किसी संभावित वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जांच चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है। यह घटना 19 जुलाई को अमेरिका के एरिजोना राज्य के टक्सन में रात भर हुई मास शूटिंग में संदिग्ध समेत दस लोगों के घायल होने की एक और घटना के ठीक बाद हुई है।

टक्सन पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह शूटिंग 19 जुलाई को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 2 बजे एरिजोना के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर टक्सन के डाउनटाउन के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई। स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ऑफिसर गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत उधर की तरफ दौड़े> जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने एक आदमी को भागते हुए देखा। अधिकारियों ने संदिग्ध को कई बार ऑर्डर दिए, जिसके बाद एक यूनिफॉर्म पहने अधिकारी ने उसे गोली मार दी।

कोलकाता में प्रदर्शन : पुलिस और मीडिया पर हमले के मामले में दो अन्य गिरफ्तार

विश्व केसरी■

कोलकाता। नीट पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अन्य घोटालों के खिलाफ 24 जुलाई को कोलकाता में निकाली गई विरोध रैली के दौरान पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर हुए हमले और हिंसा के मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी।

इससे पहले, शनिवार शाम से रविवार दोपहर तक हिंसा के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पहचान कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

सोमवार सुबह गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान दक्षिण-पूर्व कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके के करया निवासी वकार आज़म (35) और कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके गार्डन रीच निवासी जावेद अख्तर (32) के रूप में हुई है।

दोनों आरोपियों को आज बाद में कोलकाता की निचली अदालत में पेश किया जाएगा। सरकारी वकील अदालत से उनकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे।

इन सभी आरोपियों के खिलाफ हाल ही में लागू किए गए 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026' के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछले हफ्ते इसकी घोषणा की थी। इस कानून में असामाजिक और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। 24 जुलाई की दोपहर नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और कुछ छात्र व युवा संगठनों की संयुक्त रैली के दौरान तनाव फैल गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिसकर्मियों पर कांच की बोतलें, पत्थर, ईंटें, बांस की लाठियां और जूते फेंके। इस घटना की कवरेज कर रहे कुछ मीडियाकर्मी भी प्रदर्शनकारियों के एक समूह द्वारा फेंकी गई चीजों की चपेट में आकर घायल हो गए। इनमें से कुछ मीडियाकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रविवार दोपहर को मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 14 लोगों में से कोई भी छात्र नहीं था।

उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर पहचान के बाद गिरफ्तार किए गए लोग कथित तौर पर कट्टरपंथी थे। उनके अनुसार, शुक्रवार को विरोध रैली में शामिल होने के बाद छात्र कार्यकर्ताओं का रूप धारण कर शहर में अशांति फैलाना उनका मुख्य उद्देश्य था।

ई20 विवाद : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि केस

विश्व केसरी■

मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फिलहाल, हाईकोर्ट ने गडकरी की याचिका को मंजूर किया है और अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई तय की है।

यह मामला एआई से बने कथित डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें नितिन गडकरी और उनके परिवार को ई20 एथेनॉल पॉलिसी से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने याचिका में विवादित सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है।

नितिन गडकरी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'मेटा' (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) और 'एक्स' को प्रतिवादी बनाया है। याचिका के अनुसार, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया है कि

गडकरी और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की एथेनॉल पॉलिसी से आर्थिक लाभ हुआ है। हालांकि, इन आरोपों को केंद्रीय मंत्री ने बेबुनियाद और झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप जनता को गुमराह करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़े गए हैं। अपनी याचिका में गडकरी ने कहा कि ई20 एथेनॉल पॉलिसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में है। इस वजह से ये आरोप तथ्यों के आधार पर गलत हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के जरिए उन्हें सरकारी नीतिगत फैसलों और कथित निजी लाभ से गलत तरीके से जोड़कर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट से डिजिटल प्लेटफॉर्म से डीपफेक वीडियो और संबंधित पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश देने की मांग की है।

उन्होंने ऐसी सामग्री के आगे प्रसार, शेयर करने और प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की भी मांग की। साथ ही, उन्होंने इसे तैयार और प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। बता दें कि 'ई20 नीति' केंद्र सरकार की व्यापक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ई20 ईंधन में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। इसका मकसद आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना, गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को घटाना और घरेलू बायो-फ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देना है।

संक्षिप्त खबर

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करने वाली 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या की

विश्व केसरी■

अमरावती। आंध्र प्रदेश के पोलावरम जिले में एक सरकारी स्कूल में 'मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग' के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू के साथ मंच साझा करने वाले 10वीं कक्षा के एक छात्रा ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। रामपाचोडावरम के जिला परिषद हाई स्कूल में 'मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग 4.0 के दौरान मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर बोलने वाली मुर्रम शिवानी ने इर्लापल्ली गांव में अपनी दादी के घर पर आत्महत्या कर ली। लड़की ने हाथ से लिखा एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने माता-पिता के सपने पूरे न कर पाने के लिए उनसे माफी मांगी। उसके इस कठोर कदम का कारण पता नहीं चल सका। लड़की के माता-पिता कोरुकोंडा के एक होटल में काम करते हैं, जबकि वह अपनी दादी के साथ रहती थी और रामपाचोडावरम के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पढ़ाई में होनहार मानी जाने वाली शिवानी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में 'मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग 4.0 में अपने भाषण से सबका ध्यान खींचा था। उसने कड़ी मेहनत करने और अगले साल 'शाइनिंग स्टार अवॉर्ड' जीतने की इच्छा जताई थी। भाषण के बाद, मुख्यमंत्री ने उसे बुलाया और अपने बगल में बिठाया। उन्होंने उससे बातचीत भी की थी। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि मुर्रम शिवानी के निधन से उन्हें गहरा दुख हुआ है।

ड्रग तस्कर ने कार से तीन पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, कांस्टेबल महेंद्र यादव का पैर फ्रैक्चर

विश्व केसरी■

हैदराबाद। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग (एच-एनईडब्ल्यू) के नारकोटिक्स अभियान के दौरान एक संदिग्ध ड्रग तस्कर ने भागने की कोशिश की। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि इस दौरान उसने अपनी कार से तीन पुलिसवालों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए। रविवार को शहर के बीचों-बीच एबिड्स इलाके के तिलक रोड पर यह घटना हुई। पुलिस के मुताबिक, ड्रग तस्करी की जानकारी मिलने पर (एच-एनईजब्ल्यू) टीम ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए तिलक रोड पर एक अभियान चलाया। पुलिस टीम ने संदिग्ध ड्रग पेडलर को एक दुकान के पास एक कार में सप्लाई करने के लिए आते हुए देखा। कार में बैठे आदमी ने एक पैकेट दूसरे आदमी को दे दिया। पुलिसवालों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पैकेट लेने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। जब (एच-एनईजब्ल्यू) टीम ने कार को रोका तो गाड़ी चला रहे शख्स ने कार को एक तरफ पार्क करके नीचे उतरने का नाटक किया, लेकिन अचानक गाड़ी तेज कर दी और भागने की कोशिश में पुलिसवालों को टक्कर मार दी। पुलिस कांस्टेबल महेंद्र यादव के पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने भाग रहे ड्रग पेडलर का पीछा किया और उसे अफजल गंज के पास हिरासत में ले लिया। इस दौरान, इंस्पेक्टर श्रीकांत और एक दूसरे कांस्टेबल वामसीधर को भी मामूली चोटें आईं।

ई-20 के खिलाफ 'आप' का अभियान तेज, अरविंद केजरीवाल ने की युवाओं से राष्ट्रीय टाउनहॉल में शामिल होने की अपील

विश्व केसरी■

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ई 20 नीति को लेकर एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के युवाओं से एकजुट होकर इस मुद्दे पर अपनी राय रखने और आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है।

केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह युवाओं की एकजुट आवाज के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह ई 20 के मुद्दे पर भी देश के युवाओं को संगठित होकर अपनी बात मजबूती से रखनी होगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा, 'देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ई 20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी।'

उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि यह केवल किसी एक संगठन या

राजनीतिक दल का विषय नहीं है, बल्कि देश के भविष्य और आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान में भाग लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से आम आदमी पार्टी की ओर से 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई 20' का आयोजन किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम 1 अगस्त 2026 (शनिवार) को सुबह 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में आयोजित होगा। पार्टी ने बताया कि इस कार्यक्रम में देशभर से छात्र, युवा, विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, उनके लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होने की भी व्यवस्था की गई है।

पार्टी का कहना है कि इस टाउनहॉल के माध्यम से ई 20 नीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर खुलकर चर्चा होगी और लोगों की राय सुनी जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को अपनी चिंताओं और सुझावों को साझा करने का मंच उपलब्ध कराना है।

आम आदमी पार्टी ने देशभर के युवाओं से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है। पार्टी का दावा है कि यदि नागरिक संगठित होकर अपनी बात रखेंगे तो सरकार को भी जनता की भावनाओं और चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

प्रदर्शन से सुर्खियों में आई रिया अहीर ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई

विश्व केसरी■

मुंबई। मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े होकर चर्चा में आई 27 वर्षीय मॉडल रिया अहीर ने अब महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। रिया की ओर से आरोप लगाया गया है कि वायरल वीडियो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग, उत्पीड़न और अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए रिया ने कहा, 'मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। ऑनलाइन गालियां दी जा रही हैं और चरित्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल यह सब सोशल मीडिया पर हो रहा है, लेकिन यह आगे चलकर और गंभीर रूप ले सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे माता-पिता को इसकी वजह से किसी तरह की परेशानी झेलनी पड़े। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि पूरी दुनिया देख रही है। हमें शर्मिंदा करने की कोशिश के लिए हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, और हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे।' रिया ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में, स्टूडेंट्स के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ

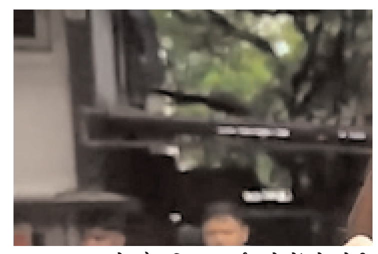

आवाज उठाने के लिए कई लोगों ने मेरी तारीफ की है। मैंने पूरी दुनिया को यह मैसेज भी दिया है कि हम अब और नहीं झुकेंगे। जब हम झुकने की कोशिश नहीं करते, तो कुछ लोग हमें घुटनों पर लाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो मेरे बारे में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई कोशिशें की हैं, लेकिन मैं उन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दूंगी क्योंकि ये सभी दावे झूठे हैं।' उन्होंने कहा, 'ऐसी अफवाहें हैं कि मेरी पर्सनल इमेज लीक हो गई हैं या कोई एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है, जिसमें मेरी तस्वीरें हैं। हम सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइन्स हैं। मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है, तो हमारे पास सच या झूठ को वेरिफाई करने के तरीके हैं।

महिला तस्करी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, दुर्गापुर से कारोबारी गिरफ्तार

विश्व केसरी■

कोलकाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी गुलाम रजा के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया।

रजा पर मानव तस्करी विशेष रूप से महिलाओं की तस्करी में शामिल होने का आरोप है।

बिहार के मुजफ्फरपुर के मूल निवासी रजा करीब तीन साल पहले अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ दुर्गापुर आकर बस गए थे। उन्होंने दुर्गापुर स्टील प्लांट क्षेत्र के पास एक मकान खरीदा था। जांच में पता चला कि रजा ट्रैवल एजेंसी का भी कारोबार करता था। इस एजेंसी के जरिए वह राज्य के बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को विदेश में नौकरी दिलाने का इंतजाम करता था। हालांकि, प्रवासी मजदूरों को विदेश

खासकर पश्चिम एशिया के देशों में नौकरी दिलाने की आड़ में उस पर एक ऐसे गिरोह से जुड़े होने का आरोप है, जो लोगों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने का काम करता था।

आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय की टीम के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी के छह अधिकारी, जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थीं, जब रजा के घर छापेमारी करने पहुंचे, तब शुरुआती तौर पर इस कार्रवाई की वजह स्पष्ट नहीं थी। हालांकि, उसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई की वजह साफ हो गई।

जांच में पता चला कि रजा खुद भी उन देशों में अक्सर जाता था, जहां वह प्रवासी मजदूरों को भेजता था। उस पर इन देशों में युवा महिलाओं की तस्करी करने का भी आरोप है। आखिरकार, छापेमारी और तलाशी के दौरान लंबी पूछताछ के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रजा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अधिकारी उसका चेहरा ढंककर उसे घर से बाहर लेकर आए।

अमृतसर में हथियार और हेरोइन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

विश्व केसरी■

अमृतसर। पंजाब पुलिस ने सीमा पार से अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर करते हुए बताया कि यह कार्रवाई सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पांच आधुनिक पिस्तौल, 2.015 किलोग्राम हेरोइन और नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित पांच लाख रुपये बरामद किए गए हैं।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सीमा पार से अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे।

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह के तार किन लोगों से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान गिरोह के आगे और पीछे के संपर्कों का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा तस्करी के इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस ने कहा कि राज्य में अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने दोहराया कि वह सीमा पार से होने वाली तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने और पंजाब को सुरक्षित और नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

डॉक्टर बनने का सपना टूटा, अहिल्यानगर की छात्रा अंकिता सांगले ने की आत्महत्या

विश्व केसरी■

अहिल्यानगर। देश में नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। कर्जत तालुका के जलालपुर गांव की छात्रा अंकिता सुरेश सांगले ने रविवार को आत्महत्या कर ली। परिवार के अनुसार, अंकिता ने नीट री-एग्जाम में कम अंक आने के सदमे में यह कदम उठाया।

सुसाइड नोट में अंकिता ने लिखा कि उसे कम अंक मिलने से डॉक्टर बनने का सपना टूट गया है। नोट में उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आत्महत्या के लिए उसके अभिभावकों को जिम्मेदार न

ठहराया जाए। अभिभावकों ने बताया कि अंकिता को पहली बार नीट परीक्षा में अच्छे अंक आए थे लेकिन पेपर लीक की घटना के कारण री-एग्जाम कराना पड़ा। री-नीट में कम अंक मिलने के बाद वह लगातार तनाव में रहने लगी थी। परिवार का कहना है कि वह डॉक्टर बनने की बहुत उत्सुक थी और परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह लगी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही रिश्तेदार अंकिता के घर पहुंचने लगे हैं। आस-पास के लोग भी दुख व्यक्त कर रहे हैं।

मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का आना शुरू

विश्व केसरी■

मुजफ्फरनगर। जैसे-जैसे सालाना कांवड़ यात्रा जोर पकड़ रही है भगवान शिव के भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचने लगे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान जिले से गुजरकर अलग-अलग शिव मंदिरों तक जाने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है।

जिला प्रशासन और पुलिस ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के व्यापक इंतजाम किए हैं।

खूबसूरती से सजाई और कलात्मक ढंग से डिजाइन की गई कांवड़ें मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंचने लगी हैं, जिन्हें देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

मेरठ जिले के रहने वाले ऐसे ही एक कांवड़िया भोले, अपनी कांवड़ और पवित्र गंगा जल लेकर शिव चौक पहुंचे।

मुजफ्फरनगर की युवतियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मानित किया और उनकी कांवड़ की अनोखी सजावट की तारीफ की।

शिव भक्त आदेश ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 'हमने 23 जुलाई को पवित्र जल इकट्ठा किया था। हम 10 अगस्त तक अपने इलाके में पहुंच जाएंगे और 13 अगस्त को अपने मंदिर में गंगा जल चढ़ाएंगे। कांवड़ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम बहुत अच्छे हैं और हमें कोई परेशानी नहीं हुई।' राजस्थान के रहने वाले एक अन्य भक्त दीपक ने कहा, 'मैंने हरिद्वार में हर की पौड़ी से पवित्र जल इकट्ठा किया और मैं इसे मेरठ के काली पलटन स्थित अघोरनाथ मंदिर ले जा रहा हूं। यहां सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है और इंतजाम बेहतरीन हैं।' कांवड़ यात्रा आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को सावन के पवित्र महीने के पहले दिन शुरू होगी और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के अवसर पर समाप्त होगी। इस साल की यात्रा 13 दिनों तक चलेगी, जिसके दौरान लाखों भक्तों के हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों से पवित्र गंगा जल इकट्ठा करने और उसे उत्तर भारत भर के शिव मंदिरों तक ले जाने की उम्मीद है।

सावन शिवरात्रि को कांवड़ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस शुभ अवसर पर, कांवड़िए शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर जलाभिषेक करते हैं। इस साल यह रस्म 11 अगस्त को निभाई जाएगी, जो यात्रा के समापन और भक्तों की धार्मिक विधियों के पूरे होने का प्रतीक होगी।

विश्व केसरी

सीएमएफआरआई ने लॉन्च किया 'शार्क अवेयर' ऐप

संकटग्रस्त समुद्री जीवों के संरक्षण को मिलेगी मजबूती

विश्व केसरी ■

कोच्चि। समुद्री संरक्षण और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) ने दो तकनीक आधारित मंच शुरू किए हैं। इनका उद्देश्य संकटग्रस्त शार्क और रे मछलियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

सोमवार को संस्थान ने 'शार्क अवेयर' मोबाइल ऐप और एक इंटरैक्टिव ई-लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया। यह समुद्री जैव विविधता के संरक्षण को मजबूत करने और इस क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य के मत्स्य पालन मंत्री वी.ई. अब्दुल गफूर ने कोच्चि स्थित सीएमएफआरआई मुख्यालय में इन दोनों पहलों की शुरुआत की।

नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (एनएफडीबी) की आर्थिक सहायता से तैयार किए गए इन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मछुआरों, मत्स्य विभाग के अधिकारियों, वन्यजीव संरक्षण एजेंसियों, शोधकर्ताओं और छात्रों को शार्क और रे मछलियों की संरक्षित प्रजातियों की सही पहचान करने में मदद करना है। इससे संरक्षण से जुड़े नियमों का बेहतर तरीके से पालन सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

यह मोबाइल ऐप वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (2022 में संशोधित) की अनुसूची-1, अनुसूची-2 और अनुसूची-4 में शामिल संरक्षित शार्क और रे मछलियों की प्रजातियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है।

प्रजातियों की पहचान के अलावा यह ऐप उपयोगकर्ताओं को इन समुद्री जीवों से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी, उन्हें मिली कानूनी सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों और इनके संरक्षण के पर्यावरणीय महत्व के बारे में आसान भाषा में जानकारी देता है।

सीएमएफआरआई के फिनफिश मत्स्य पालन विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. लिवी विल्सन, जिन्होंने इस परियोजना का नेतृत्व किया, ने बताया कि यह ऐप समुद्री मत्स्य पालन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों के बीच जानकारी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, 'यह ऐप लोगों को संरक्षित शार्क और रे मछलियों की सही पहचान करने में मदद करेगा। साथ ही, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने और इन प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूत करेगा।

उम्मीद है कि यह ऐप जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। इसके साथ एक संवादात्मक ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल भी तैयार किया गया है, जिसकी मदद से उपयोगकर्ता प्रश्नोत्तरी, तुरंत मूल्यांकन और अपनी सीखने की प्रगति की जानकारी के जरिए अपनी सुविधा के अनुसार प्रशिक्षण ले सकेंगे।

यह डिजिटल मंच वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, लुप्तप्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी सम्मेलन (साइट्स), प्रजातियों की पहचान करने के तरीकों और संरक्षित शार्क तथा रे मछलियों के संरक्षण के महत्व से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है।

यह पहल दिखाती है कि सीएमएफआरआई टिकाऊ मत्स्य पालन और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर लगातार जोर दे रहा है।

संस्थान का मानना है कि वैज्ञानिक और कानूनी जानकारी को आसान तरीके से उपलब्ध कराने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। इससे अधिक लोग संरक्षण के प्रयासों में भाग लेंगे, नियमों का पालन करेंगे और समुद्री जीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

भारत ने हेपेटाइटिस रोकथाम अभियान तेज किया

विश्व केसरी ■

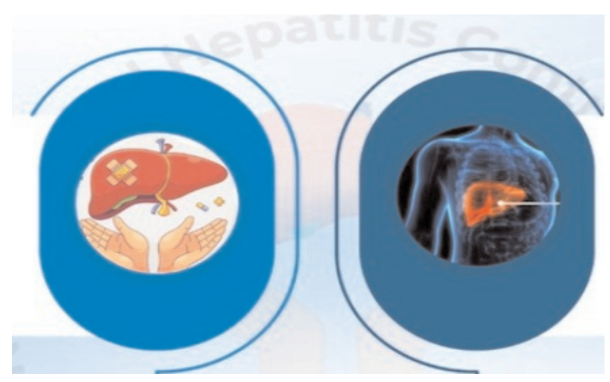

नई दिल्ली। भारत वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 'राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत जांच, मुफ्त परीक्षण और इलाज की सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को भी व्यवस्थित तरीके से दूर किया जा रहा है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम को कई अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ा गया है, ताकि संक्रमण की रोकथाम की जा सके और संक्रमित लोगों को मुफ्त जांच, दवाएं और इलाज की सुविधा मिल सके।

साल 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लोगों की जांच और इलाज की सुविधा दी जाती है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

बयान में कहा गया है, 'राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संक्रमण की रोकथाम, लोगों में जागरूकता बढ़ाने और बेहतर इलाज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने और जरूरतमंद सभी लोगों को वायरल हेपेटाइटिस की मुफ्त जांच और इलाज उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है। मरीजों के पंजीकरण, इलाज और निगरानी के लिए कागज रहित राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम प्रबंधन सूचना पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर तेजी से फैलने वाले संक्रमण हैं, जिनमें लोगों में जल्दी लक्षण दिखाई देते हैं और कई बार इनके प्रकोप भी देखने को मिलते हैं। इनकी निगरानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत की जाती है।

हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से संक्रमित जरूरतमंद सभी लोगों को मुफ्त जांच, दवाएं और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने वर्ष 2021 के एचआईवी निगरानी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जांच में शामिल लोगों में लगभग 0.85 प्रतिशत लोग हेपेटाइटिस बी और 0.29 प्रतिशत लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित पाए गए। यानी औसतन हर 118 लोगों में एक व्यक्ति हेपेटाइटिस बी और हर 345 लोगों में एक व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से संक्रमित था।

सरकार प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी की जांच कराने की व्यवस्था भी कर रही है। सभी नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज़ और पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन (एचबीआईजी) मिलना पक्का करने के लिए सरकार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ-साथ जन्म के 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज देने में मदद करती है।

इस कार्यक्रम के लिए 1800-11-6666 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है, जिसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के साथ साझा किया गया है। इस नंबर पर लोग संक्रमण, उससे बचाव, उसके फैलने के तरीके, इलाज और देशभर में इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध जांच एवं उपचार केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एनवीडिया, ओपनएआई के मेगा डेटा सेंटर के लिए 250 अरब डॉलर की वित्तीय गारंटी देने पर कर रही बातचीत : रिपोर्ट

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया, यूएस में बनने वाले ओपनएआई के विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए करीब 250 अरब डॉलर की वित्तीय गारंटी उपलब्ध कराने पर बातचीत कर रही है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित वित्तीय समर्थन से चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई को दक्षिणी ओहायो में सॉफ्टबैंक की ऊर्जा इकाई द्वारा विकसित किए जा रहे 10 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर परिसर को लीज पर लेने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परियोजना की कुल लागत 500 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है, जिसमें इस डेटा सेंटर को संचालित करने वाले एनवीडिया के एआई चिप्स की लागत भी शामिल है।

प्रस्तावित 250 अरब डॉलर की गारंटी डेटा सेंटर की लीज और डेट फाइनेंसिंग को कवर करेगी, लेकिन इसमें चिप्स की लागत शामिल नहीं होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया ओपनएआई द्वारा 350 अरब डॉलर तक के एआई चिप्स की खरीद के लिए फाइनेंसिंग पर भी चर्चा कर रही है।

ओपनएआई के लिए यह समझौता अपनी खुद का एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और ओरेकल जैसे क्लाउड सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता कम कर सकेगी। वहीं, एनवीडिया के लिए यह व्यवस्था उसके एआई चिप्स की दीर्घकालिक मांग सुनिश्चित करने में मददगार होगी। इन चिप्स का उपयोग उन्नत एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और संचालित करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वित्तीय सहायता उन निवेश ढांचों को भी मजबूत करेगी, जिनका उद्देश्य इस परियोजना के फंडिंग को लेकर ऋणदाताओं का भरोसा बढ़ाना है।

ओहायो में बनने वाली इस परियोजना का पहला चरण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 800 मेगावाट बिजली क्षमता उपलब्ध होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस परियोजना के लिए बिजली आपूर्ति का नियंत्रण अमेरिकी सरकार के पास होगा और इसकी फंडिंग जापान करेगा। यह हाल ही में हुए व्यापार समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत टोक्यो ने 33 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस संयंत्र में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया के बड़े औद्योगिक समूहों और एनवीडिया सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों ने करीब 950 अरब डॉलर मूल्य की कई सहयोगी परियोजनाओं की संभावनाओं पर सहमति जताई थी। यह जानकारी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई थी।

बरसात में रहना है सेहतमंद? तो रोजमर्रा की इन छोटी आदतों से करें संक्रमण का बचाव

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के साथ-साथ मानसून अपने साथ प्रकृति की हरी-भरी सुंदरता भी लेकर आता है लेकिन इसके आगमन से कई तरह के मौसमी संक्रमण और बीमारियां भी पनपती हैं। उमस और नमी के दौर में सतर्कता और स्वच्छता सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनता है।

रोजमर्रा की जिंदगी में अगर व्यक्ति छोटी-मोटी और आसान आदतों का ध्यान दे, तो वह न सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है बल्कि पूरे मानसून में खुद ऊर्जावान और स्वस्थ भी बना रह सकता है।

इसी को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने मानसून में कुछ सावधानियों पर जोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'स्वस्थ मानसून (बरसात) की शुरुआत अच्छी स्वच्छता की आदतों से होती है। रोजमर्रा की छोटी-छोटी सावधानियां आपको मौसम में होने वाले संक्रमणों से बचाने और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में बड़ी मदद कर सकती हैं।

आयुष मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में सबसे पहले उन्होंने नियमित रूप से हाथ धोने पर जोर दिया है। उनके अनुसार, नियमित रूप से हाथ धोना काफी नहीं है बल्कि सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। इसके लिए 'सुमन-के' तरीके से हाथ धोने के लिए बताया जाता है, जिसमें एस (सीधा), यू (उल्टा), एम (मुट्ठी), ए (अंगूठा), एन (नाखून) और के (कलाई) के छह चरण शामिल होते हैं। यह विधि हाथों को पूरी तरह साफ करके कीटाणुओं और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़े तुरंत बदल लेने चाहिए ताकि त्वचा पर नमी न बढ़े। ऐसा करने से स्किन पर खुजली, रैशेज और फंगल इंफेक्शन से बचा जा सकता है। इसलिए बरसात में कोशिश करें कि न भीगें और अगर ऐसा हो भी गया, तो फौरन कपड़े बदल लें। बारिश के मौसम में रोजाना पैरों को साफ और सूखे मोजे पहनने की कोशिश करें। क्योंकि लंबे समय तक गीले जूते या मोजे पहनने से फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

अपने आसपास की जगह को साफ रखें और बारिश के मौसम में पानी जमा न होने दें। ऐसा करने से घर में मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। वहीं, कमरों में पर्याप्त हवा का आवागमन बनाए रखें। अगर बारिश के मौसम में किसी भी तरह के स्किन इंफेक्शन, उल्टी और तेज बुखार जैसी शारीरिक समस्या हो, तो एक बार डॉक्टर की सलाह लें। खुद दवा लेने की गलती बिल्कुल भी न करें।

बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप जारी: अब तक 825 बच्चों की मौत, आखिर कहां हुई चूक?

विश्व केसरी ■

ढाका। खसरा पिछले तीन महीनों से बांग्लादेश के लिए आफत का सबब बना हुआ है। खसरे जैसे लक्षणों वाली बीमारी से सोमवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में पांच और बच्चों की मौत हो गई, और इस तरह मृतकों की कुल संख्या 825 तक पहुंच गई। स्थानीय मीडिया आंकड़ों के आधार पर खसरे की रोकथाम को लेकर अपनाए ढुलमुल रवैए को इसके फैलने का कारण मान रहा है।

बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी यूएनबी ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के हवाले से बताया कि हाल में हुई सभी मौत संदिग्ध खसरा वर्ग में आती हैं।

ताजा अपडेट के बाद कथित खसरे से मौत की संख्या बढ़कर 730 हो गई है, जबकि लैब कन्फर्म खसरे की वजह से मौत का आंकड़ा 95 है और ये पिछले कुछ दिनों से स्थिर बना हुआ है।

पिछले 24 घंटों में खसरे के 992 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देशभर में संदिग्ध मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,24,745 हो गई है। इस दौरान 113 नए मामले भी दर्ज किए गए, जिससे लैब टेस्ट से कन्फर्म मामलों की संख्या बढ़कर 15,555 हो गई।

डीजीएचएस के आंकड़ों के अनुसार, 15 मार्च से अब तक देशभर में खसरे के संदिग्ध लक्षणों वाले 1,07,654 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 1,03,467 मरीज ठीक हो चुके हैं।

ढाका ट्रिब्यून ने इस मुद्दे को काफी संवेदनशील बताया और विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता वाला डेटा किसी भी प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की नींव होता है। यह जानकारी को ऐसी रणनीतियों में बदलने में मदद करता है, जिन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। टीकाकरण कवरेज, मौसमी बदलाव और संक्रमण के पुराने पैटर्न से जुड़े सांख्यिकीय मॉडल के जरिए ज्यादातर खसरा प्रकोप का पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है। बांग्लादेश कभी भी खसरा-युक्त टीके की पहली और दूसरी दोनों खुराकों के लिए 95 प्रतिशत कवरेज हासिल नहीं कर सका। यह वह स्तर है, जिसे खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए जरूरी माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2025 में खसरा टीकाकरण कवरेज घटकर करीब 57 प्रतिशत रह गया।

सरकार के प्रशासनिक आंकड़ों में हमेशा टीकाकरण कवरेज 100 प्रतिशत से अधिक दिखाया गया, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार, बांग्लादेश में खसरा टीकाकरण कवरेज 2010 से लगातार 93 से 96 प्रतिशत के बीच रहा।रिपोर्ट के अनुसार, 'इन आंकड़ों में अंतर पहले से ही एक चेतावनी संकेत था, लेकिन हम समय रहते इसे पहचानने और संभावित संकट का अनुमान लगाने में विफल रहे।

छोटी-छोटी सावधानियां बरत कर मौसमी इंफेक्शन से बचें, पैरों को साफ और सूखा रखना चाहिए

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। बरसात के मौसम में केवल गर्मी से ही राहत नहीं मिलती, बल्कि मौसमी इंफेक्शन का भी खतरा रहता है। छोटी-छोटी सावधानियां बरतने से मौसमी इंफेक्शन से बचा जा सकता है, जिससे सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है और बीमारियां नहीं होती हैं।

मौसमी इंफेक्शन से बचने के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की गई है। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि एक हेल्दी मानसून की शुरुआत साफ-सफाई की आसान आदतों से होती है। रोजाना की छोटी-छोटी सावधानियां मौसमी इंफेक्शन से बचाने और पूरी सेहत को बनाए रखने में बहुत मदद कर सकती हैं। आयुष मंत्रालय ने मौसमी इंफेक्शन से बचने के लिए हाइजीन चेकलिस्ट जारी की है। बताया गया है कि बरसात के मौसम में हाथ को नियमित तौर पर साबुन और पानी से धोना चाहिए। गीले कपड़े को तुरंत बदले चाहिए। अपने पैर साफ और सूखा रखना चाहिए। पानी जमा होने से रोकने के लिए अपने आसपास साफ-सफाई रखनी चाहिए और मच्छरों को कम करने के लिए कचरे को ठीक से फेंकना चाहिए। अगर इन छोटी-छोटी सावधानियों को बरता जाता है तो मौसमी इंफेक्शन से बचा जा सकता है।

आयुष मंत्रालय ने बीते दिन खांसी के आम लक्षणों को पहचानने और आयुष पर आधारित आसान सेल्फ-केयर उपायों के बारे में जानकारी दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर आयुष मंत्रालय ने लिखा था, 'लक्षणों से लेकर सेहत तक, बेहतर सांस की सेहत की ओर पहला कदम उठाएं। खांसी के आम लक्षणों को पहचानें और आयुष पर आधारित आसान सेल्फ-केयर उपायों के बारे में जानें जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के हिस्से के तौर पर आराम और रिकवरी में मदद कर सकते हैं।

सूखी खांसी के लिए आयुष मंत्रालय ने बताया था कि मुलेठी (लिकोरिस) या लौंग का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखना चाहिए।

चेहरे की चमक से लेकर बालों की मजबूती तक, बादाम का तेल है कुदरती ब्यूटी टॉनिक

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। आजकल बढ़ता प्रदूषण, धूल-मिट्टी, खराब खानपान और तनाव का असर सबसे पहले हमारी त्वचा और बालों पर दिखाई देता है। कम उम्र में ही बाल झड़ने लगते हैं और त्वचा अपनी प्राकृतिक चमक खोने लगती है। ऐसे में लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा फायदा मिल सकता है। इन्हीं में से एक है बादाम का तेल। बादाम के तेल में ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा और बालों दोनों की देखभाल में मदद कर सकते हैं।

बादाम के तेल में विटामिन ई, हेल्दी फैट, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह त्वचा की नमी बनाए रखने, बालों को मुलायम बनाने और बाहरी नुकसान से बचाने में मदद करता है। बादाम के तेल से हल्के हाथों से सिर की मालिश करने से बालों को नमी मिलती है और वे पहले से ज्यादा मुलायम महसूस होते हैं। कुछ लोग बादाम के तेल को जैतून के तेल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। इससे बालों की देखभाल बेहतर तरीके से होती है। हालांकि अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हों, तो पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक, बादाम के तेल में ऐसे फैटी एसिड होते हैं, जो बालों की बाहरी परत को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इससे बालों का रूखापन कम होता है और बालों के टूटने की संभावना भी कुछ हद तक कम हो जाती है। आंखों के नीचे होने वाले काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स की समस्या भी आजकल काफी आम हो गई है। देर रात तक जागना, तनाव, नींद की कमी और शरीर में पानी की कमी इसके बड़े कारण माने जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रात में सोने से पहले आंखों के नीचे थोड़ी मात्रा में बादाम के तेल से हल्की मालिश करने से त्वचा को नमी मिलती है। हालांकि मेडिकल रिसर्च कहती है कि डार्क सर्कल्स का पूरा इलाज सिर्फ किसी एक तेल से संभव नहीं है। इसके लिए अच्छी नींद, पर्याप्त पानी और संतुलित जीवनशैली भी उतनी ही जरूरी है।

बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कई लोगों में यह बदलाव जल्दी दिखाई देने लगता है।

सीडब्ल्यूजी 2026: पहले ही प्रयास में 8.01 मीटर की जंप

श्रीशंकर मुरली ने हासिल किया फाइनल का टिकट

एजेंसी ■ ग्लासगो

भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार शुरुआत की है। उन्होंने सोमवार को पुरुषों की लॉन्ग जंप के क्वालिफिकेशन राउंड में 8.01 मीटर की छलांग लगाकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। श्रीशंकर ने ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन मार्क को आसानी से पार कर लिया।

क्वालीफाइंग 'ग्रुप-ए' में 27 वर्षीय एथलीट को फाइनल में सीधा प्रवेश पाने के लिए कम से कम 8.00 मीटर की छलांग लगाने की जरूरत थी। श्रीशंकर ने यह लक्ष्य केवल एक प्रयास में हासिल कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन राउंड समाप्त कर दिया और बुधवार को होने वाले मेडल इवेंट के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखी।

केरल के इस एथलीट ने अपने पहले प्रयास से ही 'ग्रुप-ए' में शीर्ष स्थान हासिल किया। वे जमैका के जॉर्डन टर्नर से आगे रहे, जिनकी सर्वश्रेष्ठ छलांग 7.80 मीटर थी। अगर श्रीशंकर क्वालिफिकेशन मानक तक नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए दोनों क्वालिफिकेशन ग्रुप के 12 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शामिल होना पड़ता।

इसके बजाय, भारतीय एथलीट ने शुरुआत से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और अपनी पहली छलांग से ही जरूरी मार्क को आसानी से पार करके किसी भी तरह की अनिश्चितता को दूर कर दिया।

चोट से उबरकर इस सीजन में शानदार फॉर्म में वापसी करने वाले श्रीशंकर, भारत के लिए एथलेटिक्स में मेडल जीतने की सबसे मजबूत उम्मीदों में से एक के तौर पर ग्लासगो पहुंचे हैं। उनके नाम इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (8.38 मीटर) दर्ज है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में श्रीशंकर ने क्वालिफिकेशन राउंड में दबदबा बनाया था और सभी प्रतिस्पर्धियों में सर्वश्रेष्ठ छलांग (8.05 मीटर) लगाई थी, लेकिन फाइनल में मामूली अंतर से गोल्ड मेडल से चूक गए थे। उन्होंने 8.08 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई थी, जो बहामास के लाक्वान नायरन के बराबर थी। नायरन ने अपनी दूसरी सर्वश्रेष्ठ छलांग बेहतर होने के कारण 'काउंटबैक नियम' के तहत गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब श्रीशंकर 29 जुलाई को फाइनल खेलेंगे, जिसमें उनके पास चार साल पहले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए सिल्वर मेडल का रंग बदलने को मौका है।

सीडब्ल्यूजी 2026 : सचिन सिवाच ने विलियम हेविट को हराया, पुरुषों के 60 किलोग्राम बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

विश्व केसरी ■ ग्लासगो

भारतीय बॉक्सर सचिन सिवाच 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2026' में पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सचिन ने सोमवार को 'राउंड ऑफ 16' में इंग्लैंड के विलियम हेविट को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से शिकस्त दी।

बेहतरीन रिंग क्राफ्ट, तेज कॉम्बिनेशन और रणनीतिक अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए, सचिन ने तीन राउंड के मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और घरेलू खिलाड़ी पर शानदार जीत हासिल की। कजाकिस्तान, कनाडा, मैक्सिको और मोरक्को के जजों ने मुकाबले का स्कोर भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 29-27 दिया, जबकि तुर्की के जज ने हेविट को 29-27 अंक दिए। मुकाबले के दौरान सचिन का एक अंक काटा गया, लेकिन इससे अंतिम नतीजे पर कोई खास असर नहीं पड़ा और वे आसानी से विजेता बने।

सचिन ने लगातार सटीक पंच मारे और पूरे मुकाबले के दौरान अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने अपने आक्रामक लेकिन संयमित अंदाज से हेविट पर दबाव बनाए रखा। मुकाबले की गति तय करने और प्रभावी ढंग से स्कोर करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अंतिम-8 में पहुंचाया।

इस जीत के साथ, सचिन ने पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदों को जिंदा रखा और ग्लासगो गेम्स में पोडियम की ओर एक कदम और आगे बढ़े। भारतीय बॉक्सर को अब क्वार्टर फाइनल में और भी कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि वे अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखने और मेडल राउंड में जगह बनाने की कोशिश करेंगे।

राउंड ऑफ 16जीतने के बाद सचिन सिवाच ने 'आईएएनएस' से कहा, 'यह मुकाबला बहुत मुश्किल था और सब कुछ इसलिए अच्छा रहा क्योंकि मैंने निर्देशों का पालन किया। अपने कोच की बात सुनने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि गोल्ड मेडल जीतकर ही लौटूंगा। हमने पहले से ही यह तैयारी कर रखी थी कि किस बॉक्सर के खिलाफ हमें कैसा खेलना है।

ईटीपीएल में ग्लासगो कॉस्मिक के लक्ष्यों पर वरुण आरोन बोले- 'हमारा मकसद एक छाप छोड़ना है'

विश्व केसरी ■ नई दिल्ली

यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) के पहले सीजन की शुरुआत 26 अगस्त से होगी। ग्लासगो कॉस्मिक के बॉलिंग कोच वरुण आरोन का कहना है कि फ्रेंचाइजी दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है, जिसका मकसद ग्लासगो और पूरे यूरोप में इस खेल की एक छाप छोड़ना है।

आरोन ने 'आईएएनएस' के साथ एक खास बातचीत में कहा, 'मुझे लगता है कि जब आप किसी टीम से जुड़ते हैं, तो उनका एक मजबूत विश्वास होता है कि वे स्थानीय माहौल पर असर डालेंगे, उसे बेहतर बनाने में योगदान देंगे और उस क्षेत्र के टैलेंट को निखारने में मदद करेंगे। मैं ऐसी चीजों से जुड़ना पसंद करता हूं। 'एक तरफ आप सुपरस्टार्स को लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो अनजान है या जिसने अभी तक बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन आप उसमें कुछ क्षमता देखते हैं और उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाते हैं। ग्लासगो कॉस्मिक इन मूल्यों को पूरी तरह से अपनाती है क्योंकि पहला मैच शुरू होने से लगभग 10 दिन पहले ही हम ग्लासगो में स्थानीय समुदाय के साथ काम करने, वहां की कुछ एकेडमी से जुड़ने और इस नई फ्रेंचाइजी की एक छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं - क्योंकि यह पहली बार हो रहा है? यह सब यूरोप में हो रहा है और स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा नीदरलैंड्स में लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ लीग जीतने पर ही नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि इस पूरे खेल तंत्र में निरंतर विकास और मजबूती सुनिश्चित की जाए।

मैदान पर, ग्लासगो की सफलता पिच और हालात को सही ढंग से समझने पर निर्भर करती है।

वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश टीम कॉम्पिटिशन में भारतीय पुरुष प्री-क्वार्टर में पहुंचे, महिला टीम की जीत के साथ शुरुआत

विश्व केसरी ■ ओंटारियो

भारत ने वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि महिला टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में प्रभावशाली जीत दर्ज की। पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम, जिसमें गुरवीर सिंह, युशा नफीस और आर्यवीर दीवान शामिल हैं, ने ग्रुप-5 के पहले मुकाबले में नीदरलैंड को 3-0 से हराया। इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने फ्रीक बोनेमा, जेस्पर हेम्पेनियस और क्विंटन वैन एस की चुनौती को आसानी से पार कर लिया।

इसके बाद ब्राजील के खिलाफ मुकाबले में गुरवीर सिंह की जगह पूरव रांभिया को टीम में शामिल किया गया। पूरव, युशा और आर्यवीर की तिकड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए ब्राजील के बर्नार्डो जॉर्ज गुइमारेस, मैथियस फ्राबेटी और विगो हेंड्रिक्स को भी 3-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। महिला वर्ग में भी पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय टीम ने जीत से शुरुआत की। सान्वी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह की टीम ने चीनी ताइपे को 3-0 से मात दी। अब भारत का अगला मुकाबला ग्रुप-4 में मलेशिया से होगा।

महिला टीम की स्टार खिलाड़ी अनाहत सिंह, जिन्होंने एक दिन पहले विश्व जूनियर व्यक्तिगत खिताब जीता था, को शुरुआती मुकाबले में आराम दिया गया। टूर्नामेंट में अन्य प्रमुख टीमों ने भी दमदार शुरुआत की। मेजबान कनाडा की महिला टीम ने अपने पहले मैच में नाइजीरिया को सीधे गेम में हराया, जबकि जापान की पुरुष टीम ने कनाडा को मात दी। दूसरी ओर, गत चैंपियन मिस्र ने भी अपने खिताब बचाने के अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए महिला वर्ग में ब्राजील और पुरुष वर्ग में नीदरलैंड तथा न्यूजीलैंड को हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की।

एशियन गेम्स 2026 : भारतीय दल में गुजरात से रिकॉर्ड 9 एथलीट शामिल होंगे

विश्व केसरी ■गांधीनगर

जापान के ऐची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए जाने वाले भारतीय दल में गुजरात से रिकॉर्ड 9 एथलीट शामिल होंगे। 9 एथलीटों के अलावा एक रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल है।

एशियन गेम्स 2014 में भारतीय दल में गुजरात के 3 एथलीट शामिल थे। ऐसे में आगामी एशियन गेम्स में तीन गुणा ज्यादा एथलीट राज्य से शामिल हो रहे हैं। राज्य के अधिकारियों ने कहा कि यह नया दल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के कई वर्ग में गुजरात की मौजूदगी के विस्तार को दिखाता है।

गुजरात से चुने गए एथलीटों में शूटर एलावेनिल वालारिवन, टेबल टेनिस खिलाड़ी हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, और मानुष शाह, सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी अनिकेत पटेल, तैराक आर्यन नेहरा, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना और वैदेही चौधरी, और स्प्रिंटर (धावक) देवयानी जाला शामिल हैं। टेनिस खिलाड़ी जिल देसाई को रिजर्व के तौर पर चुना गया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रतिनिधित्व में वृद्धि खेल विकास में लंबे समय के निवेश का नतीजा है। उन्होंने कहा, 'यह पक्का करने के लिए कि गुजरात के एथलीट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा विकसित करें। नरेंद्र मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने खेल महाकुंभ से लेकर शक्तिदूत योजना जैसी कई पहल की थी। उन कोशिशों के नतीजे अब दिख रहे हैं। गुजरात खेल के क्षेत्र में एक वैश्विक पावरहाउस के तौर पर उभर रहा है। संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार एक बड़ा खेल इकोसिस्टम बनाने पर फोकस कर रही है। हम न सिर्फ एथलीट को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने में सक्षम बनाए।

सीडब्ल्यूजी 2026: वेटलिफ्टर बिंद्यारानी देवी ने 58 किग्रा वर्ग में जीता ब्रॉन्ज, भारत के नाम छठा मेडल

विश्व केसरी ■ नई दिल्ली

महिला वेटलिफ्टर बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम ने सोमवार को भारत के लिए 58 किग्रा भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी के साथ भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना छठा पदक हासिल कर लिया है।

नाइजीरिया की रफियातू फोलाशादे लावाल ने कुल 229 किग्रा (103 स्नैच और 126 क्लीन एंड जर्क) उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कनाडा की एन सोफी ताशेरो ने कुल 215 किग्रा (94 स्नैच और 121 क्लीन एंड जर्क) के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। बिंद्यारानी देवी कुल 199 किग्रा के साथ तीसरे स्थान पर रहीं, जिन्होंने स्नैच में 87 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 112 किग्रा भार उठाया।

एसईसी आर्माडिलो में भारत की स्टार वेटलिफ्टर बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम ने स्नैच राउंड में 87 किलोग्राम वजन उठाकर संयुक्त रूप से तीसरा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। बिंद्यारानी ने अपने पहले प्रयास में 83 किग्रा, दूसरे में 85 किग्रा और तीसरे प्रयास में 87 किग्रा सफलतापूर्वक उठाया।

स्नैच राउंड में इंग्लैंड की एलिजा प्रैट ने भी 87 किग्रा वजन उठाया, जबकि भारत की बिंद्यारानी समान वजन उठाने के बावजूद प्रयासों के क्रम (काउंटबैक) के आधार पर उनके पीछे रहीं। नाइजीरिया की रफियातू फोलाशादे लावाल ने स्नैच में 103 किग्रा वजन उठाकर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड और गेम्स रिकॉर्ड अपने नाम किया। कनाडा की एन सोफी ताशेरो 94 किग्रा के साथ दूसरे पायदान पर रहीं। 'क्लीन एंड जर्क' राउंड में रफियातू फोलाशादे लावाल ने 117 किग्रा, 122 किग्रा और 126 किग्रा के तीन सफल प्रयास किए। वहीं, एन सोफी ताशेरो 111 किग्रा, 115 किग्रा और 121 किग्रा के तीनों प्रयास में सफल रहीं। भारत की बिंद्यारानी देवी 110 किग्रा के पहले प्रयास में नाकाम रहीं, जिसके बाद उन्होंने अगले प्रयास में 112 किग्रा वजन उठाया। तीसरे प्रयास में उन्होंने 4 किग्रा वजन बढ़ाया, लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकीं। इसी के साथ भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में छठा पदक हासिल किया। पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ देश के लिए खाता खोला था, जिसके बाद ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की वेटलिफ्टिंग (60 किग्रा) प्रतियोगिता में भारत को सिल्वर जिताया। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 48 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड जीता।

कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत जीतने वाले राजा मुथुपंडी को तमिलनाडु सरकार का तोहफा

सीएम विजय ने 30 लाख के नकद इनाम का किया ऐलान

विश्व केसरी■ चेन्नई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 65 किग्रा में रजत पदक जीतने वाले वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी के लिए 30 लाख रुपये के नगद इनाम की घोषणा की है।

एथलीट को उनकी कामयाबी पर बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इनाम उनके शानदार प्रदर्शन के लिए है। सीएम ने भरोसा जताया कि उनकी कामयाबी राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।

विजय ने कहा, 'मैं ग्लासगो में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए राजा मुथुपंडी को दिल से बधाई देता हूं। उनकी सफलता तमिलनाडु के लिए बहुत गर्व की बात है। उनकी यह उपलब्धि हमारे युवाओं को प्रेरणा दे। मैं उन्हें और भी कई जीत की शुभकामनाएं देता हूं जो तमिलनाडु और देश दोनों के लिए सम्मान लाएंगी। मुख्यमंत्री विजय ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए युवा वेटलिफ्टर को दिल से बधाई दी। उन्होंने मुथुपंडी के परफॉर्मेंस को एक रिकॉर्ड बनाने वाली कामयाबी बताया और कहा कि उन्हें राज्य के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इंसेंटिव में से एक से सम्मानित किया जाएगा।

राजा को उनकी सफलता पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है।

राजा ने कुल 286 किग्रा (126 किग्रा+160 किग्रा) के साथ खत्म किया। राजा ने 125 किग्रा के सफल स्नैच से शुरुआत की और फिर अपनी दूसरी कोशिश में 126 किग्रा तक सुधार किया। वह अपनी आखिरी लिफ्ट में 129 किग्रा क्लियर नहीं कर पाए। क्लीन एंड जर्क में, उन्होंने 158 किग्रा और 160 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश में 170 किग्रा पर फेल हो गए और दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक जीता।

स्वात्वधिकारी राइवल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुजीत कुमार द्वारा साई प्रीटिंग प्रेस, डी-85, सेक्टर 6 नोएडा,गौतम बुध्द नगर पिन कोड -201301 उ.प्र. से मुद्रित और मकान संख्या एन-58 जगतराम पार्क के सामने, लक्ष्मी नगर पूर्व दिल्ली-110053 से प्रकाशित
समाचार संपादक : चन्द्रमणी साव (पीआरबी एक्ट के अनुसार समाचार पत्र चयन एवं संपादन के लिए उत्तरदायी। नोट किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा) मोबाइल 9340573892 ई-मेलः vishwakesari2026@gmail.com,आर.एन.आई.नं. DLHIN/2015/61415